राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 7 अंक 268

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, बुधवार, 6 मार्च, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकेंगे ट्रंप, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया प्रतिबंध

>> 11

जागरण विशेष

नवाचारी अधिकारी

बस्तर की 'छवि' तोड़कर पर्यटन को दी नई दिशा

जगदलपुर : बस्तर का नाम सुनते ही नक्सल आतंक की छवि मन में उभर आती है। आइएफएस अधिकारी धम्मशील के प्रयासों के चलते पर्यटक अब यहां के अप्रतिम सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं। ● पेज-7

संपादकीय

कांग्रेस के पराभव का कारण: अपेक्षाकृत कम योग्य उत्तराधिकारियों के कारण ही कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल संकट में हैं। कुछ तो डूब रहे हैं। **सुरेंद्र किशोर** का आलेख।

गरीबी घटाने से आगे की चुनौती: यह अच्छी बात है कि देश में गरीबी कम हो रही है, लेकिन प्रयास यह होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े। **डा. जयंतीलाल भंडारी** का दृष्टिकोण। ● पेज-8

विमर्श

सेमीकंडक्टर का हब बनने की डगर पर : पिछले दिनों केंद्र सरकार ने दो सेमीकंडक्टर यूनिट गुजरात में तथा एक असम में लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सेमीकंडक्टर के घरेलू निर्माण से देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। अभिषेक कुमार सिंह का विश्लेषण।

नए भारत का विकासवादी चरित्र : गुलामी की मानसिकता से आज देश का अर्थतंत्र बाहर आया है तो इसका कारण बीते एक दशक में भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपरा को केंद्र में रखकर किए गए विकास कार्य हैं। प्रेम प्रकाश का आकलन। ● पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग

सेहत भरे जीवन का

संपूर्ण सेहत की हो बात

काला मोतिया की आशंका से कैसे बचें

● पेज-13

लश्कर माड्यूल का पर्दाफाश, कैदियों को आत्मघाती हमलावर बनाने की थी साजिश

बेंगलुरु की जेल में लश्कर के लिए भर्ती की जांच के दौरान माड्यूल की मिली जानकारी

नीलू रंजन, नई दिल्ली

- कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात व बंगाल समेत सात राज्यों में की गई छापेमारी
- बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण, दस्तावेजी सुबूत और देशी-विदेशी मुद्रा बरामद

लश्कर-ए-तैयबा के बड़े माड्यूल का पर्दाफाश करते हुए एनआइए ने कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात और बंगाल समेत सात राज्यों में छापा मारा है। इस माड्यूल का पर्दाफाश बेंगलुरु जेल के भीतर लश्कर के लिए भर्ती की साजिश की जांच के सिलसिले में हुआ। एनआइए का कहना है कि आरोपितों ने बेंगलुरु जेल में बंद कैदियों को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आत्मघाती हमले के लिए तैयार करने की साजिश रची थी। गत वर्ष जुलाई में बेंगलुरु के एक ठिकाने से सात पिस्तौल, चार हैंडग्रेनेड, 45 गोलियों के साथ एक मैगजीन और चार वाकी-टाकी की बरामदगी के बाद लश्कर की साजिश का पता चला था। बेंगलुरु पुलिस की शुरुआती एफआइआर के बाद एनआइए ने केस की जांच अपने हाथ में ली थी।

एनआइए के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जेल के भीतर आतंकी भर्ती की जांच पूरी हो चुकी है। 12 जनवरी को आठ आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। इनमें दो आरोपितों जुनैद अहमद और सलमान खान को भगोड़ा घोषित किया गया है। अधिकारी ने बताया कि केस की जांच के दौरान कई राज्यों में फैले लश्कर के नेटवर्क की जानकारी मिली, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल थे और इसके लिए ट्रेनिंग और फंडिंग तक उपलब्ध करा रहे थे। जांच के दौरान ऐसे 12 संदिग्धों की पहचान की गई, जो इस नेटवर्क में शामिल थे। मंगलवार को इन सभी के ठिकानों की सघन तलाशी ली गई। एनआइए के अनुसार, तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण, दस्तावेजी साक्ष्य और देशी व विदेशी मुद्रा में नकद बरामद किए गए। इनमें 25 मोबाइल फोन, छह लैपटाप और चार स्टोरेज उपकरण शामिल हैं।

जिन संदिग्धों के ठिकानों पर छापे मारे गए, उनमें कर्नाटक में मेंगलुरु के नवीद, बेंगलुरु के सैयद खैल व दक्षिण कर्नाटक के बिज्जु के साथ ही बंगाल के 24 परगना जिले के मयूर चक्रवर्ती, पंजाब के गुरदासपुर के नवजोत सिंह, गुजरात के मेहसाणा के हार्दिक कुमार व अहमदाबाद के करन कुमार, तमिलनाडु के रामनाथपुरम के दो भाई अहमद सथिकली व मुबिथ और चेन्नई के हसन अल बस्सम शामिल हैं। इस पूरे माड्यूल के मास्टरमाइंड की पहचान की कोशिश की जा रही है।

बेंगलुरु की जेल में कट्टरपंथी बनाने के मामले में एनआइए ने मंगलवार को तमिलनाडु के रामनाथपुरम में छापेमारी की। एएनआइ

बम धमाके के कई मामलों का आरोपित है नसीर

एनआइए की चार्जशीट के अनुसार, केरल के कन्नूर का निवासी टी नसीर बम धमाके के कई मामलों का आरोपित है और बेंगलुरु की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। यहीं उसकी जुनैद अहमद उर्फ जेडी और सलमान खान से मुलाकात हुई। दोनों को उसने लश्कर का आतंकी बनने और आत्मघाती हमले के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद वह अन्य आरोपितों को जेल के अपने बैरक में शिफ्ट कराने में सफल रहा और उन्हें लश्कर का आतंकी बनने के लिए तैयार कर लिया। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आरोपितों ने आतंकी हमलों के लिए हथियार और फंड जुटाना शुरू कर दिया। एनआइए के वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार के छापे में मिले डिजिटल उपकरणों और अन्य दस्तावेज को अहम बताते हुए कहा कि इससे इनके नेटवर्क के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है। एनआइए आरोपितों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में जुट गई है।

राजस्थान में पेपर लीक से बने दारोगा, टापर समेत 14 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जयपुर

- राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में ट्रेनिंग ले रहे थे गिरफ्तार उप निरीक्षक
- कुल 16 गिरफ्तार लोगों में 14 पुलिस उप निरीक्षक, एक परीक्षा केंद्र का अधीक्षक व एक अन्य है शामिल

10 आरोपितों ने करीब 20 से 22 लाख रुपये में खरीदा था पर्चा, जांच जारी

- पुलिस के आने से पहले ही फरार हुए एक दर्जन प्रशिक्षु उप निरीक्षक

राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा- 2021 के पर्चे लीक और मूल परीक्षार्थी के स्थान पर डमी अभ्यर्थी को बिठाने के मामले में राजस्थान स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 14 वे लोग हैं, जिनका भर्ती परीक्षा में चयन हो गया और वे फिलहाल जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर (आरपीए) में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से दस ने 20 से 22 लाख रुपये में लीक हुआ पर्चा खरीदा था। चार लोग ऐसे हैं, जिनके स्थान पर डमी अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी और उनका चयन हो गया। गिरफ्तार किए गए प्रशिक्षुओं में उप निरीक्षकों की परीक्षा में टाप करने वाला नरेश खिलेरी भी शामिल है। एसओजी की टीम के आरपीए पहुंचने से पहले ही करीब एक दर्जन प्रशिक्षु उप निरीक्षक फरार हो गए।

एसओजी के अधिकारियों का मानना है कि करीब 30 प्रशिक्षु उप निरीक्षक लीक हुए पर्चे और डमी अभ्यर्थी के माध्यम से नौकरी पाने में सफल हुए हैं। एसओजी फरार हुए प्रशिक्षु उप निरीक्षकों के बारे में जानकारी जुटा रही है। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक वी. के. सिंह ने बताया कि पर्चा लीक जयपुर के हसनपुरा में संचालित होने वाली रवींद्र बाल भारतीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र से हुआ था। परीक्षा केंद्र के अधीक्षक राजेश खंडेलवाल को गिरफ्तार किया गया है। खंडेलवाल को जयपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। सिंह ने बताया कि जो 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें 14 प्रशिक्षु उप निरीक्षक, परीक्षा केंद्र के अधीक्षक राजेश खंडेलवाल एवं एक अन्य शामिल हैं। दो अन्य प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार को पूरी भर्ती परीक्षा ही निरस्त करने का सुझाव कुछ भाजपा नेताओं ने दिया है। हालांकि सरकार ने इस बारे में अभी कोई विचार नहीं किया है।

एडीजी ने की परीक्षा निरस्त कराने की अपील पेज>>6

सीबीआइ करेगी संदेशखाली कांड की जांच

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, ईडी अफसरों पर हुआ था हमला
- फैसले के विरुद्ध ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख
- सीआइडी ने सीबीआइ को नहीं सौंपा शाहजहां

संदेशखाली में पांच जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले सहित उससे जुड़े तीन मामलों की जांच सीबीआइ करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को यह निर्देश दिया। इधर, हाई कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में त्वरित सुनवाई याचिका दाखिल की गई, जिसे न्यायालय ने खारिज करते रजिस्ट्रार के पास जाने की सलाह दी। हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपित निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को सीबीआइ को सौंपने का भी निर्देश दिया था। लेकिन सीआइडी ने मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए शाहजहां को सीबीआइ को नहीं सौंपा। सीबीआइ के अधिकारी केंद्रीय बल के साथ शाहजहां को अपने अधिकार में लेने के लिए कोलकाता स्थित सीआइडी मुख्यालय पहुंचे थे। ढाई घंटे बाद वे वहां से खाली हाथ लौट गए। इधर, भाजपा ने अदालत द्वारा सीबीआइ जांच के फैसले का स्वागत किया है।

अदालत ने इसके साथ ही नजाट व बनगांव थाने में दर्ज संदेशखाली कांड से जुड़े तीन मामलों के सभी दस्तावेज भी पुलिस को तत्काल सीबीआइ को सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने ईडी अधिकारियों पर हमले की पड़ताल के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एसआइटी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मामले में राज्य पुलिस की भूमिका की कड़ी आलोचना की।

बता दें कि ईडी ने हाई कोर्ट में अपील की थी कि संदेशखाली घटना की जांच अकेले सीबीआइ को सौंप दी जाए। एजेंसी ने हाई कोर्ट को बताया था कि उसे राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है। क्योंकि इस मामले में राज्य पुलिस का रवैया शुरू से पक्षपातपूर्ण रहा है। शाहजहां के खिलाफ 40 मामले वर्षों से लंबित हैं, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया था। अधिकारियों पर हमले की घटना के बाद ईडी ने एफआइआर दर्ज कराई थी जिसके बाद शाहजहां को गिरफ्तार किया गया। दूसरी ओर राज्य ने कहा था कि पुलिस ने ठोस कदम उठाए हैं और कई आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

कोलकाता में मंगलवार को सीआइडी द्वारा संदेशखाली कांड आरोपित शेख शाहजहां को नहीं सौंपे जाने के बाद सीआइडी मुख्यालय से प्रस्थान करते सीबीआइ अधिकारी। प्रेट्र

ईडी ने कुर्क की शाहजहां की 12 करोड़ की संपत्ति

ईडी ने शाहजहां शेख की 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति मनी लांड्रिंग के तहत प्रावधानिक तौर पर कुर्क की है। इनमें कोलकाता, संदेशखाली व ग्राम सरबेरिया में स्थित अपार्टमेंट, कृषि भूमि, मत्स्य पालन केंद्र, भूमि व भवन जैसी 14 अचल संपत्ति शामिल हैं। शाहजहां के दो बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया है। जांच एजेंसी ने मंगलवार को एक्स पर इसकी जानकारी दी।

न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने दिया त्यागपत्र, भाजपा में होंगे शामिल

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट के जज पद से त्यागपत्र देने वाले अभिजीत गंगोपाध्याय भाजपा में शामिल होंगे। कोलकाता में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मैं सात मार्च को भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं। (पेज-5)

द्रमुक सांसद ए राजा बोले- भारत एक राष्ट्र नहीं

- कहा - एक देश का मतलब एक भाषा, एक परंपरा और एक संस्कृति
- यहां अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रथाएं, परंपराएं और संस्कृतियां
- कांग्रेस ने भी राजा की टिप्पणी की निंदा की, कहा-संयम बरतना चाहिए

द्रमुक सांसद ए राजा। फाइल

चेन्नई, प्रेट्र : सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके द्रमुक सांसद ए राजा ने फिर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है और न ही कभी एक राष्ट्र रहा है, बल्कि यह एक उपमहाद्वीप है और यहां विभिन्न प्रथाएं और परंपराएं हैं। उनकी इस टिप्पणी की न केवल भाजपा बल्कि द्रमुक की सहयोगी कांग्रेस ने भी निंदा की है। भाजपा ने द्रमुक नेता की टिप्पणी को देश विभाजन का आह्वान बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है तो कांग्रेस ने भी कहा है कि बोलते समय उन्हें संयम बरतना चाहिए।

राजा एक वीडियो में पार्टी की बैठक में कहते हैं- 'भारत एक राष्ट्र नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लें। भारत कभी एक राष्ट्र नहीं रहा। एक राष्ट्र एक भाषा, एक परंपरा और एक संस्कृति को दर्शाता है और ऐसी विशेषताएं ही एक राष्ट्र का निर्माण करती हैं।' राजा ने कहा, 'यहां तमिल एक राष्ट्र है। मलयालम एक भाषा, एक राष्ट्र है। उड़िया एक भाषा और एक राष्ट्र है। ऐसी सभी श्रेणियां मिलकर भारत का निर्माण करती हैं। ऐसे में भारत एक देश नहीं है, बल्कि यह एक उपमहाद्वीप है और इसमें विभिन्न प्रथाएं, परंपराएं और संस्कृतियां हैं।' उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, केरल, दिल्ली और ओडिशा जैसे राज्यों में अपनी-अपनी स्थानीय संस्कृति है।

उन्होंने कहा-'मणिपुर में कुत्ते का मांस खाया जाता है जो एक सांस्कृतिक पहलू है। कश्मीर में अलग संस्कृति है। हर संस्कृति को मान्यता देनी होगी। अगर कोई समुदाय बीफ खाता है तो उसे मानिए, आपको क्या समस्या है? क्या उन्होंने आपसे इसे खाने के लिए कहा? यही विविधता में एकता है। हमारे बीच अंतर है और इसे स्वीकार करना होगा।' राजा ने कहा कि अगर 'जय श्री राम' और 'भारत माता की जय' के नारे का मतलब कट्टरवाद है तो हम जय श्री राम और भारत माता की जय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तमिलनाडु इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि यदि उन्हें और उनकी पार्टी को भगवार राम का दुश्मन करार दिया जाता है तो भी उन्हें कोई चिंता नहीं है। उधर, कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि वह इससे पूरी तरह असहमत है। पार्टी की इंटरनेट मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि नेताओं को संयमित होकर बात करनी चाहिए। राजा के रामायण और भगवान राम के बारे में कुछ टिप्पणियां करने पर उन्होंने कहा- 'मेरा मानना है कि राम सबके हैं, राम हम सबमें हैं। जिस राम को इमाम-ए-हिंद कहा गया है, वो संप्रदायों, धर्म और जाति से ऊपर हैं। राम जीवन जीने का आदर्श हैं, राम मर्यादा हैं, राम नैतिकता हैं, राम प्रेम हैं।' वहीं, शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि राजा मानसिक रूप से बीमार हैं।

(तृणमूल विधायक के बिगड़े बोल, कहा- अपवित्र है अयोध्या का राम मंदिर: पेज-5)

भाजपा ने कहा- यह माओवादी विचारधारा, राजा गिरफ्तार किए जाएं

भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ए राजा का यह बयान उनकी माओवादी सोच को भी उजागर करता है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राजा को गिरफ्तार कराएं। (पेज-5)

डीके शिवकुमार के खिलाफ ईडी का केस रद

- कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री को शीर्ष अदालत से मिली राहत

200 करोड़ की रकम मिलने का ईडी ने किया था दावा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ ईडी द्वारा शुरू की गई मनी लांड्रिंग मामले की जांच को रद कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा शिवकुमार को जारी किए गए समन को रद करने से इन्कार कर दिया था। शिवकुमार ने मनी लांड्रिंग केस को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की योजना बना रही हैं, लेकिन वह इसके लिए तैयार हैं।

अगस्त 2017 में आयकर विभाग ने शिवकुमार, नई दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी हनुमंतैया व अन्य के विरुद्ध कर चोरी की जांच के तहत दिल्ली में कई परिसरों की तलाशी ली थी। ईडी ने आयकर विभाग द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर शिवकुमार, हनुमंतैया व अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की। जांच के दौरान ईडी को शिवकुमार से संबंधित 200 करोड़ रुपये की बेनामी रकम का पता चला। ईडी ने दावा किया कि यह पैसा शिवकुमार के नियंत्रण वाले 317 से अधिक बैंक खातों में जमा किया गया था। ये खाते 20 बैंकों में खोले गए थे। ईडी ने शिवकुमार से जुड़ी 800 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्तियों की खोज का भी दावा किया। इस मामले में शिवकुमार को तीन सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था।

'युवाओं को बढ़ावा देने से डरती है कांग्रेस'

सांगारेड्डी (तेलंगाना): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा, कांग्रेस युवा नेताओं को बढ़ावा देने से डरती है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे पर कटाक्ष करते हुए कहा, विपक्षी पार्टी 75-80 साल से अधिक उम्र के लोगों को नियुक्त कर रही है। पीएम ने सांगारेड्डी में 7,200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। (पेज-6)

हिजबुल्ला के हमले में एक भारतीय की मौत

नई दिल्ली: लेबनान से सोमवार को दागी गई मिसाइल में एक भारतीय की मौत और दो के घायल होने के बाद तेलअवीव स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार को एडवाइजरी जारी की। सोमवार को मार्गोलियट में एंटी टैंक मिसाइल हमले में केरल निवासी 30 वर्षीय निबिन मैक्सवेल की मौत हो गई थी जबकि बुश जोसेफ जार्ज व पाल मेल्विन नामक दो भारतीय मजदूर घायल हुए हैं। (पेज-11)

ट्राई का प्रस्ताव

कालर के नाम को स्क्रीन पर दिखाना अनिवार्य कर सकती है सरकार, ट्राई द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर दूरसंचार मंत्री ने दिखाया सकारात्मक रुख

यूजर को जानने का अधिकार है कि उसे कौन कर रहा काल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

फोन स्क्रीन पर कालर के नाम को प्रदर्शित करना सरकार अनिवार्य कर सकती है। सरकार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के इस प्रस्ताव के पक्ष में दिख रही है और इसे लेकर सकारात्मक फैसले की उम्मीद है।

ट्राई के प्रस्ताव पर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की सुरक्षा और उनकी निजता महत्वपूर्ण है। ग्राहकों को यह जानने का अधिकार है कि उसे कौन फोन कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह ट्राइ के इस प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। अभी मोबाइल फोन पर काल करने वाले का सिर्फ नंबर दिखाई पड़ता है। कालिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंटेशन (सीएलआइपी) सेवा के तहत फोन के स्क्रीन पर काल करने वाले का नंबर दिखता है। ट्राई का कहना है कि दूरसंचार कंपनियों को सीएलआइपी में नाम के प्रदर्शन की सेवा जोड़नी होगी। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे देशों में पहले से कालर के नाम को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। यूएई ने तो वहां बिकने वाले हैंडसेट में उस फीचर को समाहित करना भी अनिवार्य कर दिया है, जिसकी मदद से काल करने वाले का नाम स्क्रीन पर दिखता है। हालांकि कुछ मोबाइल फोन में पहले से यह फीचर है। ट्राई के प्रस्ताव के मुताबिक ऐसी सुविधा फीचर फोन यानी कि बिना इंटरनेट वाले फोन में भी देनी होगी।

दूरसंचार कंपनियों को तैयार करना होगा डाटा बेस: ट्राई के प्रस्ताव के मुताबिक स्क्रीन पर नाम के सही प्रदर्शन के लिए दूरसंचार कंपनियों को मास्टर डाटाबेस तैयार करना होगा। स्क्रीन पर काल करने वाले का सही नाम प्रदर्शित हो, यह जिम्मेदारी भी दूरसंचार कंपनियों की होगी। कामर्शियल कनेक्शन लेने वालों को दूरसंचार कंपनियां उनके ब्रांड का नाम आवंटित कर सकती हैं। **(खाने के साथ बोतलबंद पानी देना मानसिक प्रताड़ना: पेज-10)**

अश्विनी वैष्णव। फाइल

अश्लील या फ्राड काल से बच सकेंगे ग्राहक

ट्राई का मानना है कि इस सुविधा का फायदा यह होगा कि ग्राहक फोन उठाने से पहले यह तय कर सकेंगे कि उन्हें फोन उठाना है या नहीं। इससे बेवजह आने वाले फोन, अश्लील व फ्राड काल से ग्राहक बच सकेंगे। सिर्फ नंबर आने से कई बार जरूरी काल की भी ग्राहक अनदेखी कर देते हैं। हालांकि स्क्रीन पर नाम आने के बाद ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है। इतना ही नहीं ग्राहकों को बेकार काल से होने वाली मानसिक पीड़ा व आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
Scan the QR code to Download Toppers' Answer Copies
8468022022 WWW.VISIONIAS.IN
Heartiest Congratulations to all candidates selected in CSE 2022
39 IN TOP 50 SELECTIONS from various programs of VISIONIAS
1 AIR ISHITA KISHORE — ABHYAAS PRELIMS, ABHYAAS MAINS, ESSAY TEST SERIES, PERSONALITY DEVELOPMENT PROGRAM
2 AIR GARIMA LOHIA — ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES, ALL INDIA MAINS TEST SERIES, PERSONALITY DEVELOPMENT PROGRAM
3 AIR UMA HARATHI N — ALL INDIA MAINS TEST SERIES, PERSONALITY DEVELOPMENT PROGRAM
हिंदी माध्यम टॉपर — 66 AIR KRITIKA MISHRA
लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन 2025
प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
दिल्ली: 5 मार्च, 1 PM
अधिक जानकारी, रजिस्टर या फ्री काउंसलिंग के लिए हमारे एक्सपर्ट से बात करें
Lakshya लक्ष्य प्रीलिम्स मेंटरिंग प्रोग्राम 2024
UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2024 पर केंद्रित रिवीजन, प्रैक्टिस और मेंटरिंग प्रोग्राम
15 मार्च
ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
प्रारंभिक ✓ सामान्य अध्ययन ✓ सीसैट — English 2024: 10 Mar, हिन्दी 2024: 10 मार्च
मुख्य ✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र — English 2025: 3 Mar, हिन्दी 2025: 3 मार्च
DELHI: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, Delhi | CONTACT: 8468022022, 9019066066
GTB Nagar Enquiry and Classroom Centre, Above GTB Nagar Metro Station Gate No. 2, Delhi - 110009
AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

****

127 रहा मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ)। इससे अधिकांश इलाकों में हवा मध्यम श्रेणी में रही। अगले तीन दिन हवा की गुणवत्ता इसी श्रेणी में बनी रहेगी।

आज का मौसम

बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में धूप भी खिली रहेगी।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
6 मार्च	25.0	11.0
7 मार्च	27.0	10.0
नोएडा		
6 मार्च	26.0	11.0
7 मार्च	27.0	11.0
गुरुग्राम		
6 मार्च	23.0	09.0
7 मार्च	24.0	09.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

पुलिस, सीएपीएफ एसआइ परीक्षा के लिए आवेदन शुरू

नई दिल्ली : कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ एसआइ) परीक्षा 2024 में 4187 उप-निरीक्षक पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 29 मार्च है। परीक्षा नौ, 10 और 13 मई को आयोजित की जाएगी। दिल्ली पुलिस-पुरुष में सब-इंस्पेक्टर के लिए 125 और दिल्ली पुलिस-महिला में सब-इंस्पेक्टर के लिए 61 रिक्तियां हैं। सीएपीएफ में एसआइ की 4001 रिक्तियां हैं। (जासं)

आतंकी जावेद अहमद मट्टू के खिलाफ आरोपपत्र दायर

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद अहमद मट्टू के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। पुलिस ने मट्टू के जम्मू-कश्मीर में 11 आतंकवादी हमलों में शामिल होने का दावा किया है। स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में दायर आरोपपत्र में कहा है कि मट्टू अपनी गिरफ्तारी के समय हथियार और गोला-बारूद इकट्ठा करने के लिए एनसीआर में था। कोर्ट आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बारे में 15 मार्च को सुनवाई करेगा। (जासं)

25 झुग्गी बस्तियों को मिलेगा नल से जल

नई दिल्ली : लुटियंस दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। एनडीएमसी के अनुसार 25 झुग्गी बस्तियों के 4500 आवास में नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एनडीएमसी ने 12.7 करोड़ की राशि मंजूर की है। (जासं)

महिलाओं के खाते में अक्टूबर से आने लगेगी प्रति माह एक हजार की सम्मान राशि : आतिशी

साक्षात्कार

दिल्ली सरकार ने विधानसभा में अपना 10वां बजट पेश कर दिया है। बजट को राम राज्य बजट की थीम दी गई है। महिलाओं को एक हजार रुपये की सम्मान राशि देने जैसी बजट में घोषणाएं हैं। वैसे पूरे बजट को देखें तो यह पहली बार है कि बजट में नई घोषणाओं की कमी है। इस सब के बीच दिल्ली सरकार ने पिछले साल की अपेक्षा इस बार बजट की अनुमानित राशि भी कम की है, क्या इससे दिल्ली के विकास पर भी असर पड़ सकता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वी के शुक्ला ने वित्त मंत्री आतिशी से बात की। प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश :-

● सरकार ने इस बार राम राज्य बजट पेश किया है। चुनावी माहौल में इसका क्या उद्देश्य है?

–हमारी सरकार हर बार अलग-अलग थीम पर बजट पेश करती है। यह हमारी सरकार का 10वां बजट है। पहले बजट का थीम रोजगार था, फिर पर्यावरण था। इस बार राम राज्य थीम है। राम राज्य का मतलब है कि ऐसी सरकार जो हर वर्ग के लिए काम करे। हर वर्ग की सरकार में हिस्सेदारी हो। हम इसी अवधारणा पर पिछले कई साल से काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हर जन सुखी और समृद्ध हो। हमें नहीं लगता है कि हमारी सरकार के अलावा देश में और ऐसी कोई सरकार होगी, जो हर जन के लिए काम कर रही होगी।

● मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना कब तक शुरू होगी, इसे लेकर सरकार की क्या रणनीति है?

– दिल्ली सरकार की इस नई योजना, जिसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, सितंबर-अक्टूबर में यह राशि महिलाओं के खाते में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि इसका लाभ अधिक महिलाओं को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को अधिसूचित किया जाएगा। इसके तहत करीब 45 लाख महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। इसके लिए बजट में दो हजार करोड़ रुपये प्रविधान रखा गया है।

● विश्वविद्यालयों में बिजनेस ब्लास्टर्स योजना को लेकर छात्रों को दी जाने वाली राशि को लेकर क्या स्थिति रहेगी?

– दिल्ली सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में संचालित होने जा रही बिजनेस ब्लास्टर्स योजना प्रमुख योजनाओं में शामिल है, हम इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए तैयारी कर रहे हैं। योजना के तहत 11वीं और 12वीं के छात्रों को 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। सरकार अपने विश्वविद्यालयों में स्टार्ट-अप के लिए प्रत्येक चयनित छात्र टीम को 25 हजार रुपये की प्रारंभिक धनराशि देगी। करीब एक हजार टीमें इस योजना का हिस्सा होंगी।

● बजट में घोषणाओं में कंजूसी की है, क्या कारण है?

–हमने बजट में घोषणाओं में कंजूसी नहीं की है, हमने उन घोषणाओं का जिक्र किया है, जो हम पूरी करेंगे। जिन योजनाओं की घोषणा की है, उन्हें पूरा किया है। कई ऐसी योजनाएं भी पूरी की हैं, जिनकी घोषणा नहीं की थी।

● आप वित्त मंत्री हैं और आपके पास लोक निर्माण विभाग की भी जिम्मेदारी है, इस विभाग के पास ऐसे काम हैं, जिससे सरकार की उन्नति सड़क पर दिखती है, इसका बजट काफी कम कर दिया गया है? एक भी नई घोषणा नहीं की गई है?

–मैंने बजट में भविष्य की योजनाओं के साथ-साथ पिछले नौ साल का लेखा-जोखा भी दिया है। हमारी ऐसी सरकार है जिसने अभी तक की सभी सरकारों से तेजी से काम किया है। अभी तक 30 से अधिक फ्लाईओवर, अंडरपास आदि बनाए गए हैं। आठ फ्लाईओवर अंडरपास साल के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा।

● पिछले साल की अपेक्षा इस साल बजट की राशि में कमी की गई है। क्या इससे दिल्ली के विकास पर असर पड़ेगा?

–यह सही नहीं है कि दिल्ली का बजट पिछले साल की तुलना में कम है। पिछले साल का जो वास्तविक बजट था, उससे इस साल बजट की राशि अधिक है। कोई कमी नहीं है। दिल्ली के विकास पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को मिलने वाले 325 करोड़ रुपये रोक दिए हैं। इसके अलावा अभी तक मिलते आ रहे 10 हजार करोड़ रुपये इस बार से रोक दिए हैं। इसके बाद भी हमारी सरकार बगैर ऋण लिए चल रही है।

● इस बार स्वास्थ्य और परिवहन का भी बजट कम किया गया है, क्या कारण है?

–इस बार परिवहन क्षेत्र के लिए आवंटन कम है, क्योंकि पिछले साल के बजट में धन का एक बड़ा हिस्सा बस डिपो के विद्युतीकरण के लिए आवंटित किया गया था। यही एक कारण है कि परिवहन क्षेत्र के लिए आवंटन कम किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यदि आप बजट के प्रतिशत के रूप में देखते हैं, तो यह इतनी बड़ी गिरावट नहीं है।

● यमुना की सफाई के लिए बजट में कोई प्रविधान नहीं है?

–जल बोर्ड के काम में अड़चन लगाई जा रही है। पिछले सात माह से जल बोर्ड को एक भी पैसा जारी नहीं किया गया है, फिर भी हमने एसटीपी लगाने का काम आगे बढ़ाया है। हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।

संगम विहार कालोनी की समस्याओं को लेकर एलजी और सीएम आमने-सामने

तकरार ▶ केजरीवाल बोले, उपराज्यपाल विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मजबूर

एलजी के संगम विहार का दौरा करने के बाद की गई पोस्ट पर भड़के सीएम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

एलजी ने पोस्ट में लिखा, नौ साल बाद भी क्षेत्र के 20 लाख से अधिक लोग बदतर जीवन जीने को मजबूर

संगम विहार इलाके में निरीक्षण करते उपराज्यपाल वीके सक्सेना। सौ. एक्स

दक्षिणी दिल्ली में एलजी वीके सक्सेना द्वारा संगम विहार कालोनी में दौरे के बाद की गई पोस्ट को लेकर एलजी और सीएम मंगलवार को आमने-सामने आ गए। एलजी ने पोस्ट में लोगों को बुनियादी सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित होने का आरोप लगाया। एलजी की दिल्ली सरकार की इस आलोचना पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी सक्सेना विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मजबूर हैं।

एलजी ने पोस्ट लिखा कि नौ साल बाद भी क्षेत्र में रहने वाले 20 लाख से अधिक लोग बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं। देश कल्पना नहीं कर सकता कि भारत की राजधानी में बजबजाती नालियां, कूड़े के ढेर व बदबूदार सीवर के पानी से भरी सड़कें होंगी। इससे पहले एलजी किराड़ी और बुराड़ी इलाकों का दौरा करके भी वहां की समस्याओं को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना कर चुके हैं।

दरअसल एलजी वीके सक्सेना ने मंगलवार को एक्स पर फोटो डालकर पोस्ट में लिखा कि मैं स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर सोमवार को संगम विहार गया था। नौ साल की कठिनाइयों के बावजूद लोग यहां बुनियादी सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित हैं। वहां सड़कें नहीं हैं। कोई सीवर लाइन नहीं, कचरा निपटान की व्यवस्था नहीं है। बिजली के तार बेतरतीब ढंग से लटके हुए हैं, जो खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि उनके सामने एक रिक्शा पलट गया और एक महिला घायल हो गई। सभी संबंधित विभाग पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अधीन हैं और एमसीडी भी आपके अधीन है। एलजी ने कहा कि मुख्यमंत्री से वहां की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहा।

एलजी की पोस्ट से नाराज केजरीवाल ने जवाब देते हुए पोस्ट किया कि मैं मुख्य सचिव को सात दिनों के भीतर इन सभी कमियों को दूर करने का आदेश दे रहा हूं। आप जो काम कर रहे हैं, वह विपक्ष को करना चाहिए था। विपक्ष का काम सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करना है। उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्य से आज विपक्ष (भाजपा) के सभी सात सांसद राजनीति से संन्यास लेने में व्यस्त हैं और आठ विधायक गहरी नींद में सो रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 26 वर्षों से दिल्ली की सत्ता भाजपा से दूर है।

'दो करोड़ दिल्लीवासी कार्रवाई का इंतजार करेंगे'

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद एलजी विपक्ष की भूमिका निभाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी ठीक से जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो सेवा और सतर्कता विभाग एलजी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन्हें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि यदि यह मेरे अधीन होता तो मैं न केवल ऐसे लापरवाह अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर देता, बल्कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई भी करता कि कोई अन्य अधिकारी इस तरह की लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप इनमें से सबसे वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर देंगे। विभाग और उन्हें अनुकरणीय सजा दें। कहा कि दो करोड़ दिल्लीवासी आपकी कार्रवाई का इंतजार करेंगे।

महिलाएं फोन कर पंजीकरण के बारे में पूछ रहीं : केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- **सीएम ने एक्स पर लिखा, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की जानकारी ले रहीं महिलाएं**
- **सरकार योजना के तहत जल्द ही शुरू करेगी पंजीकरण, लाखों महिलाओं को लाभ होने की संभावना**

अरविंद केजरीवाल। सौ. : दिल्ली सरकार

मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महिलाओं का आशीर्वाद मांगा और घोषणा की कि उन्हें प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करने की योजना के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू होगा। सोमवार को विधानसभा में 2024-25 का दिल्ली बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री आतिशी ने महिलाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत 18 साल से ऊपर की पात्र गैर-आयकर दाताओं को हर महीने राशि मिलेगी।

लोकसभा चुनाव के बाद लागू होने वाली इस योजना से राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 50 लाख महिलाओं को लाभ होने की संभावना है। एक्स पर एक लंबी पोस्ट में केजरीवाल ने लिखा कि सोमवार को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा के बाद से उन्हें महिलाओं के बहुत सारे फोन आ रहे हैं और वे योजना के लिए पंजीकरण के बारे में पूछ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस योजना पर काम कर रहे हैं और इसके लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू होगा। वह जो कुछ भी कर पाए हैं, वह महिलाओं के आशीर्वाद और प्रार्थनाओं के कारण है। केजरीवाल ने महिलाओं से कहा कि मेरे विरोधियों ने मुझे कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन आपका आशीर्वाद उनकी सभी साजिशों को विफल कर रहा है। वह महिलाओं और उनके परिवारों के लिए अच्छे काम करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा उन्हें एलजी के हवाले से रुकवा देती है। अगले महीने चुनाव हैं। चुनाव में मुझे अपना (महिलाओं का) आशीर्वाद दें और अपने परिवार के सदस्यों से भी चुनाव में मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए कहें, ताकि आपका भाई और बेटा आपकी अच्छी तरह से सेवा कर सके।

आज से मोदीनगर तक चलेगी नमो भारत ट्रेन

जागरण संवाददाता, मोदीनगर

- **दुहाई-मोदीनगर खंड का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वर्चुअल शुभारंभ**
- **17 किमी लंबा है आरआरटीएस का यह खंड, मुरादनगर स्टेशन से दिखाई जाएगी हरी झंडी**

मुरादनगर में बनाया गया नमो भारत ट्रेन का स्टेशन। सौ : आरआरटीएस

मोदीनगर-मुरादनगर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। इस रूट पर आज बुधवार से नमो भारत ट्रेन दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कारिडोर के 17 किमी लंबे इस रूट का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। तीनों स्टेशनों को फूलों से सजाया गया है। नमो भारत ट्रेन के संचालन से मोदीनगर से गाजियाबाद के बीच की दूरी कुछ ही मिनटों में तय हो सकेगी। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कारिडोर का काम मार्च 2019 से शुरू हुआ था। पिछले साल प्रधानमंत्री ने इसके प्राथमिकता खंड का शुभारंभ किया। इसमें दुहाई तक नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। प्रतिदिन लोग सफर भी कर रहे हैं। तभी से अगले सेक्शन को शुरू करने पर आरआरटीएस की तैयारी चल रही थी, जिसमें मोदीनगर तक ट्रेन शुरू होनी थी। ट्रेन मुरादनगर और मोदीनगर में नार्थ व साउथ स्टेशन पर ठहरेगी। नमो भारत ट्रेन की सेवा 34 किमी के खंड पर निर्बाध रूप से उपलब्ध होगी।

मोदीनगर से बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन गाजियाबाद, साहिबाबाद व इंदिरापुरम तक नौकरी के लिए जाते हैं। ऐसे में उन्हें जाम में फंसकर परेशान होना पड़ता है। अब नमो भारत ट्रेन शुरू होने से कुछ ही देर में यह दूरी का तय होगी।

रेल इंजन में फंसकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा युवती का कटा सिर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : युवती का कटा हुआ सिर रेल के इंजन में फंसकर सोमवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में जानकारी मिली कि युवती आनंद विहार के पास ट्रेन की चपेट में आई थी और उसका सिर इंजन में लिपटकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। पुलिस जांच में युवती की पहचान कर ली गई है और आगे की जांच जारी है।

जानकारी के अनुसार सोमवार को आनंद विहार के पास लखनऊ-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस के इंजन में फंस कर युवती का सिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। यहां पर यात्रियों की नजर इंजन के नीचे फंसी सिर पर पड़ी थी। जीआरपी थाने की पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंची और जिस रूट से ट्रेन आई थी, उस रूट पर पीछे के सभी स्टेशनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पता चला कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास किसी युवती की रेल से कटकर मौत हुई थी, मगर उसका सिर गायब था।

केजरीवाल आवास में प्रत्यारोपित 19 में से सिर्फ एक ही पेड़ बच सका जिंदा

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली

- **एनजीटी ने पेड़ों के प्रत्यारोपण व काटने की अनुमति देने पर उठाए सवाल**
- **काटे गए पेड़ों के सापेक्ष नहीं लगाए गए पर्याप्त पौधे, एनजीटी ने मांगा जवाब**

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का फोटो। जागरण आर्काइव

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करने संबंधी मामले में एनजीटी के समक्ष दाखिल एक रिपोर्ट में सामने आया है कि मुख्यमंत्री आवास से प्रत्यारोपित किए गए 19 पेड़ों में से महज एक बरगद का ही पेड़ जिंदा बच सका है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्यारोपित किए गए पेड़ों में से 11 सूख चुके हैं, जबकि सात पेड़ मिसिंग हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया कि आवास से कुल नौ पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी और इसके बदले 270 बड़े पेड़ लगाए जाने थे, लेकिन अब तक महज 50 से 55 पेड़ ही लगाए गए हैं।

मामले पर सुनवाई के दौरान एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व पर्यावरण सदस्य डा. एएस बेल की पीठ ने सवाल किया कि 50 पेड़ कब लगे, इसका कोई प्रमाण है? हालांकि, इसका वन विभाग के अधिकारियों के पास जवाब नहीं था। सुनवाई के दौरान एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में प्रत्यारोपण सफल नहीं है, लेकिन जब पीठ ने पूछा कि प्रत्यारोपण क्यों किया गया, तो इसका भी अधिकारियों के पास जवाब नहीं था। एनजीटी ने उक्त तथ्यों को देखते हुए वन विभाग को निर्देश दिया कि वह बताए कि पेड़ों के काटने और प्रत्यारोपण की अनुमति देते समय क्या फैक्टर देखे जाते हैं। एनजीटी ने वन विभाग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

मुख्यमंत्री आवास पर पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने के विरुद्ध आवेदनकर्ता नरेश चौधरी के आवेदन पर नौ मई, 2023 को दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया था। एनजीटी ने मामले में बैठक कर तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाकर तीन सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि, मामले में उचित रिपोर्ट पेश नहीं करने पर एनजीटी ने जनवरी माह में वन विभाग पर 15 हजार और दिल्ली सरकार व पीडब्ल्यूडी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। आवेदनकर्ता नरेश चौधरी ने आरोप लगाया है कि लोक निर्माण विभाग ने छह-फ्लैग स्टाफ रोड में हुए निर्माण के लिए 20 से अधिक पेड़ों को काटकर पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन किया है।

नौ मीटर वाली मोहल्ला बस का ट्रायल शुरू

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले महीने से नौ मीटर लंबी मोहल्ला बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। दिल्ली सरकार इसी माह 25 मोहल्ला बसें मंगा लेगी। ये सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी। एक मोहल्ला बस दिल्ली आ चुकी है, जिसका मंगलवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राजघाट डिपो में निरीक्षण किया। दिल्ली में नौ मीटर वाली मोहल्ला बसों के चलने से लास्ट माइल कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। निरीक्षण के बाद परिवहन मंत्री गहलोत मोहल्ला बस में बैठकर बजट सत्र में भाग लेने विधानसभा पहुंचे। अभी तक दिल्ली को मिली एक मोहल्ला बस का ट्रायल शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार अभी 100 मेट्रो फीडर बसों को मोहल्ला बस के रूप में विभिन्न रूटों पर चला रही है।

गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित 7,582 बसों में प्रतिदिन 40 लाख से अधिक (बस ट्रिप) यात्री सफ़र करते हैं। इन नौ मीटर लंबी मोहल्ला बसों में 23 यात्री सीटें हैं और इनमें 25% सीटें (6 सीटें) गुलाबी हैं, जो महिला यात्रियों के लिए आरक्षित होंगी।

स्वास्थ्य

देश में लगभग हर तीसरे व्यक्ति की आंखों की दृष्टि कमजोर

55 करोड़ लोगों को चश्मे की दरकार, हर वर्ष 15 लाख चश्मा उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी नहीं हो रहा पूरा, ट्रक चालकों में भी दृष्टि दोष है एक बड़ी समस्या, एम्स में आयोजित कार्यक्रम में बोले डाक्टर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

देश में करीब हर तीसरे व्यक्ति को दृष्टि दोष है। इस वजह से उन लोगों की आंखों की नजर कमजोर है। 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को यह समस्या अधिक है लेकिन इससे छोटे बच्चे भी अछूते नहीं हैं। समस्या यह है कि दृष्टि दोष से पीड़ित ज्यादातर लोग जागरूकता के अभाव में चश्मा इस्तेमाल नहीं करते। इससे कामकाज की क्षमता भी प्रभावित होती है। लंबे समय तक दृष्टि दोष की समस्या को नजरअंदाज करने से कई लोगों को बाद में आंखों की गंभीर बीमारी भी हो जाती है। जबकि चश्मे से दृष्टि दोष की समस्या दूर हो जाती है। यह बातें एम्स में दृष्टि दोष पर आयोजित एक कांफ्रेंस में डाक्टरों ने कही।

एम्स के आरपी सेंटर के डाक्टरों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर इस समस्या के समाधान और लोगों को जागरूक करने की पहल की है।

एम्स के आरपी सेंटर के कम्युनिटी नेत्र विज्ञान के प्रोफेसर डा. प्रवीण वशिष्ठ ने बताया कि देश में 55 करोड़ लोगों को दृष्टि दोष है। 40 वर्ष की उम्र के 70 प्रतिशत लोगों को दृष्टि दोष है। इस उम्र के लोगों को नजदीक की चीजें कम दिखाई देने की समस्या अधिक होती है। दृष्टि दोष से पीड़ित सभी लोगों को चश्मे की जरूरत होती है। लेकिन बहुत कम लोगों को चश्मा उपलब्ध हो पाता है। उन्होंने बताया कि 55 करोड़ लोगों को चश्मा उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। सरकार या कोई संस्थान अकेले यह काम नहीं कर सकता। सरकार, सभी अस्पतालों व गैर सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना होगा। केंद्र सरकार ने हर वर्ष 15 लाख निश्शुल्क चश्मा देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्कूलों में बड़े बच्चों के अलावा दृष्टि दोष से पीड़ित प्राथमिक स्कूल के बच्चों को भी निश्शुल्क चश्मा दिए जाने का प्रविधान किया है। लेकिन निर्धारित लक्ष्य से 50 प्रतिशत चश्मे ही निश्शुल्क वितरित हो पाते हैं। क्योंकि लोगों की आंखों की दृष्टि जांच करने के लिए आप्टोमेट्रिस्ट व आंखों के डाक्टरों की कमी है। इसके अलावा विजन केंद्र भी कम हैं।

प्रोफेसर डा. प्रवीण वशिष्ठ ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले लोग व ट्रक चालकों को भी चश्मे की जरूरत होती है। ट्रक चालकों के दृष्टि की कभी जांच नहीं होती। दृष्टि कमजोर होने के बावजूद बगैर चश्मे के ट्रक चालक गाड़ी चलाते हैं। यह भी हादसे का एक कारण बनता है। संस्थान के साथ मिलकर काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन ने पिछले कुछ वर्षों में 20 लाख औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले व ट्रक चालकों को चश्मे दिए। इसके बाद यह पाया गया कि उन लोगों की उत्पादकता 33 प्रतिशत बढ़ गई। यदि ट्रक चालकों की आंखों की जांच कराकर निश्शुल्क चश्मे दिए जाएं तो इससे हादसे भी कम होंगे।

अभी 16 हजार विजन सेंटर बनाने की जरूरत

प्रोफेसर डा. प्रवीण वशिष्ठ ने बताया कि वर्ष 2020 तक देशभर में 20 हजार विजन केंद्र शुरू किए जाने थे। लेकिन अभी तक चार हजार ही ऐसे केंद्र शुरू हो सके हैं। 16 हजार विजन केंद्र अभी और शुरू किए जाने हैं। विजन केंद्र कम होने के कारण लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति को वर्ष में एक बार दृष्टि की जांच जरूर करनी चाहिए। लेकिन आंखों की जांच के लिए प्राथमिक विजन केंद्र कम होने से बड़े अस्पतालों में जाकर हमेशा जांच कराना लोगों के लिए आसान नहीं होता।

****

मिस्री समझकर दिया था ड्राई आइस, रेस्तरां मैनेजर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

- **मैनेजर ने गलती से दिए जाने की बात कही, आरोपित महिला वेटर अभी फरार, तलाश जारी**
- **ड्राई आइस खाने से पांच लोगों की बिगड़ी थी हालत, एक की स्थिति अभी भी गंभीर**

गुरुग्राम में रेस्तरां में खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर (मिस्री) देने से मुंह से खून निकलने के मामले में पुलिस ने रेस्तरां के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पहचान दिल्ली निवासी गगनदीप सिंह के रूप में की गई। उसने पूछताछ में गलती से ड्राई आइस क्यूब देने की बात स्वीकार की है। वहीं इसे खाने से हालत बिगड़ने के बाद पांच लोगों को आर्वी अस्पताल ले जाया गया था। यहां एक की स्थिति अब भी गंभीर है। ड्राई आइस क्यूब कार्बन डाई आक्साइड का सालिड फार्म होता है। रेस्तरां, बार व होटलों में मीट को काफी दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

सफायर 90 ला फोरेस्टा रेस्तरां में खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के नाम पर महिला वेटर ने गलती से ग्रेटर नोएडा से आए पांच लोगों को ड्राइ आइस क्यूब दे दिया था। घटना के बाद से ही महिला वेटर फरार है।

ग्रेटर नोएडा निवासी अंकित शनिवार रात पत्नी नेहा, मानिक पत्नी प्रीतिका और दीपक अरोड़ा पत्नी हिमानी के साथ गुरुग्राम स्थित सफायर 90 ला फोरेस्टा रेस्तरां में खाना खाने गए थे। अंकित के मुताबिक खाना खत्म होने के बाद उन्हें वेटर अमृतपाल कौर ने माउथ फ्रेशनर के रूप में आइस क्यूब दिया।

मणिपुर की स्थिति दुखद, पूरा भारत चाहता है सामान्य स्थिति : जयशंकर

विदेश मंत्री बोले ▸ म्यांमार से लगी खुली सीमा से स्थितियां अधिक खराब हुईं

कोरियाई दौरे पर कहा- वैश्विक पुनर्व्यवस्था में कुछ ताकतों का प्रभाव बीती बात

सियोल, प्रेट्र : दक्षिण कोरिया के दौरे पर मंगलवार को पहुंचे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वह 'बेहद दुखद' है। वहां की परिस्थितियों ने हमारे दिल तोड़ दिए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूरा भारत पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य परिस्थितियों की बहाली देखना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह युग जब कुछ ताकतों ने वैश्विक व्यवस्था को पुनर्निर्धारित करने में 'अत्यधिक प्रभाव' का प्रयोग किया था, वह अब बीत चुका है इसलिए भारत व दक्षिण कोरिया की इस प्रक्रिया में सक्रिय योगदान की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है।

दक्षिण कोरिया और जापान की चार दिवसीय यात्रा के पहले दिन भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने एक एनआरआइ के मणिपुर की स्थिति के बारे में पूछने पर अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा कि यह कैसे हुआ? सरकार ने ऐसा कैसे होने दिया? वहां जो कुछ भी हो रहा है, किसी को भी इससे पीड़ा होगी। वहां जो कुछ भी हुआ वह बेहद दुखद और पीड़ादायी है। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को 'व्यथित' बताना एक हल्का शब्द है। उन्होंने बताया कि आपसी मेलजोल वाले समुदायों (मैतेयी और कुकी) के बीच तनाव से ऐसे हालात बने। उनके बीच खाई इतनी बढ़ गई कि इतनी भीषण हिंसा हुई जिसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन पूरा देश मणिपुर के साथ है। लोग वहां सामान्य स्थिति और कानून व्यवस्था की बहाली देखना चाहेंगे। कई मायनों में पूर्वोत्तर स्वयं सेतु के रूप में कार्य कर सकता है। दुर्भाग्यवश म्यांमार से लगी खुली सीमा के चलते स्थितियां अधिक खराब हुईं। इसलिए, भारत ने सीमा के दोनों ओर 16 किमी तक बिना किसी दस्तावेज के आवाजाही की छूट पर प्रतिबंध लगाया है।

जयशंकर ने 'कोरिया नेशनल डिप्लोमेटिक अकादमी' को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक व्यवस्था के पुनर्निर्धारण में सक्रिय रूप से योगदान देने के प्रति भारत और दक्षिण कोरिया की जिम्मेदारी बढ़ रही है। वह युग जब कुछ शक्तियों ने उस प्रक्रिया पर असंगत प्रभाव डाला था, अब बीत चुका है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद या सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार का मुकाबला करना या समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना, दोनों देशों के लिए मायने रखता है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार, निवेश, सेवाओं, संसाधनों, लाजिस्टिक्स और प्रौद्योगिकी के मामले में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है। इस क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। अपनी क्षमता का अहसास कराने के लिए दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भागीदारी बढ़ाएं। जयशंकर बुधवार को अपने प्रतिपक्षी चो-ताइ-युल के साथ 10वें भारत-दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग (जेसीएम) की बैठक में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कोरियाई प्रधानमंत्री केआर हैन डक-सू से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंध सशक्त करने पर चर्चा की। उन्होंने कोरियाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चांग हो-जिन और व्यापार, उद्योग व ऊर्जा मंत्री अहन ड्यूकगेन से भी मुलाकात की है।

दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में मंगलवार को भारत-कोरिया साझेदारी पर एक सत्र को संबोधित करते विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रेट्र

भारत-फ्रांस ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग-क्षमता निर्माण पर किया मंथन

नई दिल्ली, एएनआइ : दिल्ली में आयोजित दूसरी भारत-फ्रांस रणनीतिक अंतरिक्ष वार्ता में दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे मजबूत द्विपक्षीय जुड़ाव और सरकारी क्षेत्र व वाणिज्यिक क्षेत्र में आगे के सहयोग के रास्ते पर चर्चा की। इस दौरान पहली रणनीतिक अंतरिक्ष वार्ता के बाद हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई।

अंतरिक्ष वार्ता की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से विदेश सचिव विनय क्वात्रा और फ्रांस की ओर से यूरोप-विदेश मामलों के मंत्रालय के महासचिव एनी मैरी डेस्कोट्स ने की। इस दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा अंतरिक्ष सहयोग, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण और अंतरिक्ष क्षेत्र आदान-प्रदान और रक्षा अंतरिक्ष औद्योगिक सहयोग पर हाल ही में हस्ताक्षरित आशय पत्र के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की।

इसके पहले सोमवार को भारत-फ्रांस ने परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को फ्रांस की यूरोप-विदेशी मामलों के मंत्रालय की महासचिव एनी मैरी डेस्कोट्स के साथ भी बैठक की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी तेजी से मजबूत हो रही है।

सेना की पदोन्नति सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया स्पष्ट करे केंद्र : कोर्ट

▸ **महिला अधिकारियों को सूची में शामिल करने में भेदभाव का लगाया गया है आरोप**

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह सेना में पदोन्नति संबंधी सूची में पुरुष एवं महिला अधिकारियों को शामिल किए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट करे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की स्थिति के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

इससे पहले महिला सैन्य अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने महिला अधिकारियों को सूची में शामिल करने में भेदभाव होने का आरोप लगाया। उन्होंने पिछले साल तीन नवंबर को शीर्ष अदालत द्वारा पारित एक पूर्व आदेश का हवाला दिया और कहा कि इसमें उन सभी महिला अधिकारियों पर विचार की आवश्यकता है, जिन पर पहले के विशेष चयन बोर्ड 3बी (कर्नल के रूप में पदोन्नति के लिए) द्वारा विचार किया गया है।

वेंकटरमणी ने कहा कि सूची में शामिल किए जाने की अवधारणा एक ही बैच के अधिकारियों के बीच तुलनात्मक योग्यता पर आधारित है। इसके समर्थन में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दायर नीति दस्तावेज पर भरोसा जताया और कहा कि जिन अधिकारियों को पहले ही पैनलबद्ध किया जा चुका है, उनके बारे में छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, जब नया विशेष चयन बोर्ड बुलाया गया है तो पैनल में शामिल अधिकारियों और अन्य अधिकारियों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है।

महिलाओं की भर्ती के बाद रैंक नामकरण में बदलाव के लिए भेजा प्रस्ताव : नौसेना प्रमुख

पणजी से प्रेट्र के अनुसार नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने मंगलवार को कहा कि महिलाओं को नाविकों के रूप में शामिल करने के बाद रैंक नामकरण में बदलाव और उन्हें लिंग-तटस्थ बनाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है। हमने पदनामों सी-मैन, सी-मैन क्लास-1, सी-मैन क्लास-2 में बदलावों के लिए मंजूरी को लेकर रक्षा मंत्रालय को लिखा है। अब नौसेना में महिला नाविक भी हैं और महिलाएं सी-मैन नहीं हो सकतीं। हम उन्हें नौसैनिक नाम देने पर विचार कर रहे हैं जो लैंगिक रूप से तटस्थ होगा क्योंकि हम भारत सरकार की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं।

बच्ची के साथ नहीं किया जा सकता 'संपत्ति' की तरह व्यवहार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कस्टडी (अभिरक्षा) के मुकदमे के निपटारे के लिए लड़की के साथ 'संपत्ति' की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता है। इस टिप्पणी के साथ शीर्ष अदालत ने उड़ीसा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें एक लड़की के जैविक पिता को उसकी कस्टडी दी गई थी।

शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ लड़की की बुआ की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि लड़की अपनी बुआ के पास खुशी-खुशी रह रही है। अदालत ने गौर किया कि मार्च 2014 में पैदा हुई बच्ची लगभग तीन महीने की उम्र से ही अपने जैविक पिता की बहन के साथ रह रही है।

जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोई भी पक्ष गोद लेने का दावा कर रहा है। यह केवल लड़की की कस्टडी से संबंधित विवाद है। पीठ ने कहा कि उसने लड़की से बात की और उसने कहा कि वह बुआ के साथ खुश है। लड़की इस संबंध में राय बनाने में सक्षम है। उसे संपत्ति मानकर उसके जैविक पिता को नहीं सौंपा जा सकता।

सरकारी हस्तक्षेप के बाद गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए एप फिर बहाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ **भारतीय एप को फिर से बहाल करने के लिए सहमत हुआ गूगल : वैष्णव**

▸ **केंद्रीय मंत्री ने गूगल और स्टार्टअप कंपनियों के साथ की थी मुलाकात**

सरकार के हस्तक्षेप के बाद गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटाए गए सभी भारतीय एप को फिर से बहाल करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय आइटी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि गूगल और उन स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की जिनके एप को गूगल ने प्ले स्टोर से हटाया था। उनके साथ सकारात्मक चर्चा हुई। गूगल इस बात को लेकर राजी हो गया कि हटाए गए एप पहले की तरह प्ले स्टोर पर दिखेंगे।

वैष्णव ने कहा कि टेक्नोलाजी विकास की हमारी यात्रा को गूगल लगातार मदद देता रहा है। हमें विश्वास है कि आने वाले महीनों में स्टार्टअप कंपनियां और गूगल अपने विवाद का हल निकाल लेंगे। शुल्क के भुगतान को लेकर विवाद के कारण गूगल ने गत एक मार्च को 250 से अधिक भारतीय एप को प्ले स्टोर से हटा दिया था। इन एप में भारत मैट्रिमोनियल, नौकरी डाट काम, 99एकड़, जीवनसाथी, शादी डाट काम, कुकु एफएम जैसे एप शामिल थे।

प्रतीकात्मक

गूगल की कार्रवाई के बाद अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा था कि गूगल ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद शनिवार और रविवार को कुछ एप बहाल किए गए थे। प्रेट्र के अनुसार गूगल ने बयान में कहा, सहयोग की भावना से हम एप को अस्थायी रूप से बहाल कर रहे हैं। इन कंपनियों के लिए भुगतान की समयसीमा बढ़ा रहे हैं। हम समाधान के लिए सहयोगात्मक प्रयास की आशा करते हैं।

बंगाल में किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे चुनावी हिंसा : सीईसी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

▸ **राजीव कुमार ने कहा-सख्ती से लागू करेंगे 'जीरो टालरेंस' की नीति**

▸ **बंगाल में आधार कार्ड बिना भी कर सकेंगे मतदान**

बंगाल में चुनावी हिंसा के इतिहास को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग इस बार बेहद सख्त है। राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कोलकाता के तीन दिनी दौरे पर आई निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ ने कड़े शब्दों में कहा कि बंगाल में चुनावी हिंसा किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे लेकर सख्ती से 'जीरो टालरेंस' की नीति अपनाई जाएगी। बंगाल में कुछ जिलों में लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय होने की शिकायत पर कहा- आधार कार्ड नहीं होने पर भी मतदान करने में समस्या नहीं होगी। अन्य 12-13 तरह के दस्तावेज में से कोई एक दिखाकर मतदान किया जा सकेगा।

राज्य चुनाव आयुक्त, राजनीतिक दलों, प्रवर्तन एजेंसियों व पुलिस-प्रशासन के साथ बैठकों के दौर के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को प्रेस कान्फ्रेंस में कहा- 'लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष व हिंसा-मुक्त चुनाव कराने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। लोग भय-मुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसकी व्यवस्था की जाएगी। चुनाव की तैयारियों के बाबत हुई बैठक में जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों व पुलिस आयुक्तों को अपने अधिकार क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया के दौरान हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा गया है। पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष होकर काम करने को कहा गया है। वे अगर इसका अनुपालन नहीं करेंगे तो चुनाव आयोग को अनुपालन करवाना भी आता है।'

अगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। प्रेट्र

प्रत्याशियों के लिए शुरू किया जाएगा 'केवाईसी'

निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्याशियों को जानने के लिए 'नो योर कैंडिडेट' (केवाईसी) नामक विशेष एप शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रत्याशियों की ओर से जमा किए गए उनके हलफनामे उपलब्ध होंगे। जिन प्रत्याशियों के खिलाफ पूर्व या वर्तमान में कोई आपराधिक मामला होगा, उन्हें अनिवार्य रूप से समाचारपत्रों और टीवी चैनलों में तीन बार उसकी जानकारी देनी होगी।

इसी तरह पार्टियों को भी अपनी वेबसाइट/इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म और एक राष्ट्रीय और एक आंचलिक समाचार पत्र के माध्यम से इस बात की जानकारी देनी होगी कि उक्त प्रत्याशी का उन्हें क्यों चयन करना पड़ा।

चुनाव के चरणों पर चल रहा विचार : बंगाल में एक चरण में मतदान कराने की तृणमूल की मांग पर राजीव कुमार ने कहा- 'कहां कितने चरण में मतदान होंगे, यह अभी तय नहीं किया गया है। हम इस पर होमवर्क कर रहे हैं और संबंधित पक्षों से सुझाव ले रहे हैं। सही समय पर इसकी सूचना दे दी जाएगी।'

सभी राज्यों में भेजा जा रहा केंद्रीय बल: लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही बंगाल में केंद्रीय बल भेज दिए जाने की तृणमूल की शिकायत पर राजीव कुमार ने कहा कि सिर्फ बंगाल नहीं, सभी राज्यों में केंद्रीय बल भेजा जा रहा है। यह एक मानक संचालन प्रक्रिया है। जिला चुनाव अधिकारी, पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त व पर्यवेक्षकों के परामर्श के आधार पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। फर्जी मतदान रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

धन-बल पर भी कड़ी निगरानी : चुनाव में धन-बल के इस्तेमाल पर भी कड़ी निगरानी रहेगी। ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नकद, शराब, मादक पदार्थ व मुफ्त उपहारों के वितरण को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बंगाल से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के एप पर एक घंटे तक ठप रहे नेटवर्क

▸ **भारत समेत कई देशों के यूजर्स ने की शिकायतें, लोगों ने शिकायत के लिए एक्स का लिया सहारा**

नई दिल्ली, एपी : जीमेल, यूट्यूब, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म की कई सेवाएं लगभग एक घंटे तक डाउन रहीं हैं। लोगों के फेसबुक अकाउंट खुद से ही लाग आउट हो रहे थे, जबकि इंस्टाग्राम के कई फीचर्स काम नहीं कर रहे थे। इंटरनेट मीडिया मंचों के तमाम यूजरों को मंगलवार को भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में अपने अकाउंट के संचालन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गूगल और मेटा के अधीन संचालित विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर यूजर्स के अकाउंट अचानक ही बंद नजर आने लगे। ऐसी स्थिति में इंटर मीडिया यूजरों ने अपनी समस्याओं के बारे में सूचना देने के लिए एक्स, वाट्सएप और अन्य आनलाइन मंचों का सहारा लिया।

इंटरनेट मीडिया नेटवर्क पर होने वाली गड़बड़ियों पर नजर रखने वाले मंच डाउन डिटेक्टर के अनुसार, गूगल और मेटा के विभिन्न एप में नेटवर्क खराब होने की समस्या भारतीय समयानुसार रात नौ बजे के आसपास दर्ज की गई थी। यूजरों की शिकायत है कि उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, यूट्यूब के खातों से लाग आउट कर दिया गया और वे इनमें से किसी भी प्लेटफार्म का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इस संबंध में फेसबुक और इंस्टाग्राम का संचालन करने वाली कंपनी मेटा के संचार निदेशक एंडी स्टोन ने कहा कि हम अभी इस पर काम कर रहे हैं। वहीं जीमेल और यूट्यूब का संचालन करने वाली कंपनी गूगल की तरफ से तत्काल कोई जवाब नहीं मिला।

मेटा के डाउन होने पर मस्क ने किया कटाक्ष

मेटा का सर्वर डाउन होने पर एलन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग द्वारा संचालित सेवाओं पर कटाक्ष किया। इस दौरान उन्होंने एक मीम एक्स पोस्ट किया। इसमें कैप्शन के रूप में इंस्टाग्राम, फेसबुक और थ्रेड्स की टीम का नेतृत्व करने वाले कप्तान को पेंगुइन के रूप में दिखाया गया। मस्क ने मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन की पोस्ट की छवि के साथ यह एक्स पोस्ट किया।

भारत ने यह सुनिश्चित किया कि हिंद महासागर में कोई ताकत नहीं दिखाएगा

▸ **रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी सैन्य आक्रामकता पर दिया परोक्ष संदेश**

▸ **कहा-पीएम मोदी के नेतृत्व में खतरे आंकने व निपटने का तरीका बदला**

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के सैन्य शक्ति दिखाने के संदर्भ में परोक्ष संदेश देते हुए कहा कि भारतीय नौसेना यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी सशक्त आर्थिक और सैन्य ताकत हिंद महासागर क्षेत्र में अन्य देशों पर अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाए या उनकी संप्रभुता के लिए खतरा बन जाए। नौसेना यह भी पक्का कर रही है कि कोई भी यहां पर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश नहीं कर पाए। इसके अलावा, उन्होंने नौसैनिक कमांडरों को किसी भी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है।

गोवा स्थित नेवल वार कालेज की नई इमारत के उद्घाटन और कर्नाटक के करवर नौसैनिक बेस के कार्यक्रमों के वर्चुअल संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंद महासागर के सभी पड़ोसी देशों को उनकी स्वायत्तता और संप्रभुता कायम रखने में मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना पूरी तरह तैयार है। वह हिंद महासागर के तटीय देशों को पूरी सुरक्षा प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खतरों को आंकने और उनसे निपटने का तरीका बदल गया है। पहले सरकारों का पूरा फोकस जमीन पर स्थित सीमाओं को ही सुरक्षित करने पर पूरा जोर रहता था। लेकिन जल क्षेत्र के खतरों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। नए भारत के रणनीतिक विचारों में बदलाव पर सिंह ने कहा कि अब भारत को जमीनी सीमाओं के साथ समुद्र से घिरे देश के रूप भी देखा जाता है।

गोवा स्थित नेवल वार कालेज के नए भवन के उद्घाटन अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तथा नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार। एएनआइ

आइएनएस ने न्यूजप्रिंट पर 5% सीमा शुल्क समाप्त करने की मांग की

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ **भू-राजनीतिक अनिश्चितता, लाजिस्टिक लागत में बढ़ोतरी, डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में कमी और सीमा शुल्क जैसे कई कारणों से प्रकाशकों का वित्तीय भार बढ़ा**

द इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी (आइएनएस) ने सरकार से न्यूजप्रिंट के आयात पर लगने वाले पांच प्रतिशत शुल्क को समाप्त करने का आग्रह किया है ताकि अखबार की लागत को कम किया जा सके। आइएनएस ने अपने बयान में कहा है कि भू-राजनीतिक अनिश्चितता, लाजिस्टिक लागत में बढ़ोतरी, डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में कमी और सीमा शुल्क जैसे कई कारणों से देश के प्रकाशकों का वित्तीय भार बढ़ गया है। बयान में कहा गया है कि रूस व यूक्रेन के बीच लड़ाई के साथ पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन के साथ न्यूजप्रिंट की सप्लाई भी प्रभावित हुई है।

आइएनएस के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि ऐसे में सरकार अगर न्यूजप्रिंट के आयात पर लगने वाले पांच प्रतिशत के शुल्क को वापस ले लेती है तो इससे प्रिंट मीडिया उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। प्रकाशक को अपनी लागत के प्रबंधन में आसानी होगी और वे जनता तक विश्वसनीय खबर व सूचनाएं निर्बाध तरीके से पहुंचाते रहेंगे। बयान के मुताबिक लाल सागर में व्यवधान की वजह से अनिवार्य वस्तुओं के साथ न्यूजप्रिंट का आयात भी प्रभावित हो रहा है। न्यूजप्रिंट सप्लायर पुराने आर्डर को रद कर रहे हैं। कई न्यूजप्रिंट मिल ने अपने संचालन को इन वजहों से निलंबित कर दिया है। डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में होने वाली गिरावट से भी प्रिंट मीडिया उद्योग की लागत में बढ़ोतरी हो रही है। आइएनएस ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कायम रखने के लिए प्रिंट मीडिया उद्योग का जिंदा रहना सबसे जरूरी है। इंटरनेट मीडिया पर गलत सूचना के प्रसार के इस युग में प्रिंट मीडिया पाठकों में खबरों के प्रति विश्वसनीयता कायम करने का काम कर रहा है। प्रिंट मीडिया सरकार की नीति व लोक कल्याणकारी कार्यक्रम की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाने का काम करता है।

हिमाचल में हाई कोर्ट ने निरस्त किया वाटर सेस अधिनियम

आदेश

सरकार को प्रविधानों के तहत उगाही राशि चार सप्ताह के भीतर वापस करने का आदेश, भारत सरकार के उपक्रमों और निजी कंपनियों ने कोर्ट में दायर की थी याचिकाएं

विधि संवाददाता, शिमला

▸ **कोर्ट ने कहा, संविधान के तहत राज्य सरकार के पास ऐसा कानून बनाने की शक्ति नहीं**

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश वाटर सेस अधिनियम के प्रविधानों को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट के समक्ष विद्युत उत्पादन से जुड़े भारत सरकार के उपक्रमों और निजी विद्युत कंपनियों ने याचिकाएं दायर की थीं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने 39 कंपनियों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अधिनियम के प्रविधानों व नियमों को रद कर दिया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को उगाही राशि चार सप्ताह में वापस करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत प्रदेश सरकार ऐसा कानून बनाने की शक्तियां नहीं रखती। एनटीपीसी, बीबीएमबी, एनएचपीसी व एसजेवीएनएल ने दलील दी थी कि प्रदेश सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत उस पानी पर कर नहीं लगा सकती, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाना हो।

हाई कोर्ट ने दी अहम व्यवस्था।

प्रदेश सरकार केवल उत्पादित बिजली पर ही कर या सेस लगाने की शक्तियां रखती है। केंद्र व प्रदेश सरकार के साथ अनुबंध के आधार पर कंपनियां राज्य को 12 से 13 प्रतिशत बिजली निश्शुल्क देती हैं। ऐसे में हिमाचल वाटर सेस अधिनियम के तहत कंपनियों से सेस वसूलने का प्रविधान संविधान के अनुरूप नहीं है।

केंद्र सरकार ने भी दिए थे निर्देश : कोर्ट को बताया गया था कि 25 अप्रैल, 2023 को केंद्र सरकार ने पाया था कि कुछ राज्यों में भारत सरकार के उपक्रमों पर सेस वसूला जा रहा है। केंद्र ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी कर भारत सरकार के उपक्रमों से वाटर सेस न वसूलने के लिए कहा था। आरोप लगाया था कि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। इससे पहले प्रदेश में निजी जल विद्युत कंपनियों ने भी अधिनियम को चुनौती दी थी। निजी जल विद्युत कंपनियों ने आरोप लगाया था कि वाटर सेस संविधान के प्रविधानों के विपरीत है।

वाटर सेस से आए 34.75 करोड़, आयोग पर 1.9 करोड़ रुपये खर्च : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से वाटर सेस अधिनियम को निरस्त करने के बाद प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय जाने का निर्णय लिया है। राज्य जल आयोग को अब तक विद्युत कंपनियों से 34.75 करोड़ रुपये का सेस प्राप्त हुआ था, जबकि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के वेतन पर 1.9 करोड़ का खर्च हुआ है। अब सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलने पर ही इस आयोग का अस्तित्व बरकरार रहेगा। पिछले वर्ष आयोग ने 173 सरकारी और निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों से वाटर सेस लेने के लिए प्रशासनिक कार्यवाही की थी। सभी को नोटिस दिए गए थे। जिन कंपनियों ने वाटर सेस का भुगतान किया था, उनमें से अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र की थीं। दो निजी कंपनियों ने वाटर सेस का भुगतान किया था।

पिछले वर्ष अप्रैल में प्रदेश सरकार ने 173 विद्युत उत्पादक कंपनियों को 871 करोड़ के वाटर सेस का नोटिस जारी किया था। वाटर सेस का यह बिल मार्च 2023 से जुलाई 2023 तक के पांच माह का रहा था। नोटिस में कहा गया था कि 10 दिन में कंपनियां आयोग की तरफ से दिए बैंक खातों में इसको जमा करवाएं। भुगतान के लिए दिसंबर 2023 तक तीन किस्तें चुनने का विकल्प था, लेकिन अधिकांश कंपनियों ने आयोग के नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया था।

****

कह कर रहेंगे

माधव जोशी

23 जनवरी, 1977 को आधिकारिक तौर पर जनता पार्टी लांच हुई। इसमें जनता मोर्चा, चौधरी चरण सिंह का भारतीय लोक दल, स्वतंत्र पार्टी, राज नारायण और जार्ज फर्नांडीस की सोशलिस्ट पार्टी आफ इंडिया व भारतीय जनसंघ शामिल हुए थे।

घोटाले की कालिख से निकले देश में अब नई ऊर्जा

यूपीए सरकार की गलतियों से लिया सबक, केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने कई नीतियों में किया संशोधन

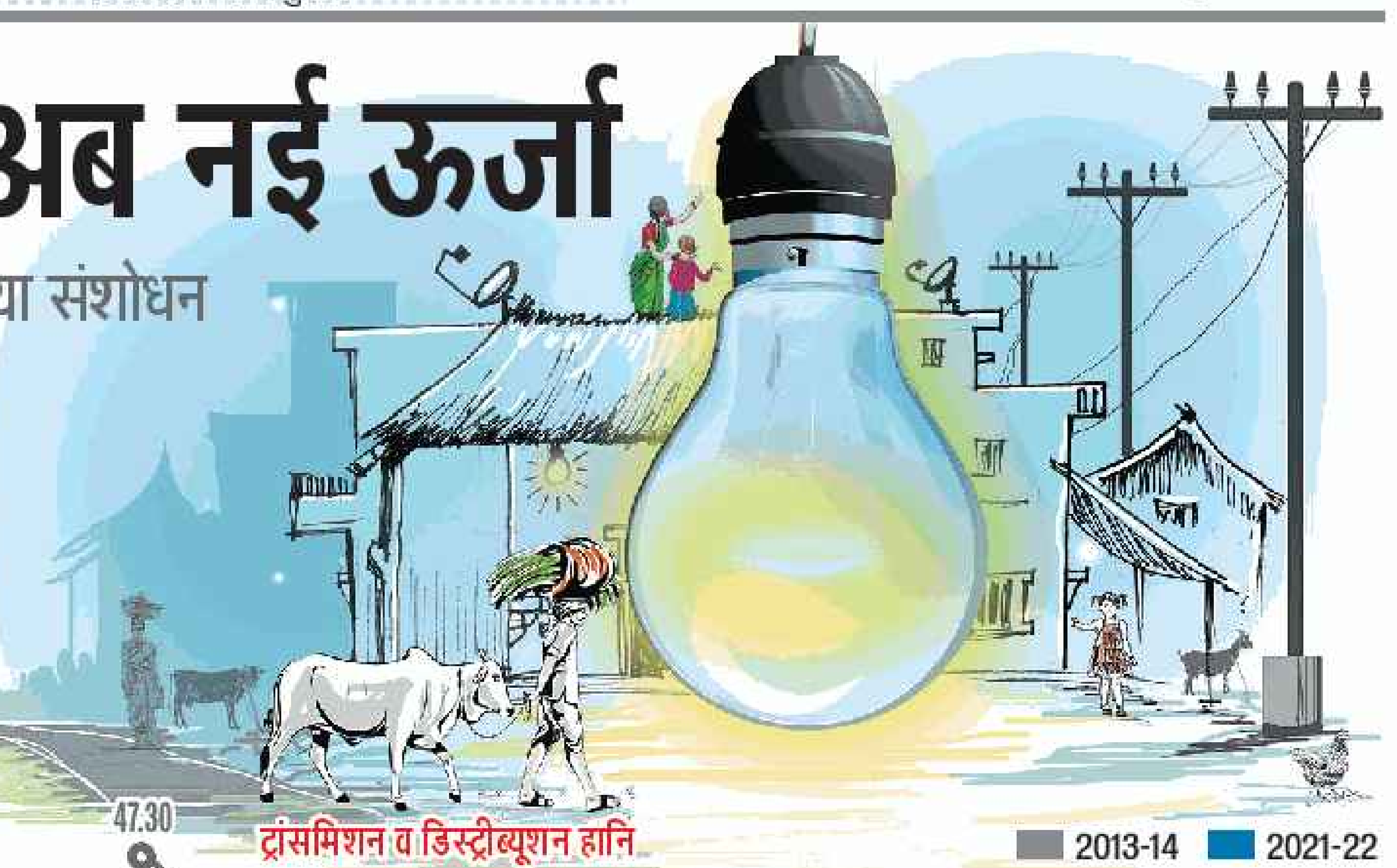

जयप्रकाश रंजन • नई दिल्ली

सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं, आज के दौर में बिजली भी जीवन की मूलभूत जरूरतों में ही शामिल है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में विद्युतीकरण के लिए प्रयास पिछली यूपीए सरकार ने भी किए, लेकिन नीतियों की खामियां 'ब्रेकडाउन' साबित हुईं। परिणामतः आजादी के छह दशक बाद भी 17 हजार गांव अंधेरे में डूबे रहे। बिजली क्षेत्र की डांवाडोल स्थिति में 'कोढ़ में खाज' वाली कहावत कोयला ब्लाक आवंटन ने चरितार्थ कर दी, जिसके कारण इस क्षेत्र में कंपनियों का भारी-भरकम निवेश और बैंकों का लाखों करोड़ रुपया एनपीए के तौर पर फंस गया। अब आंकड़े केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के इस दावे को पुष्ट करते हैं कि बीते 10 वर्षों में देश उस अनिश्चितता के अंधेरे से निकला है, गांव-गांव और घर-घर बिजली पहुंचने से देश में विकास पथ पर बढ़ने की नई ऊर्जा का संचार हुआ है। 2014 में केंद्र में जब भाजपा सत्ता में आई, तब उसे विरासत में अच्छी विकास दर वाली अर्थव्यवस्था तो मिली, लेकिन डांवाडोल बिजली सेक्टर भी मिला।

जुलाई, 2012 में बिजली की कमी से देश के अधिकांश हिस्सों में बिजली आपूर्ति का संकट था। कोयला ब्लाक आंवटन घोटाले के बाद कोयला आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह से अनिश्चितता थी। देश में 25 हजार मेगावाट के गैस आधारित पावर प्लांट तैयार थे, पर इनके लिए गैस अनुपलब्ध थी (यह स्थिति अब भी है)। बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति पूरी तरह से लड़खड़ा रही थी। ऐसे में अगर पिछले 10 वर्षों के रिकार्ड को देखें तो ऊर्जा सुरक्षा के हर क्षेत्र में स्थिति सुधरी हुई दिखती है। वजह यह है कि इस सरकार ने बिजली सेक्टर में पूर्व की सरकारों की गलतियों से सबक लिया और लगातार नीतियों में संशोधन किया। उसके परिणाम सामने हैं। देश के सभी गांव और सभी घरों तक बिजली पहुंच चुकी है। हर घर को बिजली देने के लिए शुरू की गई सौभाग्य योजना के तहत करीब 2.86 करोड़ घरों को बिजली दी गई। ताजा आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 21 घंटे व शहरी क्षेत्र में तकरीबन 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। पिछले नौ वर्षों में कुल 1.943 लाख मेगावाट बिजली क्षमता जोड़ी गई है, जिससे देश की कुल बिजली उत्पादन की क्षमता 4.31 लाख मेगावाट हो चुकी है, जबकि अधिकतम खपत 2.44 लाख मेगावाट ही गई है। 2023-24 के दौरान बिजली की मांग रिकार्ड 2.43 लाख मेगावाट तक पहुंच गई थी, जिसकी आपूर्ति करने में कोई परेशानी नहीं हुई। 2021 में कोयले की कमी से जो समस्या पैदा हुई थी, उससे सरकार और सरकारी कंपनियों ने भी सबक लिया और यह समस्या दोबारा पैदा नहीं होने दी गई। यूपीए के कार्यकाल में एक समय देश के 100 ताप बिजली घरों में से दो तिहाई में कोयला आपूर्ति की क्रिटिकल स्थिति (सात दिनों से कम) में चल रहे थे। अब स्थिति पूरी तरह से सुधर चुकी है।

राज्यों में शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति का लेखा-जोखा

राज्य	वर्ष 2018-19		वर्ष 2020-21		वर्ष 2022-23	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
उत्तर प्रदेश	19:10	23:97	16:28	23:47	16:15	23:54
बिहार	21:22	–	21:90	23:41	20:10	23:40
पंजाब	23:27	23:78	21:33	23:50	–	23:68
मध्य प्रदेश	23:33	23:70	19:62	23:94	20:66	23:60
हरियाणा	19:62	23:28	17:12	23:62	19:40	23:63
बंगाल	18:18	23:97	22:97	23:77	23:33	23:85
अखिल भारत	20:70	23:80	20:50	23:80	20:60	23:80

(आपूर्ति: एक दिन में औसत घंटे) (स्रोत: लोकसभा प्रश्न)

ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन हानि
2013-14 | 2021-22 (प्रतिशत में)

राज्य	मान
बिहार	47.30, 32.42
उत्तर प्रदेश	30.52, 29.10
पंजाब	20.70, 11.67
हरियाणा	35.80, 13.72
झारखंड	33.79, 13.10
हिमाचल प्रदेश	21.00, 12.90
छत्तीसगढ़	28.40, 18.13
मध्य प्रदेश	31.50, 22.45
दिल्ली	19.90, 8.12

(स्रोत-सीईए, बिजली मंत्रालय)

देश में बिजली की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)

	2013-14	2022-23
राज्य	90,062	1,06,341
निजी	72,797	2,21,328
केंद्र	66,223	1,02,293
कुल	2,29,082	4,29,961

100 करोड़ टन को पार करने जा रहा है कोयला उत्पादन

राज्यवार बिजली की कुल उपलब्धता (करोड़ यूनिट में)

राज्य	2013-14	2022-23
बिहार	1,476	3,876
उत्तर प्रदेश	8,161	14,305
पंजाब	4,808	6,922
हरियाणा	4,321	6,095
झारखंड	701	1,229
हिमाचल प्रदेश	888	1,254
छत्तीसगढ़	1,880	3,898
मध्य प्रदेश	4,939	9,197
दिल्ली	2,679	3,513
बंगाल	4,276	6,027
उत्तराखंड	1,149	1,539

(स्रोत: सीईए, बिजली मंत्रालय)

कितनी बदली जिंदगी

10 वर्षों के रिकार्ड को देखें तो ऊर्जा सुरक्षा के हर क्षेत्र में स्थिति सुधरी

17,000 गांव, ऐसे थे जिनमें बिजली नहीं पहुंची थी यूपीए शासन में

2.86 करोड़ घरों को दिया गया कनेक्शन पिछले 10 वर्षों में

बिजली उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया में इस तरह हुए मजबूत

कोयला उत्पादन: वर्ष 2013-14 में देश में 42.64 करोड़ टन कोयला उत्पादन हुआ था, जो वर्ष 2023-24 में पहली बार 100 करोड़ टन को पार करने जा रहा है। अब भारत एक कोयला निर्यातक देश बनने का रोडमैप तैयार कर रहा है। कोयला मंत्रालय की योजना के मुताबिक, वर्ष 2024-25 से भारत एक नेट कोयला निर्यातक देश बन सकता है। ऐसा नहीं है कि तब भारत कोयला के आयात को पूरी तरह से खत्म कर देगा, लेकिन सारी योजनाएं कारगर रहीं तो भारत अपनी पूरी कोयला मांग को घरेलू उत्पादन से पूरा करने में सक्षम होगा।

बिजली वितरण में सुधार: बिजली चोरी और ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन (टीएंडडी) से होने वाली हानि बिजली क्षेत्र की एक बड़ी समस्या थी। अब यह काबू में दिख रही है। जुलाई, 2021 से लागू रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) से बिजली वितरण कंपनियों को 3.03 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि टीएंडडी हानि घटाने के लिए दी गई है। अगस्त, 2023 के आंकड़े बताते हैं कि इसका स्तर पहली बार 16 प्रतिशत से कम (15.4 प्रतिशत) पर आया है। वर्ष 2013-14 में यह 22 प्रतिशत से ज्यादा था। अब केंद्र सरकार ने इसे 10 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य राज्यों को दिया है।

बिजली की बड़ी बचत: देश में प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) बल्ब लगाने के लिए सरकार ने उजाला अभियान चलाया। इससे वर्ष 2014 से अभी तक 48 अरब यूनिट बिजली सालाना बचाने में मदद मिली है। सरकार का दावा है कि इससे 3.90 करोड़ टन कम कार्बन उत्सर्जन किया गया है। वर्ष 2015 में पहली बार केंद्र सरकार के समर्थन से देशभर में स्ट्रीट लाइट को बदलने व वहां एलइडी बल्ब लगाने का अभियान एसएलएनपी शुरू किया गया था। एलईडी बल्ब की कीमतों में 90 प्रतिशत तक की गिरावट हुई और भारत आज इसका एक बड़ा निर्यातक है। इसी तरह से पहली बार वर्ष 2020 में बिजली ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर नियम लागू किया गया। ग्राहकों को यह अधिकार दिया गया कि वह सुरक्षित, पर्याप्त और गुणवत्ता वाली बिजली की मांग अपने क्षेत्र की वितरण कंपनी से कर सकते हैं। उक्त हालात इसलिए बने हैं, क्योंकि बिजली क्षेत्र को लेकर लगातार क्रियाशील नीतियां बनाई गईं।

अतीत के आईने से

लोकसभा चुनाव 1977
आपातकाल की घोषणा

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की, जिसने मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण सहित कई प्रमुख विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे धकेल दिया। आपातकाल की स्थिति ने प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता पर सीमाएं लगा दीं। हालांकि, मार्च 1977 में इंदिरा गांधी द्वारा नए चुनाव के आह्वान के बाद आपातकाल का दौर खत्म हो गया।

16-20 मार्च के बीच हुआ चुनाव के लिए मतदान

32,11,74,327 थी मतदाताओं की संख्या

19,42,63,915 वोट पड़े

60.5% हुआ मतदान

देश के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई

आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया। 41.32 प्रतिशत वोट शेयर के साथ, जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल की और 405 सीटों में से 295 पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस (ओ) ने तीन सीटें जीतीं। कुल 542 सीटों में से जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने 330 सीटें जीतीं। कांग्रेस पार्टी ने 492 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 34.52 वोट शेयर के साथ केवल 154 सीटें जीतीं। मोरारजी देसाई 24 मार्च को देश के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने।

उत्तर बनाम दक्षिण

1977 के लोकसभा परिणाम ने उत्तर बनाम दक्षिण का स्पष्ट विभाजन प्रदर्शित किया। बिहार, उप्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन दक्षिण में पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ 154 में से 121 सीटें जीतकर काफी अच्छा प्रदर्शन किया।

महासमर की खबरों के लिए स्कैन करें।

लोस में तीन गुना बढ़ीं महिला प्रत्याशी

लोकसभा चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी में दूसरी लोकसभा से लेकर 2019 आम चुनाव तक लगातार वृद्धि देखी गई है। 1957 के चुनावों में कुल उम्मीदवारों में से केवल तीन प्रतिशत महिलाएं थीं, जो 2019 में बढ़कर नौ प्रतिशत हो गई।

सबसे ज्यादा महिला सांसद 2019 में

17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद चुनी गई थीं। यह आजादी के बाद अब तक की सबसे अधिक संख्या है। चुनाव लड़ने वाली 716 महिला उम्मीदवारों में से 78 निर्वाचित हुईं जो सदन का 14 प्रतिशत है। 2014 में सदन में 62 महिला सांसद थीं।

लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की हिस्सेदारी

- **3%** महिलाएं थीं 1957 और 1989 के बीच कुल उम्मीदवारों में
- **6%** तक हो गई 1998 और 1999 में यह हिस्सेदारी
- **7%** महिलाएं थीं 2004-2009 के लोकसभा चुनावों में
- **8%** महिलाएं थीं 2014 चुनाव में
- **9%** उम्मीदवार महिलाएं थीं 2019 के लोस चुनाव में

कुल महिला उम्मीदवारों में से विजेता की संख्या घटी

- **49%** महिलाएं निर्वाचित हुई थीं 1957 के चुनावों में
- **43%** निर्वाचित हुईं 1967 में चौथी लोकसभा में
- **25%** था 1984 के लोस चुनावों में निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत
- **12%** के साथ आधा रह गया 1991 की लोकसभा में यह प्रतिशत
- **7%** अब तक की सबसे कम महिला उम्मीदवार सदन के लिए चुनी गईं 1996 में
- **13%** हो गया यह आंकड़ा 2004 के लोकसभा चुनाव में
- **11%** रह गया यह आंकड़ा 2009 के चुनाव में
- **9%** महिलाएं ही निर्वाचित हुईं 2014 की लोकसभा में
- **10%** महिलाएं निर्वाचित हुईं 2019 की लोकसभा में

आरक्षण से बढ़ेगी संख्या: बहुचर्चित नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 के कार्यान्वयन से महिलाओं की संख्या 179 तक पहुंच सकती है। इस विधेयक में 15 वर्ष के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव है।

पीएम आवास हो सकते हैं गेमचेंजर

संदीप तिवारी • रायपुर

- छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीबों को लोस चुनाव से पहले आवास देने की पहल
- इस योजना को लेकर केंद्र के साथ आमने-सामने थी पूर्ववर्ती बघेल सरकार

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है। राज्य में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के 18 लाख गरीबों के मकान निर्माण के काम में तेजी ला दी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में प्रदेश के 16 लाख गरीब आवास से इसलिए वंचित हो गए थे, क्योंकि राज्यांश की राशि नहीं मिल पाई थी। आवास नहीं दे पाने से व्यथित होकर भूपेश कैबिनेट के मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से त्याग-पत्र तक दे दिया था। इसके बाद भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठाती रही। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने सड़क से लेकर सदन तक आवासहीनों का मुद्दा उठाया था और विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा की जीत के लिए यह बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। विधानसभा की 90 सीटों में से 54 पर जीत हासिल कर भाजपा ने भूपेश सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। कांग्रेस को 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक सीट हासिल हुई।

राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में से पिछली बार भाजपा ने नौ और कांग्रेस ने दो सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार भाजपा सभी 11 सीटों को जीतने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है।

केंद्र से चाहिए अब 15 लाख परिवारों के लिए बजट

18 लाख में से अभी केंद्र से छत्तीसगढ़ को 15 लाख परिवारों के आवास के लिए राशि चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है।

"हमारी सरकार प्रदेश के गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। योजना के तहत प्रदेश के 18 लाख से अधिक परिवारों के लिए पीएम आवास की स्वीकृति प्रदान की है।"
विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, छत्तीसगढ़

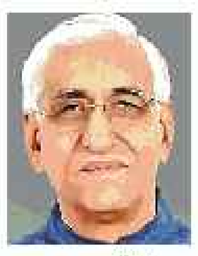

"18 लाख आवास देने की बात साय सरकार ने की है, पर बजट में इतने घरों का प्रविधान नहीं है। चुनाव तक इतने लोगों को आवास देने की बात करेंगे, पर पांच वर्ष के पहले इतने लोगों को आवास देना आसान नहीं है।"
टीएस सिंहदेव, पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, छत्तीसगढ़

विधानसभा की गारंटी आएगी लोकसभा में भी काम: भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 से पहले जारी किए गए अपने संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) को मोदी की गारंटी के रूप में सार्वजनिक किया था। इसमें 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए धन-राशि का आवंटन करने का वादा किया गया था।

पहली कैबिनेट में लिया गया है फैसला: विष्णुदेव साय कैबिनेट की पहली बैठक में ही राज्य में 18 लाख पीएम आवासों के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। इसके लिए 21 हजार, 600 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बजट में अगले पांच साल में ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ और घर बनाने का प्रविधान किया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में वंचितों के लिए घर का रास्ता खुल गया है।

खिसकते जनाधार और ढीली होती पकड़ से जूझती बसपा

दलों का दम

अजय जायसवाल • लखनऊ

राष्ट्रीय दल होने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी दूसरे राज्य में न कोई सांसद जीता और न ही उसे उल्लेखनीय वोट मिले। पार्टी ने 26 राज्यों में चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन उसे 50 प्रतिशत राज्यों में एक प्रतिशत भी वोट नहीं मिले। सात राज्यों में दो प्रतिशत से कम, जबकि पांच राज्यों में तीन से पांच प्रतिशत वोट ही हासिल हुए। उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक 19.26 प्रतिशत मतदाताओं ने 'हाथी' का बटन दबाकर पार्टी के 10 सांसद चुने थे। अबकी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर चुकी बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड को छोड़ देशभर में पार्टी का 'नीला परचम' लहराने का दायित्व अब अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल को-आर्डिनेटर आकाश आनंद को सौंप रखा है। चार दशक पुरानी बसपा की भविष्य में कमान संभालने वाले आकाश के सामने दूसरे राज्यों में पार्टी का खाता खोलने से पहले दलितों में 'हाथी' की पैठ बढ़ाने की बड़ी चुनौती है।

वर्ष 1984 में बनी बसपा के इतिहास में पार्टी के अब तक चार राज्यों में ही सांसद रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तीन लोकसभा सीटों के अलावा बसपा ने पहले-पहल वर्ष 1989 में उस पंजाब राज्य की भी एक सीट पर जीत दर्ज की थी, जहां से पार्टी के संस्थापक कांशीराम रहे हैं। वर्ष 1991 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और 1998 में हरियाणा में भी पार्टी ने पहली बार खाता खोला था। लोकसभा में पार्टी की सबसे बेहतर स्थिति डेढ़ दशक पहले तब थी, जब वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर मायावती के नेतृत्व में बसपा की सरकार बनी थी। बसपा सरकार के दौरान वर्ष 2009 के चुनाव में पार्टी के उत्तर प्रदेश से 20 और मध्य प्रदेश से एक सांसद चुने गए थे और उसे अब तक के सर्वाधिक 6.17 प्रतिशत वोट मिले थे।

अब हालात एकदम अलग: वर्तमान में पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, उससे कहीं बेहतर स्थिति में तकरीबन तीन दशक पहले वर्ष 1996 में थी। मायावती ने दूसरे राज्यों में पार्टी की सेहत सुधारने के लिए अपने विश्वासपात्रों को कमान तो सौंपी, लेकिन कोई दम न दिखा सका। लगभग तीन माह पहले बड़ी उम्मीदों के साथ मायावती ने अपने युवा भतीजे आकाश को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित करने के साथ ही देश (उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड छोड़) में हाथी की सेहत सुधारने का जिम्मा सौंपा है।

आकाश के सामने बड़ी चुनौती: लोकसभा चुनाव में आकाश के सामने देश के कम से कम 24 राज्यों में जनाधार बढ़ाकर पार्टी के पहले के प्रदर्शन को सुधारने की ही बड़ी चुनौती है। दायित्व मिलने के बाद से आकाश दूसरे राज्यों में सक्रिय भी हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि युवा आकाश के राज्यों में आंबेडकर-कांशीराम के अनुयायियों और मायावती को जानने-मानने वाले खासतौर से दलित समाज के लोगों के बीच जाने से बुजुर्गों से लेकर युवा भी 'नीले झंडे' के नीचे जुटते दिख रहे हैं, जिससे देर-सबेर बसपा के दिन फिर बहुरेंगे।

तीन दशक में लोकसभा चुनावों में बसपा का देश में प्रदर्शन

वर्ष	जीत	मत मिले (% में)
2019	10	3.66
2014	0	4.19
2009	21	6.17
2004	19	5.33
1999	14	4.16
1998	5	4.67
1996	11	4.02
1991	3	1.61
1989	4	2.07

वर्ष 2019 के चुनाव में बसपा का राज्यों में प्रदर्शन (प्रतिशत में)

राज्य	प्राप्त मत
उत्तर प्रदेश	19.26
उत्तराखंड	4.52
हरियाणा	3.65
पंजाब	3.53
मध्य प्रदेश	2.40
छत्तीसगढ़	2.33
बिहार	1.71
चंडीगढ़	1.62
अंडमान-निकोबार	1.21
कर्नाटक	1.18
झारखंड	1.13
दिल्ली	1.09
राजस्थान	1.09

नोट-जम्मू-कश्मीर, दमन द्वीप, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, दादर नगर हवेली, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल व तेलंगाना में बसपा को एक प्रतिशत से कम वोट मिले थे।

इंटरनेट मीडिया इंफ्लूएंसर चुनाव अभियान के नए सितारे

राजीव कुमार • नई दिल्ली

अभी चुनाव की घोषणा भले ही नहीं हुई हो, पर इंटरनेट मीडिया पर चुनाव का रंग चढ़ने लगा है। आम तौर पर हम वाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) व रील पर प्रत्याशियों के वीडियो देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं कि कौन इन वीडियो को बना रहा है और कौन आपके फोन तक इन जानकारियों को पहुंचा रहा है।

आपसे फेसबुक, ट्विटर पर पूछा जाने लगता है कि आपके इलाके के लिए कौन हो सकता है सबसे अच्छा उम्मीदवार। असल में यह सारा काम करते हैं इंटरनेट मीडिया इंफ्लूएंसर, जिनकी इन दिनों भारी मांग दिख रही है। राजनीतिक पार्टियों से लेकर राजनेता तक इन दिनों इन्हें ढूंढ़ रहे हैं। ये पार्टी की बैठकों में बुलाए जा रहे हैं। नेता इन पर लाखों रुपये खर्च करने के लिए तैयार हैं। उन्हें पता है कि इंफ्लूएंसर व इंटरनेट मीडिया का जादू वोटर को उनके पक्ष में कर सकता है। तभी इन दिनों पब्लिक रिलेशन (पीआर) का काम करने वाली कंपनियां इंटरनेट मीडिया का ज्ञान रखने वाले युवाओं को पार्ट टाइम के लिए भर्ती कर रहे हैं। उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर उन्हें प्रत्याशी के पक्ष में अभियान चलाना है। कैसे उन्हें इंटरनेट मीडिया पर नकली अकाउंट बनाना है और नेता के पेज की लाइकिंग कैसे बढ़ाना है।

नेता भी समझ चुके हैं कि चुनाव में इंटरनेट मीडिया से आउट होने पर वे मैदान से आउट हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत में एक अरब से अधिक लोगों के पास मोबाइल फोन है और उतने ही लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इधर, इंटरनेट सस्ता भी हुआ है, जिससे लोगों की उस तक पहुंच बढ़ी है। इसका केवल स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल होने से प्रत्याशियों का खर्च भी कम हो जाता है।

इंफ्लूएंसर अपने फालोअर के हिसाब से लेते हैं रुपये

पीआर कंपनियां भी इंफ्लूएंसर को हायर करती हैं। इंटरनेट मीडिया पर पांच हजार से लेकर एक लाख फालोअर वालों की मांग अधिक है। पांच से 25 हजार फालोअर वाले को स्थानीय स्तर के मुद्दों को उजागर करने के लिए हायर किया जाता है। बताया जाता है फेसबुक व वाट्सएप पर अब इस तरह का अभियान चलाया जा सकता है, पर वोटर को यह पता नहीं होता है कि इसके पीछे क्या कहानी है। नेता के चुनाव क्षेत्र तक ही सीमित रखने को पिनकोड के हिसाब से कंटेंट को बाजार में स्प्रेड (फैलाया) किया जाता है। इंफ्लूएंसर का कोई निर्धारित शुल्क नहीं होता है। अपने फालोअर के हिसाब से रुपये लेते हैं। जो उम्मीदवार इंटरनेट मीडिया पर कम या सक्रिय ही नहीं होते हैं, उनसे अधिक चार्ज किया जाता है।

एक्स फैक्टर

- इंटरनेट मीडिया इंफ्लूएंसर की बढ़ी मांग
- नेता ही नहीं, पार्टियां भी कर रहीं हायर

****

1989 के आम चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उसे महज 197 सीटों पर जीत हासिल हुई। जनता दल 143 सीटों के साथ दूसरे नंबर रही। वी पी सिंह भाजपा और माकपा की मदद से प्रधानमंत्री बने।

न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने दिया त्यागपत्र, भाजपा में होंगे शामिल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

▸ कहा- सात मार्च को भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं

▸ पूर्व न्यायाधीश ने टीएमसी को बताया पूरी तरह भ्रष्ट पार्टी

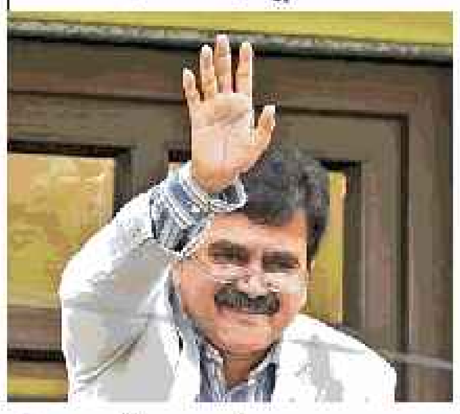
कोलकाता में मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से त्यागपत्र देने के बाद अपने आवास की बालकनी से अभिवादन करते अभिजीत गंगोपाध्याय। प्रेट्र

कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद से त्यागपत्र देने वाले अभिजीत गंगोपाध्याय भाजपा में शामिल होंगे। मंगलवार को कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने खुद इसकी घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं सात मार्च को भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं। इस बारे में गत सात दिनों में उनकी वरिष्ठ भाजपा नेताओं से बात हुई है। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरह भ्रष्ट पार्टी बताया।

अपने फैसलों व टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने मंगलवार को ही अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भेजा है और उसकी प्रतियां प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ एवं कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम को भेजी हैं।

इसलिए भाजपा में होंगे शामिल : मीडिया से मुखातिब गंगोपाध्याय ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि यह पार्टी हाई कमान द्वारा तय किया जाएगा। इस दौरान सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए पूर्व न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने कहा कि तृणमूल के भ्रष्टाचार के खिलाफ एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी भाजपा लड़ रही है, इसलिए मैंने उसमें शामिल होने का फैसला किया है। राजनीति के मैदान में उतरने की टीएमसी की चुनौती ने ही उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। माकपा व कांग्रेस में शामिल नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह ईश्वर पर विश्वास करते हैं जबकि माकपा की विचारधारा में भगवान का अस्तित्व नहीं है। वहीं कांग्रेस जमींदारी व परिवारवादी पार्टी है। इसलिए वह इन दोनों पार्टियों में शामिल नहीं हुए।

तृणमूल पर बोला जोरदार हमला : पूर्व न्यायाधीश ने तृणमूल को पूरी तरह भ्रष्ट पार्टी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल भीतर ही भीतर टूट रही है और जल्द ही बंगाल से खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह 2009 के लोकसभा चुनाव में माकपा का हाल हुआ था वही हाल 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल का होगा। उन्होंने कुछ वरिष्ठ वकीलों से मिले दस्तावेज के आधार पर दावा किया कि बंगाल में सौ दिन रोजगार की योजना (मनरेगा) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। वह आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा करेंगे।

अभिषेक ने रची थी नारद स्टिंग की साजिश : गंगोपाध्याय ने नाम नहीं लेते हुए तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि शाल पत्ते के सिपाही, जिसे कोई-कोई सेनापति (अभिषेक) कहते हैं, ने ही अपने ससुर व टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सदस्य केडी सिंह की कंपनी एलकेमिस्ट के पैसे की मदद से एक पत्रकार (मैथ्यू सैमुअल) के जरिए अपना राजनीतिक मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नारद स्टिंग आपरेशन की साजिश रची थी। उन्होंने दावा किया कि नारद स्टिंग आपरेशन के आरोपित साजिश के शिकार थे।

टीएमसी ने किया पलटवार

वरिष्ठ टीएमसी नेता कुणाल घोष ने गंगोपाध्याय पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने बतौर न्यायाधीश भाजपा का पक्षपात कर टीएमसी सरकार के खिलाफ कई फैसले दिए हैं। इसलिए उन सभी फैसलों को खारिज किया जाना चाहिए। वहीं वरिष्ठ टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पूर्व न्यायाधीश पर व्यक्तिगत हमला करते हुए उन्हें चरित्रहीन व अयोग्य करार दिया।

गुजरात कांग्रेस नेता मोढवाडिया व अंबरीश डेर भाजपा में शामिल

गांधीनगर, प्रेट्र : कांग्रेस की गुजरात इकाई के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस से इस्तीफा देने के एक दिन बाद मंगलवार को पार्टी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अंबरीश डेर के साथ भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा की गुजरात इकाई प्रमुख सीआर पाटिल ने उन्हें पार्टी में उन्हें शामिल किया।

मोढवाडिया और डेर ने अयोध्या में जनवरी में आयोजित भगवान राम मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करने के कांग्रेस के निर्णय पर नाराजगी जताते हुए सोमवार को इस्तीफा दे दिया था। दोनों नेताओं ने गुजरात में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के निर्धारित प्रवेश से ठीक तीन दिन पहले कांग्रेस छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की। मोढवाडिया लगभग 40 वर्षों तक कांग्रेस से जुड़े रहे। उन्होंने विपक्ष के नेता और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। मीडिया से बात करते हुए मोढवाडिया ने कहा कि वह देश के लिए सामाजिक और आर्थिक आजादी हासिल करने के महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों में योगदान देना चाहते हैं।

गुजरात के पूर्व कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया मंगलवार को गांधीनगर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल की उपस्थिति में भाजपा में सम्मिलित हो गए। एएनआइ

वाराणसी के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने थामा भाजपा का हाथ

नई दिल्ली, प्रेट्र : वाराणसी के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। 2004 से 2009 तक वह वाराणसी से कांग्रेस के सांसद थे। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में भाजपा महासचिव अरुण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पार्टी के मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी की मौजूदगी में भाजपा दल की सदस्यता ग्रहण की। वह लंबे समय से कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रहे थे।

भाजपा ने कहा- यह माओवादी विचारधारा, राजा गिरफ्तार किए जाएं

प्रथम पृष्ठ से आगे

जागरण ब्यूरो के अनुसार द्रमुक सांसद राजा के राष्ट्र विरोधी और राम विरोधी बयान को लेकर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत को बदनाम करना, भारतीय संस्कृति को अपमानित करना और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को गाली देना विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए की फितरत और राजनीतिक एजेंडा बन चुका है। उन्होंने कहा कि ए राजा का यह बयान कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, उनकी माओवादी मानसिकता के साथ ही घमंडिया गठबंधन के कुत्सित सोच को भी उजागर करता है। माओवादी मानसिकता वाले लोग ही भाषाओं के आधार पर अलग-अलग राष्ट्रीयता का तर्क देते रहे हैं। भाजपा की आइटी विंग के प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर कहा- 'द्रमुक की ओर से नफरत भरे भाषण लगातार जारी हैं। अब ए राजा ने भारत के विभाजन का आह्वान किया है, राष्ट्र के रूप में भारत की अवधारणा पर सवाल उठाया है। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के साथी चुप हैं।'

नए निजामों को घर बैठाने का संकल्प लीजिए : शाह

गृह मंत्री ने परिवारवाद पर हमला बोला, उद्धव और शरद को घेरा

राज्य ब्यूरो, मुंबई

छत्रपति संभाजी महाराज नगर (पूर्व का औरंगाबाद) में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां के लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में एआइएमआइएम के स्थानीय सांसद को घर बैठाने की अपील की। शाह ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर भी जमकर हमला बोला।

दो दिन के दौरे पर महाराष्ट्र आए शाह ने मंगलवार शाम एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल ने जिस मराठवाड़ा को निजामशाही से मुक्त कराया, आज उसी मराठवाड़ा में मजलिस (आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन) का सांसद है। अब पुनः चुनाव होने जा रहे हैं। समय आ गया है कि आप इन नए निजामों को घर बैठाइए। बता दें कि इस समय छत्रपति संभाजी महाराज नगर से ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम के सांसद इम्तियाज जलील हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में शिवसेना उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे को हराया था। इसी शहर में मुगल शासक औरंगजेब की भी समाधि है। शाह ने कहा कि इसी औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था। जब नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने काशी विश्वनाथ कारिडोर बनवाया। शाह ने कहा- कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बिल लाने के लिए खड़ा हुआ तो 'राहुल बाबा' ने उस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि मत हटाओ, नहीं तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां तो छोड़िए, आज तक वहां किसी की कंकड़ उठाने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। इसी कड़ी में शाह ने सामने बैठे श्रोताओं से पूछा कि क्या जो लोग अनुच्छेद 370 हटाने और छत्रपति संभाजी महाराज नगर के नामकरण का विरोध करते हों, वह क्या बालासाहब ठाकरे के वारिस हो सकते हैं ?

▸ बोले- 370 हटाने पर राहुल ने कहा था कि खून की नदियां बहेंगी, कंकड़ तक नहीं उठा

जालना में भाजपा के युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत छत्रपति शिवाजी महाराज का पोर्टेट भेंट कर किया गया। एएनआइ

शाह ने यह भी कहा

- जो पार्टियां अपने संगठनों के भीतर परिवारवाद को बढ़ावा देती हैं, वे देश के लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर सकती हैं।
- भाजपा के लिए वोट का मतलब भारत के लिए वोट है और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसका मतलब युवाओं के गौरवशाली भविष्य के लिए वोट भी है।
- मोदी की गारंटी है कि आप उन्हें तीसरा कार्यकाल दें और वह देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे।
- भाजपा ने देश से आतंकवाद और नक्सली खतरे को खत्म किया है।
- भाजपा के पास 10 साल का रिपोर्ट कार्ड व अगले 25 साल का विजन है।

कर्नाटक में आतंकियों को प्रोत्साहन और संरक्षण मिल रहा : जेपी नड्डा

चिकोडी, प्रेट्र : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पाकिस्तान समर्थक नारे के मुद्दे पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। नड्डा ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए मंगलवार को सवाल किया कि क्या वे पाकिस्तान की भाषा बोलने के लिए पार्टी चला रहे हैं और क्या वे भारत में पड़ोसी देश के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कर्नाटक में कुछ भी मुफ्त उपलब्ध है तो वह आतंकवाद है, आतंकवादियों को प्रोत्साहन और संरक्षण मिल रहा है।

नड्डा ने बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए हैं, लेकिन अब तक आपको और कर्नाटक की जनता को भी यह एहसास हो गया होगा कि जिस सरकार को उन्होंने चुना है वह उन्हें धोखा दे रही है और उन्हें गुमराह कर रही है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कैसी स्थिति आ गई है, विधान सौध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री मूकदर्शक बने हुए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए नड्डा ने पूछा, 'क्या आप इस तरह से भारत को एकजुट कर रहे हैं? आपका सांसद चुनाव जीतता है और उसकी जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। उन्होंने सिद्दरमैया, शिवकुमार, खरगे और राहुल की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? गौरतलब है कि कांग्रेस नेता सैयद नासिर हुसैन के समर्थकों ने 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में जीत पर विधान सौध में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए।

▸ नड्डा ने पाक समर्थक नारे के लिए कांग्रेस सरकार पर हमला किया

▸ भाजपा अध्यक्ष ने पूछा, इस मुद्दे पर खरगे, राहुल, सिद्दरमैया चुप क्यों हैं

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के बेलगावी में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। एएनआइ

'मोदी चाहते हैं आप मोबाइल देखो, जय श्रीराम बोलो व भूखे मर जाओ'

▸ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के सामने मोदी-मोदी के नारे लगाए

▸ एक युवक ने राहुल को भेंट किया आलू, कहा सोना दीजिए

▸ महाकाल दर्शन के बाद राहुल ने उज्जैन में किया रोड शो

राहुल गांधी ने मंगलवार को उज्जैन स्थित भगवान महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की। मप्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ भी उपस्थित रहे। एएनआइ

नईदुनिया, उज्जैन

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार को मप्र के शाजापुर और उज्जैन पहुंची। शाजापुर में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने बेरोजगारी का मुद्दा छेड़ा। कहा कि आज के कई युवा मोबाइल में व्यस्त हैं, रील देखते रहते हैं। ये मोबाइल चीन में बने हैं। हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चीन का माल यहां बेचा है। फायदा चीन के युवाओं को हुआ। मोदी चाहते हैं कि आप दिनभर मोबाइल देखो, जय श्रीराम कहो और कोई काम-धंधा न करो। भूखे मर जाओ। राहुल की यात्रा के दौरान कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी-मोदी के नारे लगाए। यह सुनकर राहुल उनके पास पहुंच गए। राहुल ने नारा लगा रहे एक युवक को टाफी दी तो एक ने उन्हें आलू दिया और कहा सोना दीजिए। इस पर राहुल मुस्कराए, बोले अगली बार सोना लेकर आऊंगा।

उज्जैन पहुंचने पर राहुल ने महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर पूजन किया। शिवरात्र होने के कारण राहुल ने गर्भगृह के द्वार से ही भगवान के दर्शन किए और नंदी हाल में बैठकर ध्यान लगाया। पुजारियों ने रुद्राक्ष की माला, पटका व पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। उनके साथ कमल नाथ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे।

सिंधिया को घेरे बगैर ही ग्वालियर-चंबल अंचल से निकल गए राहुल

जोगेंद्र सेन, ग्वालियर : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में पांच में से दो दिन ग्वालियर-चंबल में रही। यहां राहुल ने अंचल के बड़े नेता व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। यही नहीं उन्हें लेकर पूछे गए सवाल से भी किनारा कर लिया। वह सिर्फ पीएम मोदी व अदाणी पर ही हमलावर रहे। जबकि इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा जब इस अंचल में आई थीं तो उनके निशाने पर सिंधिया थे। ऐसे में कयास लगाया जा रहा था कि राहुल भी सिंधिया की घेराबंदी करेंगे लेकिन उन्होंने सिंधिया का नाम तक नहीं लिया। बता दें कि कमल नाथ की तत्कालीन सरकार गिराने में सिंधिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सिंधिया अपने समर्थित विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। कांग्रेस इस घटनाक्रम को भूल नहीं पाती। कमोवेश हर मौके पर इस घटना का जिक्र कर सिंधिया को गद्दार बताने से कांग्रेसी चूकते नहीं हैं। न्याय यात्रा ग्वालियर-अंचल से निकलकर मालवा-निमाड़ में प्रवेश कर गई है। यह न्याय यात्रा अपने पीछे कई राजनीतिक सवाल भी छोड़ गई है। राहुल गांधी यात्रा के दौरान मोदी सरकार की नीतियों व अदाणी पर हमला बोल रहे हैं लेकिन स्थानीय मुद्दों और नेताओं को छू तक नहीं रहे हैं।

कमल नाथ के गढ़ में लगाए गए भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर

छिंदवाड़ा, नईदुनिया : मप्र में कमल नाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। महाशिवरात्र के त्योहार को लेकर लगाए गए पोस्टर में कमल नाथ को भावी मुख्यमंत्री लिखा गया है। इस पोस्टर में उनके पुत्र व सांसद नकुल नाथ का भी चित्र लगा है। बता दें कि पिछले दिनों कमल नाथ व उनके पुत्र नकुल नाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें थीं। बाद में कमल नाथ ने खुद इसका खंडन किया था।

तृणमूल विधायक के बिगड़े बोल, कहा-अपवित्र है राम मंदिर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

▸ सुवेंदु ने की निंदा की, कहा- विधायक के खिलाफ दर्ज कराई एफआइआर

रामेंदु सिन्हाराय। फाइल

कहा- ऐसे घृणित बयान से दुनिया भर के हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है

बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक रामेंदु सिन्हा राय ने अयोध्या में नव्य-भव्य राम मंदिर को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की है। उन्होंने राम मंदिर को अपवित्र व दिखावटी बताते हुए यहां तक कहा कि किसी भी हिंदू को ऐसे अपवित्र स्थल पर पूजा करने नहीं जाना चाहिए। तृणमूल विधायक की इस टिप्पणी की बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने कड़ी निंदा की है। भाजपा नेता ने तृणमूल विधायक के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज कराई गई है। विधायक की टिप्पणी पर टीएमसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

हुगली जिले के तारकेश्वर से विधायक राय का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह कह रहे हैं, मेरे हिसाब से यह एक अपवित्र जगह है, जहां सबकुछ दिखावटी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ब्राह्मण मंदिरों में भगवान की पूजा करते हैं। इमाम मस्जिद में सभी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। फिर पीएम मोदी बिना ब्राह्मण हुए भी कैसे प्राण प्रतिष्ठा की। उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर को इतना निचले स्तर पर पहुंचा दिया गया है। वहां मंदिर नहीं, शो-पीस बनाया गया है।

सुवेंदु ने कहा-यही है तृणमूल का असली चरित्र : सुवेंदु ने एक्स हैंडल पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, मैं न केवल उनके इस अपमानजनक बयान की कड़ी निंदा करता हूं, बल्कि ऐसे घृणित बयान से दुनिया भर के हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

शिअद (संयुक्त) का शिअद में हुआ विलय

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

राजनीतिक हाशिये पर चल रहे शिरोमणि अकाली दल (शिअद) को मंगलवार को बड़ी सफलता मिली। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी से नाराज होकर अपनी अलग पार्टी शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) बनाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा अपने पुत्र व पूर्व वित्तमंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा और समर्थकों समेत वापस शिअद में आ गए। उन्होंने अपनी पार्टी का भी शिअद में विलय कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के विलय से इस बात को मजबूती मिली है कि जल्द ही शिअद और भाजपा में भी गठबंधन की घोषणा हो सकती है। इसका एक कारण यह भी है कि शिअद से विलय से पहले ढींडसा की पार्टी का भाजपा से गठबंधन था। हालांकि, इस दौरान शिअद अध्यक्ष सुखबीर भाजपा के साथ गठबंधन के सवालों को टाल गए।

ढींढसा परिवार को पार्टी में शामिल करवाने के लिए सुखबीर खुद उनके चंडीगढ़ स्थित निवास स्थान पर पहुंचे। सुखदेव ढींढसा ने भी सारे गिले-शिकवे को भुलाकर सुखबीर को गले लगाया। उन्होंने ढींढसा को शिअद का संरक्षक बनने का न्योता दिया। ढींढसा परिवार का पार्टी में स्वागत करते हुए सुखबीर ने कहा कि जो लोग भी पार्टी छोड़ कर गए हैं, वह वापस आ जाएं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। पंजाब के लिए अब शिअद को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि शिअद ही है जो राज्य और पंथ की सेवा करता है। उन्होंने एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर से भी पार्टी में लौटने का आग्रह किया। वहीं, मुख्यमंत्री मान पर बरसते हुए सुखबीर ने कहा कि उन्हें न तो विधानसभा की रीतियों का पता है और न ही तरीकों का। मान को पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पुराने वीडियो को देखकर सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट में कुछ भी नहीं है। महिलाओं को एक हजार और किसानों व खेत मजदूरों को फसल नुकसान का मुआवजा देने का वादा पूरा नहीं किया।

▸ सुखबीर बादल पहुंचे सुखदेव ढींढसा के घर, पार्टी का संरक्षक बनने का न्योता दिया

▸ ढींडसा ने सुखबीर को बताया बेटा, कहा- किसी कारण से हो गया था मतभेद

▸ पंजाब में भाजपा से गठबंधन को लेकर सवालों को टाल गए शिअद अध्यक्ष

गिले-शिकवे दूर : शिअद अध्यक्ष सुखबीर बादल पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा से मिलते हुए। ढींढसा परिवार शिअद में शामिल हो गया। जागरण

स्थानीय जुड़ाव

नाम के साथ तमिल, बांग्ला, पंजाबी आदि लिखकर राज्यों के लिए बनाए अलग एक्स हैंडल, पूरे देश को परिवार बताने वाले प्रधानमंत्री का चुनौती वाले राज्यों में भावनात्मक संदेश

अब नरेन्द्र मोदी 'तमिल', 'बांग्ला' और 'पंजाबी' भी

जितेंद्र शर्मा, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। फाइल

गुजरात से आकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी को अपना चुनावी केंद्र बना चुके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के हर राज्य से अपना भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करने का प्रयास हमेशा करते दिखाई देते हैं। 140 करोड़ देशवासियों को 'मेरे परिवारजन' कहकर संबोधित करने वाले पीएम मोदी की नजर फिलहाल चुनौती वाले प्रमुख राज्यों पर है। यह उनका लोकल कनेक्ट का ही दांव माना जा सकता है कि तमिलनाडु, बंगाल, पंजाब, ओडिशा आदि राज्यों के आमजन को संदेश देने के लिए उन्होंने अपने नाम से स्थानीय भाव जोड़ते हुए अपने नाम के साथ मिल, बांग्ला, ओडिया, कन्नड, पंजाबी, तेलुगु, मराठी और मलयालम लिखते हुए अलग-अलग आठ एक्स हैंडल बनाए हैं। एआइ की मदद से उनके भाषण संबंधित भाषा में ही सुने जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी तकनीक का इस्तेमाल जानते हैं। 2014 में उन्होंने 3डी संबोधन शुरू किया था, जिसमें अलग-अलग स्थानों पर उनके भाषण टीवी पर कुछ इस तरह दिखाए जाते थे जैसे वे सामने खड़े होकर बोल रहे हों। अब नया प्रयोग दिखाई दिया है। अभी हाल ही में उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अलग-अलग वैरिफाइड अकाउंड बनाए हैं। इनमें 'नरेन्द्र मोदी तमिल', 'नरेन्द्र मोदी बांग्ला', 'नरेन्द्र मोदी ओडिया', 'नरेन्द्र मोदी पंजाबी', 'नरेन्द्र मोदी कन्नड', 'नरेन्द्र मोदी तेलुगु', 'नरेन्द्र मोदी मराठी' और 'नरेन्द्र मोदी मलयालम' नाम रखा है। इन एक्स हैंडलों पर उन राज्यों से संबंधित प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों व संबोधनों को अपलोड किया गया है।

इन राज्यों के लिए पीएम के प्रयोग के भी राजनीतिक निहितार्थ हैं। दरअसल, यह विपक्षी दलों के मजबूत गढ़ हैं, जिन पर भाजपा की नजर है। पार्टी वहां लगातार मेहनत भी कर रही है। दरअसल, तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 2019 के आम चुनाव में भाजपा प्रचंड मोदी लहर के बावजूद इनमें से कोई सीट नहीं जीत पाई थी। फिर दक्षिण के इस राज्य से भावनात्मक-सांस्कृतिक रिश्तों में नया मर्म भरने के लिए ही प्रधानमंत्री ने काशी-तमिल संगमम कार्यक्रम शुरू किया। इस राज्य से जुड़े सांस्कृतिक आध्यात्मिक प्रतीक सेंगोल को नई संसद में स्थापित कराया।

कई दौरे दक्षिण के राज्यों में किए। इसी तरह बंगाल को लेकर भी पीएम और पार्टी लगातार प्रयासरत है। बंगाल की एक-एक घटना को मजबूती से उठाया जाता है। संदेशखाली की ताजा घटना के बाद हाल ही में प्रधानमंत्री बंगाल गए और जनसभा की। वहां भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें जीत पाई थी। इस बार भाजपा 370 से अधिक सीटों का लक्ष्य पूरा करने के लिए बंगाल में भी बढ़त चाहती है। ओडिशा की कुल 21 में से भाजपा आठ जीत सकी। केरल की 20 सीटों पर भाजपा का खाता तक नहीं खुला और 13 सीटों वाले पंजाब में चुनौतियां हैं।

उल्लेखनीय है कि हाल में राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर परिवार को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। इसके बाद से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से 'मोदी का परिवार' अपने नाम के साथ लिखकर अभियान छेड़ दिया गया है। माना जा रहा है कि इस चुनाव में परिवारवाद पर भाजपा अभी और मुखर होगी और इसे प्रमुख चुनावी मुद्दों के रूप में उछालने का प्रयास करेगी। पीएम मोदी इस प्रयोग से यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए सारा देश ही परिवार है।

इन भाषाओं का कई राज्यों में प्रभाव : प्रधानमंत्री मोदी ने जिन भाषाओं में अपने एक्स हैंडल बनाए हैं, उनका कई राज्यों में प्रभाव है। मसलन, आंध्र में तेलुगु और तमिल दोनों भाषा बोलने वाले नागरिक हैं। बांग्ला भाषी बंगाल के साथ असम व पूर्वोत्तर के कुछ अन्य राज्यों में भी हैं। ओडिया भाषा बोलने वाले ओडिशा के साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी हैं।

एआइ के माध्यम से होगा भाषणों का ट्रांसलेशन

भाजपा आइटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने बताया कि इन आठ एक्स हैंडल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण आठ भाषाओं में ट्रांसलेट होंगे। उनके भाषणों की यह डबिंग आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से होगी। उनका दावा है कि इस तरह का प्रयोग करने वाली भाजपा विश्व की पहली पार्टी है।

मायावती ने मिलाया केसीआर से हाथ

मायावती। फाइल

के चंद्रशेखर। फाइल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव में उप्र में भाजपा और कांग्रेस-समाजवादी पार्टी (सपा) से समान दूरी बनाकर चल रहीं मायावती ने तेलंगाना में पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की पार्टी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) से हाथ मिला लिया है। हैदराबाद में मंगलवार को केसीआर की उपस्थिति में बीआरएस ने बसपा के साथ गठबंधन की घोषणा की। इसके बाद केसीआर ने प्रवीण कुमार के साथ प्रेस कान्फ्रेंस भी किया। केसीआर ने कहा कि बसपा व बीआरएस मिलकर संसदीय चुनाव लड़ेंगे। मायावती से बात कर दोनों दल सीटों के बंटवारे पर सहमति भी बना लेंगे।

38,504 लाभार्थियों के बीच 1083 करोड़ की राशि का किया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के छपरा में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में। इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए।

न्यूज गैलरी

स्मृति इरानी ने राहुल गांधी को दी बहस की चुनौती

नागपुर : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संप्रग शासन के 10 वर्षों और नरेन्द्र मोदी सरकार के बीच अंतर पर बहस करने की चुनौती दी है। नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो युवा महा सम्मेलन में स्मृति इरानी ने कहा कि अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंच रही है तो उन्हें कान खोलकर सुन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वह इस बारे में राहुल गांधी से चर्चा करने के लिए कहेंगी तो वह नहीं आएंगे। वह भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। (एएनआइ)

सीएए पर प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा

गुवाहाटी : असम की विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा है। प्रधानमंत्री इसी सप्ताह राज्य का दौरा करेंगे। विपक्षी दल प्रधानमंत्री से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को लेकर अस्थिरता उत्पन्न होने की आशंका पर चर्चा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की अनुमति मांगने वाला पत्र भेजा है। (प्रेट्र)

मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है : जरांगे

छत्रपति संभाजीनगर : मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि वह भाजपा की राह में कांटा हैं। दावा किया कि उनके खिलाफ एसआइटी जांच रिपोर्ट तैयार है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विगत सप्ताह सरकार को एक एसआइटी गठित करने और जरांगे द्वारा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणी की जांच का निर्देश दिया था। (प्रेट्र)

राहुल गांधी को समन जारी करेगी असम पुलिस : हिमंत

गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि गुवाहाटी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हिंसा को लेकर राज्य पुलिस कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी करेगी। उन्होंने कहा कि राहुल को पुलिस के समक्ष पेश होना होगा। हिमंत ने कहा, राहुल गांधी के पास समन भेजा जाएगा। उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद पेश होना होगा। (प्रेट्र)

चुनावी बांड पर एसबीआइ के रुख से भड़की कांग्रेस

नई दिल्ली : चुनावी बांड के विवरण का ब्योरा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जून तक का समय मांगने के भारतीय स्टेट बैंक के कदम को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव में मोदी सरकार अपने 'संदिग्ध लेन-देन' को छिपाने के लिए सबसे बड़े सरकारी बैंक को ढाल बना रही है। (जाब्यू)

मोदी बोले, युवाओं को बढ़ावा देने से डरती है कांग्रेस

कहा, परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ मैंने उठाई है आवाज

कांग्रेस में 50 साल का आदमी आगे बढ़ेगा, तो परिवार का क्या होगा

सांगारेड्डी (तेलंगाना), प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह युवा नेताओं को बढ़ावा देने से डरती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी अब 75-80 साल से अधिक उम्र के लोगों को नियुक्त कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि परिवारवादी पार्टियां उन्हें निशाना बना रही हैं, क्योंकि वह उनके हजारों करोड़ रुपये के घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं।

मोदी ने भाजपा की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कभी कोई निजी हमला नहीं किया, बल्कि परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके दोस्त अब उन्हें और उनके जनता रूपी 'परिवार' को गाली दे रहे हैं, क्योंकि वह लोगों को दी गई गारंटी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पीएम ने कहा, जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और युवाओं को नए अवसर नहीं देता है तो वे इसका जवाब नहीं देते हैं। लेकिन कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। पीएम ने कहा, कांग्रेस पहले वंशवादी नहीं थी। यह 50 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बढ़ावा नहीं देती है। यदि उसे किसी को नियुक्त करना है तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो 75-80 वर्ष का हो, 85 वर्ष का हो। उसे डर है कि अगर 50 साल का आदमी आकर आगे बढ़ जाता है तो परिवार का क्या होगा।

ओडिशा के जाजपुर जिले में मंगलवार को चंडीखोल में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रेट्र

पीएम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक जहां-जहां परिवार संचालित पार्टियां शासन कर रही हैं, वे राज्य बर्बाद हो गए हैं। वे परिवार जरूर मजबूत हुए हैं, लेकिन राज्य नहीं। उन्होंने जनता से सवाल किया, क्या इन परिवार द्वारा संचालित राजनीति को जारी रहने दिया जाना चाहिए? उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार द्वारा संचालित ऐसी पार्टियां लोकतंत्र विरोधी, प्रतिभा विरोधी और युवा विरोधी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वह वंशवादी राजनीति की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है।

तेलंगाना में 7,200 करोड़ की परियोजनाएं शुरू कीं : प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को सांगारेड्डी में 7,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तेलंगाना के लिए प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि वह इस भावना के साथ काम करते हैं कि राज्यों का विकास ही देश का विकास है। पीएम ने कहा कि विकसित भारत के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा होना आवश्यक है। इसलिए केंद्र ने बजट में बुनियादी ढांचे के लिए 11 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

कोलकाता में नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा का उद्घाटन आज

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- पीएम कोलकाता में करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास
- बारासात में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम

कोलकाता में देश के पहले अंडरवाटर मेट्रो ट्रेन का रूट। प्रेट्र

लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को फिर बंगाल का दौरा करेंगे। पीएम सुबह में कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपये की मेट्रो से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हुगली (गंगा) नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली बहुप्रतीक्षित मेट्रो सेवा सहित कोलकाता मेट्रो की तीन परियोजनाएं शामिल हैं, जिसका पीएम उद्घाटन करेंगे। 4.8 किलोमीटर लंबी हावड़ा मैदान-एस्प्लेनेड मेट्रो खंड देश की पहली ऐसी मेट्रो परियोजना हैं, जिसमें हुगली के नीचे दो सुरंगे (टनल) तैयार की गई है। नदी के नीचे से मेट्रो दौड़ेगी। परिचालन शुरू होने के बाद हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन भी बन जाएगा।

पीएम इसके बाद उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले पीएम की बारासात रैली को राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना चाहती है, जो आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मद्देनजर मुख्य रूप से महिलाओं पर केंद्रित होगी। बारासात में प्रधानमंत्री के भाषण का देशभर में भाजपा के सभी मंडलों में सीधा प्रसारण भी किया जाएगा और विशेष रूप से महिला मोर्चा की कार्यकर्ता व समर्थक इसे देखेंगी। माना जा रहा है कि इस सभा से पीएम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं से अत्याचार के मुद्दे पर फिर से बोलेंगे, जो देशभर में चर्चा में है।

चार दिनों में दूसरी बार पीएम का बंगाल दौरा : लोकसभा चुनाव से पहले चार दिनों के भीतर पीएम का यह दूसरा बंगाल दौरा होगा। इससे पहले एक व दो मार्च को दो दिवसीय बंगाल दौरे में पीएम ने राज्य में 22,000 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया था और दो जनसभाओं को संबोधित किया था।

राज्य के मंत्री सुजीत बोस से पूछा दीदी कैसी हैं : पीएम के स्वागत के लिए राज्य के मंत्री सुजीत बोस एयरपोर्ट पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री एक आधिकारिक दौरे पर पहुंचे हैं, इसलिए प्रोटोकाल का पालन करते हुए उनका स्वागत के लिए राज्य के मंत्री पहुंचे थे। पीएम मोदी ने सुजीत बोस से पूछा कि ममता दीदी कैसी हैं।

रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष को देखने अस्पताल पहुंचे पीएम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बंगाल में बुधवार को प्रस्तावित कार्यक्रम व सभा के लिए मंगलवार शाम कोलकाता पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद वह सीधे दक्षिण कोलकाता के स्थित शिशु मंगल अस्पताल पहुंचे जहां पिछले कई दिनों से रामकृष्ण मिशन एवं मठ के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद जी महाराज भर्ती हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने महाराज के बारे में जानकारी ली। इससे पहले रामकृष्ण मिशन व मठ के अध्यक्ष स्वामी आत्मस्थानंद जी महाराज मई 2015 में जब कोलकाता के अस्पताल में भर्ती थे तो पीएम मोदी उन्हें भी देखने के लिए पहुंचे थे।

हरियाणा की सीमा खुलते ही ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ करेंगे दिल्ली कूच : डल्लेवाल

जासं, पटियाला : संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि पंजाब के किसान मांगें पूरी न होने पर हरियाणा की सीमा खुलते ही ट्रैक्टर-ट्रालियों में दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि बुधवार को मोर्चा से जुड़े अन्य राज्यों के किसान बिना ट्रैक्टर-ट्राली के दिल्ली के जंतर-मंतर पर इकट्ठा होंगे। इसके बाद देखा जाएगा कि किसानों के बारे में केंद्र सरकार की क्या नीति होती है। अभी पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बार्डर पर रुककर ही अपना संघर्ष जारी रखेंगे, क्योंकि क्योंकि केंद्र सरकार ने उन्हें ट्रैक्टर-ट्रालियां लेकर आने से मना किया हुआ है। डल्लेवाल ने साफ किया कि उनका उद्देश्य दिल्ली कूच नहीं, बल्कि किसानों की मांगों को मनवाना है। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि सर्दी के इस मौसम में किसानों के लिए दिल्ली की सड़कों पर रहना मुश्किल होगा।

योगी मंत्रिमंडल में राजभर सहित चार बनाए गए कैबिनेट मंत्री

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल का पहला विस्तार
- राज्यपाल ने चारों को राजभवन में दिलाई मंत्री पद की शपथ

लखनऊ में मंगलवार को राजभवन में आयोजित समारोह में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सुनील कुमार शर्मा (बाएं), अनिल कुमार (बाएं से दूसरे), दारा सिंह चौहान (दाएं) तथा ओम प्रकाश राजभर (दाएं से दूसरे) के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रेट्र

योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार में मंगलवार को चार नए कैबिनेट मंत्रियों को जगह दी गई। लंबे समय से मंत्रिमंडल में अपनी सीट कंफर्म होने के लिए प्रतीक्षारत सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर व भाजपा एमएलसी दारा सिंह चौहान का इंतजार खत्म हो गया है तो मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से रालोद विधायक अनिल कुमार और गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से भाजपा विधायक सुनील कुमार शर्मा को भी शपथ दिलाई गई है। राजभवन के गांधी सभागार में शाम पांच बजे शुरू हुए शपथग्रहण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चारों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है। वहीं कुल मंत्रियों की संख्या 56 हो गई है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल का यह पहला विस्तार है। शपथ ग्रहण के बाद इंटरनेट मीडिया एक्स पर बधाई संदेश पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी ने लिखा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

राजभर और चौहान को योगी सरकार में दोबारा मिली जगह : बसपा के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को योगी सरकार में दोबारा जगह मिली है। दोनों योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री थे। विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ने सपा का हाथ पकड़ लिया था, लेकिन अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद वापस भाजपा खेमे में आ गए।

रालोद को एनडीए में शामिल होने का इनाम : हाल ही में रालोद के एनडीए में शामिल होने पर भाजपा ने उसे बिजनौर और बागपत की लोकसभा सीटें दीं, वहीं उसके एक विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जाटव बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अनिल कुमार को मंत्री बनवा कर जयन्त चौधरी ने जाट आधारित पार्टी के सामाजिक समीकरण को व्यापक बनाने की कोशिश की है।

रिकार्ड जीत वाले सुनील शर्मा के जरिये चला ब्राह्मण कार्ड : भाजपा ने गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से तीसरी और लगातार दूसरी बार विधायक बने सुनील कुमार शर्मा को मंत्री बनाकर ब्राह्मण कार्ड चलने के साथ पिछड़ों और दलितों के अलावा अगड़ों को भी साधने की कोशिश की है। पिछले विधानसभा चुनाव में रिकार्ड 2,14,835 मतों से जीत दर्ज कराने वाले शर्मा को मंत्री पद देकर भाजपा ने यह भी साबित किया है कि वह सिर्फ दूसरे दलों से आने वाले को ही नहीं सरकार में जगह देती है, अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखती है।

स्कूल आफ हैप्पीनेस व ब्रिलिएंस से रखेंगे शिक्षित पंजाब की नींव

इन्द्रप्रीत सिंह,चंडीगढ़ : वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा की ओर से मंगलवार को पेश किए गए 2.04 लाख करोड़ के बजट में शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। खास बात यह है कि इस बजट में सरकार का पूरा जोर शिक्षित पंजाब की तरफ रहा। इसी कारण वित्त मंत्री ने दस करोड़ रुपये की लागत से 100 प्राइमरी स्कूलों को 'स्कूल आफ हैप्पीनेस' और 100 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को 'स्कूल आफ ब्रिलियंस' में बदलने, 118 स्कूल आफ एमिनेंस खोलने और छात्रों में तकनीकी विकास के लिए स्कूल आफ एप्लाइड लर्निंग स्थापित करने की घोषणा की। 'मिशन समरथ' शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है। इसी तरह कालेजों के लिए आगामी वित्त वर्ष के लिए 1425 करोड़ रुपये के बजट का प्रविधान किया गया है। आम आदमी क्लीनिक खोलने व मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान 1,133 करोड़ का प्रविधान किया गया है।

पेपर लीक के बाद हटाई गईं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- डीजी विजिलेंस राजीव कृष्ण को सौंपा गया प्रभार
- भर्ती बोर्ड की ओर से अब तक कोई एफआइआर नहीं कराई गई है दर्ज

रेणुका मिश्रा। फाइल

उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में शासन ने कड़ा कदम उठाया है। पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष डीजी रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है। उन्हें प्रतीक्षारत रखा गया है। डीजी सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) राजीव कृष्ण को अध्यक्ष/ डीजी भर्ती बोर्ड का भी प्रभार सौंपा गया है। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 17 व 18 फरवरी को दो-दो पालियों में हुई थी।

पेपर लीक मामले में भर्ती बोर्ड की आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। मामले में एडीजी (भर्ती बोर्ड) अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई गई थी और अभ्यर्थियों से पेपर लीक के साक्ष्य मांगे गए थे। भर्ती बोर्ड की ओर से अब तक मामले में दोषियों के विरुद्ध कोई एफआइआर भी नहीं दर्ज कराई गई है। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला था। शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर रद करने के साथ ही पूरे मामले की जांच एसटीएफ से कराने का निर्णय किया था। इसके साथ ही छह माह के भीतर दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया था।

एडीजी ने की परीक्षा निरस्त कराने की अपील

प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मंगलवार को एसओजी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अतिरिक्त महानिदेशक सहित अन्य अधिकारियों से पर्चे लीक व डमी अभ्यर्थी परीक्षा में बिठाने सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। मीणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरे पास ऐसे कई दस्तावेज हैं, जिससे साफ होता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में किन-किन लोगों ने पर्चे लीक करने में सहयोग किया था। अतिरिक्त महानिदेशक ने मीणा से कहा, आप सरकार में हैं, परीक्षा रद करने को लेकर प्रयास करें। मीणा ने कहा, फर्जीवाड़े में पास होने वालों की संख्या 250 से अधिक हो सकती है। फर्जीवाड़े में भर्ती हुए लोगों को बर्खास्त कर के नई भर्ती निकाली जानी चाहिए। मीणा ने कहा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) भर्ती परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि आरएएस परीक्षा में टापर को 200 में से 155 अंक मिले, वहीं लीक हुए पर्चे से पास होने वाले एक परीक्षार्थी शिवा शर्मा को 145 अंक मिले हैं। उन्होंने कहा कि शिवा ने कई सवालों के उत्तर ही नहीं लिखे थे, लेकिन बाद में आयोग में फर्जीवाड़े से उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख दिए गए।

महिला के स्थान पर पुरुष ने परीक्षा दी थी : मीणा ने दावा किया कि एक महिला परीक्षार्थी के स्थान पर पुरुष ने परीक्षा दी थी। महिला का चयन हो गया, वह अभी आरपीए में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। कांग्रेस सरकार में 50 प्रतिशत परीक्षाओं में फर्जी लोगों का चयन हुआ है।

'पारदर्शी बनाने वाली योजना तैयार कर रही कांग्रेस'

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ठोस योजना तैयार कर रही है। राहुल ने उत्तर प्रदेश में हुई पेपर लीक की हालिया घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया, पेपर लीक उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है। पिछले सात वर्षों में 70 से अधिक पेपर लीक के मामलों ने दो करोड़ से अधिक छात्रों का सपना तोड़ा है। लापरवाह सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, नकल माफिया और निजी प्रिंटिंग प्रेसों के आपराधिक गठजोड़ को खत्म कर हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, जब मैंने छात्रों से बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया कि पेपर लीक की तीन मुख्य वजह हैं। बिका हुआ सरकारी तंत्र, निजी प्रिंटिंग प्रेस और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। सभी से मिले सुझावों को मिला कर कांग्रेस युवाओं की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ठोस योजना तैयार कर रही है। बहुत जल्द हम आपके सामने अपना विजन रखेंगे। हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे! युवाओं का भविष्य गठबंधन की प्राथमिकता है।

श्रीनाथ वीर म्हस्कोबा त्योहार

पुणे से लगभग 50 किमी. दूर वीर गांव में मंगलवार को श्रीनाथ वीर म्हस्कोबा त्योहार के उल्लास के दौरान लाल रंग में सराबोर श्रद्धालु। यह त्योहार भगवान शिव के श्रीनाथ वीर म्हस्कोबा अवतार एवं उनके विवाह का उत्सव है। माघ पूर्णिमा के दौरान आयोजित यह उत्सव 10 दिन चलता है। प्रेट्र

उत्तराखंड के भाजपा विधायक का निगम में हंगामा, नगर आयुक्त से अभद्रता

जागरण संवाददाता, देहरादून

- परिचित की कंपनी का टेंडर निरस्त होने पर नगर निगम पहुंचे थे सल्ट विधायक महेश जीना
- नगर आयुक्त के साथ अभद्रता के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए निगम कर्मचारी

उत्तराखंड में सहस्रधारा रोड पर नगर निगम के पुराने ट्रेंचिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण का टेंडर परिचित को न मिलने से नाराज सल्ट (अल्मोड़ा) से भाजपा विधायक महेश जीना ने मंगलवार शाम देहरादून नगर निगम में जमकर हंगामा किया।

उन्होंने नगर आयुक्त (आइएएस) गौरव कुमार के कार्यालय में घुसकर उनसे गालीगलौज करते हुए अभद्रता की। विधायक ने नगर आयुक्त पर टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विधायक के दुर्व्यवहार पर नगर आयुक्त का पारा भी चढ़ गया और उन्होंने इस्तीफा देने की भी बात कह डाली। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम के समस्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। देहरादून में सहस्रधारा रोड पर नगर निगम का पुराना ट्रेंचिंग ग्राउंड है। जिसे दिसंबर-2027 में बंद कर दिया गया था। हालांकि, वहां लाखों मीट्रिक टन कचरा अभी भी जमा है। इस कूड़े के निस्तारण के लिए नगर निगम ने करीब 28 करोड़ रुपये के कार्य का टेंडर पिछले दिनों निकाला था। इस मामले में सल्ट विधायक महेश जीना का कहना है कि मेरे परिचित की कंपनी को अयोग्य क्यों करार दिया गया, मैं इसका पता करने गया था। वहां सरकारी कर्मचारियों की कुर्सी पर उसी निजी कंपनी का कर्मचारी बैठा हुआ था, जिसे टेंडर मिला है। जब मैं नगर आयुक्त से टेंडर से संबंधित जानकारी लेने गया तो नगर आयुक्त ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। हम सत्ताधारी दल के विधायक हैं और यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के धन का कहीं भी दुरुपयोग न हो। कुछ विपक्षी मुझे बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे कि जिस कंपनी के लिए मैं नगर निगम गया था, वह मेरे बेटे की है। मेरे बेटे का कंपनी से कोई भी लेना-देना नहीं है।

उलझा मामला

प्रकाश आंबेडकर ने अपने दल के लिए 27 सीटों की लंबी-चौड़ी सूची एमवीए नेताओं को सौंपी, महायुति में यह मसला दो दिन के महाराष्ट्र दौरे पर आए अमित शाह सुलझाने वाले हैं

महाराष्ट्र के दोनों गठबंधनों में सीटों के लिए खींचतान

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

आगामी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के दोनों बड़े गठबंधन सत्तारूढ़ महायुति एवं महाविकास आघाड़ी (एमवीए) के घटक दलों में अधिकतम सीटें पाने की खींचतान जारी है। महायुति में यह मसला दो दिन के महाराष्ट्र दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुलझाने वाले हैं, तो एमवीए में शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को राकांपा संस्थापक शरद पवार के घर जाकर इस मुद्दे पर करीब डेढ़ घंटे बैठक की।

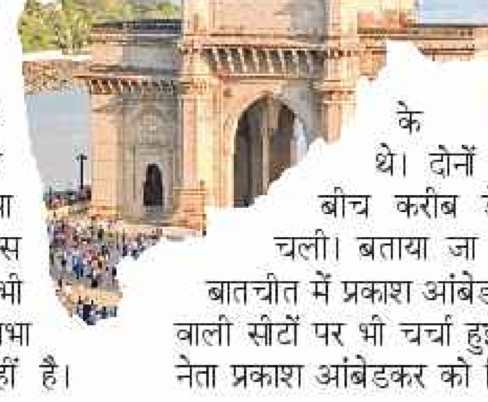

सत्तारूढ़ महायुति में सबसे बड़े दल भाजपा के साथ शिवसेना (शिंदे गुट) एवं राकांपा (अजीत गुट) शामिल है। इस गठबंधन में शामिल तो और भी कई दल हैं लेकिन, लोकसभा चुनाव में उनकी दावेदारी नहीं है। लेकिन, एमवीए में कांग्रेस, राकांपा शरदचंद्र पवार एवं शिवसेना (यूबीटी) के अलावा प्रकाश आंबेडकर, किसान नेता राजू शेट्टी और कोल्हापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज साहू जी भी कतार में हैं।

प्रकाश आंबेडकर ने तो अपने दल के लिए 27 सीटों की लंबी-चौड़ी सूची एमवीए नेताओं को सौंप दी है। स्वयं उद्धव ठाकरे भी मंगलवार को अपने दल के लिए 23 सीटों की एक सूची लेकर शरद पवार के घर गए थे। दोनों नेताओं के बीच करीब डेढ़ घंटे बैठक चली। बताया जा रहा है कि इस बातचीत में प्रकाश आंबेडकर को दी जाने वाली सीटों पर भी चर्चा हुई है। एमवीए के नेता प्रकाश आंबेडकर को कितनी सीटों पर मना पाएंगे, यह कहा नहीं जा सकता। क्योंकि, प्रकाश आंबेडकर 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने दल को मिले वोटों के आधार पर ही सीटें मांग रहे हैं। तब प्रकाश आंबेडकर का दल वंचित बहुजन आघाड़ी राज्य की 47 सीटों पर चुनाव लड़कर 14 प्रतिशत वोट पाने में सफल रहा था। वह जीत तो एक भी सीट नहीं पाए थे। लेकिन कांग्रेस को सात सीटों पर हरवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसलिए एमवीए उन्हें नाराज करने की स्थिति में नहीं है। शिवसेना (यूबीटी) और प्रकाश आंबेडकर की खींचतान में कांग्रेस और शरद पवार तो बोल भी नहीं पा रहे हैं।

दूसरी ओर सत्तारूढ़ महायुति में ऊपर से तो सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है। उसके नेता कह रहे हैं कि सीट का बंटवारा जीत के समीकरण के आधार पर तय होगा। लेकिन, शिवसेना शिंदे गुट ने 22 सीटों की सूची सामने रख दी है। दरअसल, असली शिवसेना का दर्जा एवं चुनाव चिह्न पा चुके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के भाव बढ़ चुके हैं। पिछले वर्ष शिवसेना में हुई टूट के बाद पार्टी के 18 में से 13 सांसद उनके साथ आ चुके हैं। चूंकि, 2019 में शिवसेना राज्य की 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसलिए, वह अपने साथ आ चुके सांसदों के अलावा नौ और सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी प्रकार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी अपने दल के लिए 10 सीटों की मांग रख रहे हैं।

जबकि, भाजपा अपने इन दोनों साथियों को लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर ही मना लेना चाहती है। छह माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भले वह उन्हें अधिक सीटें देकर अपने साथ रखे। मंगलवार को महाराष्ट्र पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपनी पार्टी के अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से भी बातचीत होने की संभावना है। माना जा रहा है कि दोनों गठबंधनों में सीटों का मसला बुधवार को सुलझा लिया जाएगा।

****

12 करोड़ से अधिक की शाहजहां शेख की संपत्ति को ईडी ने मनी लांड्रिंग के तहत प्रावधानिक तौर पर कुर्क की है। इनमें कोलकाता, संदेशखाली व ग्राम सरबेरिया में स्थित अपार्टमेंट जैसी 14 अचल संपत्ति शामिल हैं।

न्यूज गैलरी

जमीन के बदले नौकरी घोटाले में अंतरिम जमानत बढ़ाई

नई दिल्ली : जमीन के बदले नौकरी घोटाले में अदालत ने व्यवसायी और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के करीबी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत 12 मार्च तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग वाली उनकी अर्जी पर सुनवाई 12 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। कात्याल पांच फरवरी से अंतरिम जमानत पर हैं। मामले में ईडी ने अमित कात्याल को मिली अंतरिम जमानत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित लिया है। ईडी ने अपने आरोपपत्र में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, हृदयानंद चौधरी और अमित कात्याल को आरोपित बनाया है। ईडी ने बाद में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था। (जासं)

हीरानगर में भारत-पाक सीमा के पास बारूद बरामद

कठुआ : भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कठुआ जिला के हीरानगर सेक्टर में सुरक्षाबलों ने मंगलवार सुबह एक पालीथिन बैग से बारूद बरामद किया। बारूद को निष्क्रिय कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह देसी बारूद है, जो जंगली जानवरों को भगाने के काम आता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सात मार्च को श्रीनगर में रैली करने आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले रही हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर भी बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। (जासं)

आरएसएस कार्यकर्ता पर हमले का आरोपित गिरफ्तार

बेंगलुरु : कर्नाटक पुलिस ने मंगलवार को बेंगलुरु में आरएसएस कार्यकर्ता पर हुए हमले के मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरएसएस कार्यकर्ता पर उस समय हमला हुआ था, जब वह सीएए के पक्ष में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद घर लौट रहे थे। आरोपित की पहचान अजहर के रूप में की गई है। इसे पुलिस ने कोलार जिले के बंगारपेट शहर से गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपित सऊदी चला गया था। वहां वह बहनोई की मदद से छिपने में कामयाब रहा। अभी वह बंगारपेट में पत्नी के पास आया था। आरोपित को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में अजहर के सहयोगियों इरफान, सैयद अकबर उर्फ मैकेनिक अकबर, सैयद सिद्दीकी, अनवर बाशा, सादिक अमीन और सना को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपितों ने साजिश रचकर 22 दिसंबर 2019 में आरएसएस कार्यकर्ता वरुण पर हमला किया था।

मुख्तार खूंखार अपराधी : सुप्रीम कोर्ट

शिकंजा ▶ इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्तार की याचिका पर सुनवाई टाली

उप्र सरकार ने कोर्ट में कहा, अंसारी ने राज्य में आतंक का साम्राज्य फैला रखा था

मुख्तार अंसारी। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि वह एक खूंखार अपराधी है और उसके ऊपर ऐसे कई मामले हैं। अंसारी ने अपनी याचिका में 24 साल पुराने एक मामले में उसे पांच साल की सजा सुनाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने अंसारी की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को स्थगित कर दी।

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि अंसारी ने राज्य में आतंक का साम्राज्य फैला रखा था, जिस पर पीठ ने कहा कि वह अब सलाखों के पीछे है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 13 अक्टूबर को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अंसारी की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। इससे पहले 23 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अंसारी को बरी करने के एक फैसले को पलट दिया था और गैंगस्टर कानून से जुड़े एक मामले में उसे पांच साल की जेल की सजा सुनाई थी।

हाई कोर्ट ने विशेष सांसद-विधायक अदालत द्वारा अंसारी को बरी करने के 2020 आदेश को पलटने के साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत 1999 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विशेष अदालत ने 2020 में अंसारी को बरी कर दिया था। राज्य ने बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ 2021 में अपील दायर की। विशेष अदालत ने मऊ सदर निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार विधायक रहे अंसारी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि अभियोजन उसके खिलाफ आरोपों को प्रभावी ढंग से साबित नहीं कर सका।

मुंबई विस्फोट की जांच करने वाले अधिकारियों के नाम नहीं होंगे सार्वजनिक, जान को खतरा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ मामले में दोषी एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने की खारिज

7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में मौत की सजा पाए दोषी एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी ने सूचना के अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के तहत उन अधिकारियों के बारे में विवरण मांगा था, जिन्होंने मामले की जांच की और उसकी गिरफ्तारी व अभियोजन को मंजूरी दी थी।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने जानकारी देने से इन्कार करने के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि जानकारी उपलब्ध कराने से अधिकारियों की जान को खतरा हो सकता है। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यह सार्वजनिक हित में है कि मांगे गए विवरण का रहस्योद्घाटन नहीं किया जाए। याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी उन अधिकारियों के खिलाफ है, जो जांच में शामिल थे और जो याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और दोषसिद्धि से संबंधित अभियोजन को मंजूरी देने में भी शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि भले को घटना को हुए 20 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उक्त जानकारी उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। सिद्दीकी को मुंबई में लोकल ट्रेनों में हुए विस्फोटों में शामिल होने के लिए एक विशेष अदालत ने वर्ष 2015 में मौत की सजा सुनाई थी। इस विस्फोट में 189 लोगों की मौत हुई थी और 800 से अधिक लोग घायल हुए थे। सिद्दीकी वर्तमान में नागपुर सेंट्रल जेल में बंद है।

इसके अलावा अदालत ने सिद्दीकी की एक अन्य याचिका को भी खारिज कर दिया। उसने इसमें गृह मंत्रालय (एमएचए) को सौंपी गई इंटेलिजेंस ब्यूरो (आइबी) की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की थी। उक्त रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि कुछ लोगों को विस्फोट के मामले में गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और फंसाया गया था। हालांकि, आइबी ने कहा था कि ऐसी कोई रिपोर्ट मंत्रालय को कभी नहीं भेजी गई थी।

अपहरण व रंगदारी मांगने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोषी करार

जागरण संवाददाता, जौनपुर

▶ फैसला सुनाए जाने के बाद साथी संतोष विक्रम संग कड़ी सुरक्षा में भेजा गया जेल

पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम को अपहरण व रंगदारी मांगने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को दोषी करार दिया है। सुनवाई के दौरान वादी और गवाह पक्षद्रोही हो गए थे, इसके बाद भी अदालत ने पूर्व सांसद को दोषी करार दिया। सजा के बिंदुओं पर बुधवार को सुनवाई होगी। दोषी करार दिए जाने के समय धनंजय और संतोष विक्रम अदालत में मौजूद थे। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

जौनपुर में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 की रात लाइन बाजार थाने में तहरीर दी थी। मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव ने आरोप लगाया था कि संतोष विक्रम दो साथियों के साथ उनका अपहरण कर धनंजय सिंह के आवास पर ले गया। वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने का दबाव बनाया।

इन्कार पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर लिया। बाद में हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी।

अदालत में धनंजय सिंह व संतोष विक्रम ने कहा था कि वादी पर दबाव डालकर मुकदमा दर्ज कराया गया। उच्चाधिकारियों के दबाव में अदालत में केस डायरी दाखिल की गई। वादी अभिनव ने पुलिस को दिए बयान व धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट को दिए बयान में अलग-अलग बातें कहीं। सरकारी वकील लाल बहादुर पाल ने अदालत में तर्क दिया कि वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद धनंजय सिंह और संतोष विक्रम के विरुद्ध तीन अप्रैल 2022 को अपहरण, रंगदारी, षड्यंत्र आदि धाराओं में आरोप तय किया था। वादी अभिनव सिंघल 15 अप्रैल 2022 को कोर्ट में अपहरण व रंगदारी की बात से मुकर गए थे। कोर्ट ने अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपहरण, रंगदारी, गाली-गलौज व साजिश रचने की धाराओं में धनंजय सिंह व संतोष विक्रम को दोषी करार दिया है।

गवाहों के मुकरने के बाद धनंजय सिंह को उम्मीद थी कि दोषमुक्त हो जाएंगे। अदालत का आदेश सुनकर वह हतप्रभ रह गए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि केस दर्ज कराने वाला वादी और गवाह कोर्ट में घटना से मुकर गए थे। अपहरण व रंगदारी की बात से भी इन्कार किया था। हमें फर्जी ढंग से फंसाया गया है।

कर्नाटक के सीएम-डिप्टी सीएम को धमकी- पैसे दो नहीं तो होंगे बम धमाके

▶ ई-मेल भेजकर 25 लाख अमेरिकी डालर की मांगी फिरौती

▶ गत एक मार्च को ही रामेश्वरम कैफे में हुआ था धमाका

सिद्दरमैया। फाइल डीके शिवकुमार। फाइल

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को धमकी भरा मेल मिला है। इसमें 25 लाख अमेरिकी डालर (तकरीबन 20.72 करोड़ रुपये) का भुगतान नहीं करने पर राज्य के अलग-अलग हिस्सों में सिलसिलेवार बम विस्फोट करने की धमकी दी गई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए धमकी भरा मेल भेजने वाले की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि गत एक मार्च को बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड क्षेत्र में स्थित भोजनालय रामेश्वरम कैफे में विस्फोट हुआ था और दस लोग घायल हो गए थे।

कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को बताया कि उन्हें व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को तीन दिन पहले धमकी भरा मेल मिला था। मेल को जांच के लिए पुलिस अधिकारियों को को भेज दिया गया है। यह मेल शाहिद खान 10786 आइडी से भेजा गया है और उसने भविष्य में संचार के लिए एक अन्य आइडी मेल साझा की है। उन्होंने मेल पढ़ते हुए बताया कि इसमें चेतावनी दी गई है यदि तुमने 25 लाख डालर नहीं दिए तो हम पूरे कर्नाटक में बसों, ट्रेनों, टैक्सियों, मंदिरों, होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर बम विस्फोट करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने दूसरी चेतावनी दी है कि हम तुम्हें एक और ट्रेलर दिखाना चाहते हैं। अगले ट्रेलर में हम अंबारी उत्सव बस में धमाका करेंगे। बस में धमाका करने के बाद हम अपनी मांग इंटरनेट मीडिया पर उठाएंगे। हम विस्फोट के बारे में अपनी जानकारी ट्वीट करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें नहीं पता कि यह फर्जी है अथवा असली, लेकिन पुलिस अधिकारी अपने काम पर जुट गए हैं।

आंध्र और कर्नाटक में चार वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव

बेंगलुरु, प्रेट्र : दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) क्षेत्र से गुजरते समय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में शरारती तत्वों ने चार वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव किया। रविवार को घटित घटनाओं में किसी भी यात्री अथवा चालक दल को कोई चोट नहीं पहुंची। हालांकि ट्रेन के खिड़कियों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि पहली घटना रविवार सुबह तकरीबन सवा छह बजे हुई। चिक्काबनवारा रेलवे स्टेशन से गुजरने के बाद धारवाड़ वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। दूसरी घटना में दोपहर सवा तीन बजे धारवाड़ से बेंगलुरु सिटी जंक्शन जा रही वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। तीसरी घटना दोपहर साढ़े चार बजे हुई और आंध्र प्रदेश में कुप्पम से पहले मैसूरु जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल जा रही ट्रेन पर पथराव किया गया। चौथी घटना में रात आठ बजे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में धर्मावरम जंक्शन के पास से गुजरते समय वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके गए।

आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर खां बरेली दंगे का मास्टरमाइंड : कोर्ट

जागरण संवाददाता, बरेली

वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे का निर्णय सुनाने वाले न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आइएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को बरेली में 2010 में हुए दंगे का मास्टरमाइंड मानते हुए 11 मार्च को कोर्ट में तलब किया है। मंगलवार को दिए आदेश में उन्होंने तत्कालीन कमिश्नर, डीएम, एसएसपी, डीआइजी, आइजी व शासन स्तर के अधिकारियों पर तल्ख टिप्पणी भी की। लिखा कि अधिकारियों ने विधिक रूप से कार्य न कर सत्ता के इशारे पर मौलाना तौकीर का सहयोग किया। इस संबंध में कार्रवाई के लिए आदेश को प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजी गई है।

दो मार्च 2010 को हुए दंगे के मुकदमे में बलवा, सरकारी काम में बाधा, 7 सीएलए एक्ट, जानलेवा हमला, धार्मिक भावनाएं भड़काने, लोक संपत्ति निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गई थीं।

यदि कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता में बैठता है, तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं क्योंकि उनका जीवन त्याग एवं समर्पण का होता है। वर्तमान में गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवधारणा को सत्य साबित किया है। किंतु यदि किसी धार्मिक व्यक्ति द्वारा अपने संप्रदाय को भड़काया जाता है तो कानून व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है, इसका उदाहरण मौलाना तौकीर रजा खां है।

- न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर

उस दौरान पुलिस ने कई आरोपित बनाए, मगर, मौलाना तौकीर का नाम नहीं था। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम) रवि कुमार दिवाकर ने गवाहों के बयानों के आधार पर 319 सीआरपीसी के तहत मौलाना तौकीर रजा खां को आरोपित माना।

कोर्ट ने आदेश में जिक्र किया कि पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद पुलिस ने चार्जशीट में मौलाना तौकीर का नाम शामिल नहीं किया।

ऐसा लगता कि ज्ञानवापी प्रकरण पर फैसला देकर कोई पाप कर दिया

न्यायाधीश ने लिखा कि 2022 में वाराणसी में ज्ञानवापी प्रकरण पर निर्णय दिया तब मुस्लिम संगठन ने 32 पन्नों का धमकी भरा पत्र भेजा। उस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मेरी मां लखनऊ, भाई शाहजहांपुर में रहते हैं। उनकी चिंता बनी रहती है। मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं...पापा न्यूज में दिखाया जा रहा है कि आपको जान से मार दिया जाएगा। मेरे परिवार में इतना भय है कि शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। आवास से निकलने पर कई बार सोचना पड़ता है। उस निर्णय के बाद एक वर्ग विशेष के लोग एवं अधिकारियों का रवैया मेरे प्रति अजीब सा हो गया है। जैसे लगता हो कि मैंने ज्ञानवापी पर फैसला देकर कोई पाप कर दिया जबकि मैंने विधिक प्रविधानों के अंतर्गत कार्य किया।

छत्तीसगढ़ के कोरबा में डीएमएफ में 600 करोड़ की कमीशनखोरी

रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)

▶ पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और अनिला भेड़िया के करीबियों पर पड़े छापे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को वर्ष 2022-23 में हुए खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) घोटाले की जांच के दौरान कोरबा जिले में 500 से 600 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा होने के इनपुट मिले हैं। इसमें करीब दो हजार करोड़ रुपये के एवज में 25 से 40 प्रतिशत तक कमीशन लिए जाने की जानकारी मिली है।

ईडी की विज्ञप्ति में बताया गया कि एक मार्च को ईडी ने छत्तीसगढ़ के पांच शहरों में एक साथ दबिश दी थी। भूपेश बघेल सरकार के राजस्व मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के करीबियों सहित कुछ सरकारी अफसरों के 13 ठिकानों की तलाशी ली गई थी। इस दौरान करीब 27 लाख रुपये नकद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। इन दस्तावेजों से ही कमीशनखोरी की जानकारी सामने आई। अब इसे लेकर प्रदेश के अन्य जिलों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।

ईडी ने बताया कि साल 2022-23 में कोरबा को आबंटित डीएमएफ की राशि 2,000 करोड़ रुपये से अधिक थी। इसमें कोरबा में अकेले कमीशन की रकम 500 से 600 करोड़ तक हो गई। डीएमएफ को लेकर पूरे राज्य से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इससे पता चलेगा कि किस अधिकारी के माध्यम से डीएमएफ में कितना लेन-देन हुआ है, इसको निर्धारित करने का काम किया जा रहा है।

डीएमएफ फंड घोटाले में 54 पर एफआइआर, ईओडब्ल्यू में दर्ज है अपराध : कोयला घोटाले में जेल में बंद जिले की निलंबित कलेक्टर रानू साहू के अलावा खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) घोटाले में कारोबारी एवं टेंडर लेने वाले संजय शेण्डे, अशोक कुमार अग्रवाल, मुकेश कुमार अग्रवाल, रिषभ सोनी एवं बिचौलिए मनोज कुमार द्विवेदी, रवि शर्मा, पीयूष सोनी, पीयूष साहू, अब्दुल एवं शेखर को नामजद आरोपित बनाया गया है। साथ ही करीब 54 लोग संदेह के दायरे में हैं। सभी के खिलाफ ईओडब्ल्यू में अपराध दर्ज है।

'खून चढ़ाने से संक्रमित हुए अधिकारी को तुरंत दें 18 लाख'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वायुसेना अधिकारी को तत्काल मुआवजे के रूप में 18 लाख देने का निर्देश दिया। वायुसेना अधिकारी 2002 में जम्मू-कश्मीर के सांबा स्थित सैन्य अस्पताल में संक्रमित खून चढ़ाने से एचआइवी संक्रमित हो गया था। शीर्ष अदालत ने गत 26 सितंबर को याचिका पर दिए अपने फैसले में वायुसेना-थलसेना को चिकित्सा लापरवाही का दोषी मानते हुए उन्हें 1.5 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।

शीर्ष अदालत द्वारा 2023 के फैसले में जारी निर्देशों की अवमानना का आरोप लगाने वाली पूर्व वायुसेना अधिकारी की याचिका मंगलवार को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पहुंची। पीठ ने उन्हें तत्काल 18 लाख का भुगतान करने का आदेश देने के साथ कहा कि यह राशि उनके बैंक खाते में जमा करा दी जाए। पीठ ने निर्देश दिया कि उन्हें पेंशन का भुगतान करने के लिए दिव्यांगता को 100 प्रतिशत माना जाए।

बांबे हाई कोर्ट ने डीयू के पूर्व प्रोफेसर साईबाबा को किया बरी

राज्य ब्यूरो, मुंबई

माओवादी संपर्क मामले में सुनाई गई थी उम्र कैद की सजा

बांबे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने माओवादी संपर्क मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को मंगलवार को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में विफल रहा है। अदालत ने साईबाबा को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को भी रद कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

जस्टिस विनय जोशी और एसए मेनजेस की खंडपीठ ने मामले में पांच अन्य आरोपितों को भी बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्राप्त मंजूरी को भी अमान्य करार दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपितों के खिलाफ कोई कानूनी जब्ती स्थापित करने में विफल रहा है। पीठ के अनुसार ट्रायल कोर्ट का फैसला कानून के तहत टिकाऊ नहीं है। इसलिए हम अपील की अनुमति देते हैं और दिए गए फैसले को रद करते हैं। अदालत ने कहा कि कानून के अनिवार्य प्रविधानों के उल्लंघन के बावजूद मुकदमा चलाना न्याय की विफलता के समान है।

माओवादियों से संबंध एवं देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में साईबाबा को गिरफ्तारी 2014 में हुई थी। वह तभी से नागपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। मार्च 2017 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की एक सत्र अदालत ने साईबाबा और एक पत्रकार तथा जेएनयू के छात्र सहित पांच अन्य को यूएपीए एवं भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रविधानों के तहत दोषी ठहराया था। हाई कोर्ट की एक अन्य पीठ ने 14 अक्टूबर, 2022 को साईबाबा को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि यूएपीए के तहत वैध मंजूरी के अभाव में मुकदमे की कार्यवाही अमान्य थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उसी दिन फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अप्रैल 2023 में हाई कोर्ट के आदेश को रद करते हुए साईबाबा द्वारा दायर याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया।

जस्टिस रोहित देव और अनिल पानसरे की पिछली पीठ ने अक्टूबर 2022 के अपने फैसले में कहा था कि यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी 2014 में उन पांच आरोपितों के खिलाफ दी गई थी, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। 2014 में जब निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था, तब साईबाबा पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की कोई मंजूरी नहीं थी।

पत्नी ने कहा, 10 साल के संघर्ष के बाद मिला न्याय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा की पत्नी वसंता कुमारी ने माओवादियों से संबंध रखने के मामले में साईबाबा को बरी किए जाने पर मंगलवार को कहा कि 10 साल के संघर्ष के बाद न्याय मिला है। बांबे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने साईबाबा को बरी करते हुए कहा कि वह सभी आरोपितों को बरी कर रहे हैं, क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में विफल रहा।

वसंता कुमारी ने कहा कि उनके पति की प्रतिष्ठा कभी भी दांव पर नहीं लगी क्योंकि जो लोग उन्हें जानते थे, वे उन पर विश्वास करते थे। उन्होंने अधिवक्ताओं और कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं केवल यह आशा करती हूं कि भविष्य में भी उनकी उचित स्वतंत्रता में कोई बाधा न आए। हाई कोर्ट ने साईबाबा (54) की सुनाई गई उम्रकैद की सजा को भी रद कर दिया। न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वाल्मीकि एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने मामले में पांच अन्य आरोपितों को भी बरी कर दिया है। साईबाबा 2014 में, गिरफ्तारी के बाद से नागपुर कारागार में बंद हैं। वर्ष 2017 में, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की एक सत्र अदालत ने माओवादियों से संबंध रखने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोपों को लेकर साईबाबा, एक पत्रकार और जेएनयू के एक छात्र सहित पांच अन्य को दोषी ठहराया था।

जागरण विशेष नवाचारी अधिकारी

नवाचार से तोड़ी बस्तर की 'छवि', दशा बदल पर्यटन को दी नई दिशा

अनिमेष पाल ● जगदलपुर

25 गांवों के लोगों को मिला रोजगार

इंटरनेट मीडिया इंफ्लुएंसर्स को बस्तर बुलाकर भ्रमण कराया, अब यहां के सौंदर्य की देशभर में चर्चा

छत्तीसगढ़ के बस्तर का नाम सुनते ही नक्सल आतंक की छवि मन में उभर आती है। मगर अपनी नवाचारी गतिविधियों से भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के अधिकारी धम्मशील गणवीर इस छवि को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो पर्यटक अब तक बस्तर नहीं आए हैं, वे यहां के अप्रतिम सौंदर्य को देख सकें। इसी का परिणाम है कि पिछले तीन वर्षों में यहां पर्यटकों की संख्या सवा लाख तक बढ़ गई है। 2021-22 में पर्यटकों की संख्या 85,519 थी, 2023-24 में यह दो लाख के पार पहुंच गई।

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक बनाए जाने के बाद से गणवीर ने 200 वर्ग किमी के उद्यान क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाई।

- यहां के आदिवासियों को अब रोजगार भी मिलने लगा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में धुरवा, गोंड जनजाति बहुल 54 गांव आते हैं। इसमें से 25 गांव में इको विकास समिति का गठन कर रोजगारपरक गतिविधि शुरू की है।
- जंगल सफारी पर्यटन में 35 हितग्राही को सफारी वाहन उपलब्ध कराने के साथ 25 युवाओं को गाइड नियुक्त कर रोजगार दिया है।
- तीरथगढ़ जलप्रपात में 50 से अधिक परिवार को कैंपिंग, होम स्टे, कैंटीन के माध्यम से रोजगार मिला है। उद्यान क्षेत्र के गुड़ियापदर, कोटमसर, मादरकोंटा, मांझीपाल में होम स्टे भी शुरू किए हैं।
- धुड़मारास में कयाकिंग व बंबू राफ्टिंग का दायित्व वन समिति के माध्यम से 45 परिवारों को दिया गया है, समिति को 25 से 30 हजार रुपये की आय प्रतिदिन हो रही है।

कांगेर वैली के धुड़मारास में बंबू राफ्टिंग ● फाइल फोटो

विश्व में बस्तर जैसे प्राकृतिक व सांस्कृतिक महत्व के गिने-चुने स्थल ही बचे हैं। पर्यटन को अर्थव्यवस्था जोड़कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन की संभावनाओं को देखते हुए नवाचारी गतिविधियां शुरू की थी। इसका लाभ भी यहां के लोगों को मिल रहा है।

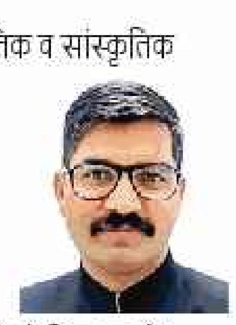

धम्मशील गणवीर, निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान

तीन वर्षों में बढ़ी पर्यटकों की संख्या

85,519	1,85,865	2,23,190
2021-22	2022-23	2023-24

उन्होंने बताया कि साइकिलिंग और बाइक राइडिंग का शौक होने के कारण वह सुबह की सैर में आसपास के क्षेत्र में निकल जाते हैं। इससे उन्हें पर्यटक के लिहाज से बेहतर स्थानों की जानकारी हो जाती है। 45 गांव के वनवासियों की आस्था को समझते हुए, उन्होंने कांगेर घाटी क्षेत्र में प्रकृति व सांस्कृतिक पर्यटन का माडल तैयार किया। इससे यह क्षेत्र आदिम संस्कृति के साथ ही प्राकृतिक पर्यटन का केंद्र बनकर उभरा है। जबकि अब तक इसे केवल तीरथगढ़ या कोटमसर गुफा के नाम से जाना जाता था। कांगेर घाटी में कांगेर नाला में केरल की तर्ज पर बंबू राफ्टिंग व कयाकिंग व नेचर ट्रेल शुरू की, जिससे सैकड़ों पर्यटक यहां खिंचे चले आ रहे हैं। पर्यटन और आदिम संस्कृति को जोड़ते हुए कोटमसर व धुड़मारास गांव को विकसित किया है। धुड़मारास गांव को बेस्ट टूरिस्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। अब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भी यूनेस्को भेजा है।

देखो बस्तर से क्षेत्र के सौंदर्य की चर्चा: गणवीर ने बस्तर के सौंदर्य को बाहरी दुनिया तक पहुंचाने को 'देखो बस्तर' आयोजित किया। देशभर से इंटरनेट मीडिया इंफ्लुएंसर्स को बस्तर का भ्रमण करवाया, जिससे देशभर में यहां के सौंदर्य की चर्चा होने लगी है। देशभर के बाइकर्स को बुलाकर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चित्रकोट जलप्रपात से लेकर दंतेवाड़ा की ढोलकल पहाड़ी तक लोगों को लेकर गए।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

धन निकासी की शिकायत पर उद्धव गुट के अनिल देसाई ईओडब्ल्यू के समक्ष पेश

मुंबई, प्रेट्र : शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता अनिल देसाई पार्टी कोष से 50 करोड़ रुपये निकाले जाने के आरोप की प्रारंभिक जांच के संबंध में मंगलवार को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के समक्ष पेश हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना के एक पदाधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई है। इसके अनुसार, उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (यूबीटी) ने निर्वाचन आयोग द्वारा शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित करने के बाद भी पार्टी के कोष से 50 करोड़ रुपये निकाले। ईओडब्ल्यू ने पार्टी कोष से पैसे निकालने में धोखाधड़ी व जालसाजी की जांच शुरू कर देसाई को समन भेजा था। देसाई सुबह दक्षिण मुंबई स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय में ईओडब्ल्यू अधिकारियों के समक्ष पेश हुए।

****

दैनिक जागरण

एक आरंभिक छोटे कदम से ही बड़े लक्ष्य की पूर्ति होती है

बेहूदा बयान

कोई नेता बौखलाहट, घृणा या फिर किसी स्वार्थ के कारण किस हद तक गिर सकता है, इसका ताजा उदाहरण है द्रमुक सांसद ए. राजा का यह बेहूदा बयान कि भारत कोई देश ही नहीं। उनकी समझ से भारत एक उपमहाद्वीप है, जिसमें तमिल, मलयालम आदि अलग भाषा और देश हैं। वह केवल क्षेत्रवाद और अलगाववाद को हवा देने तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने जय श्रीराम का नारा लगाने वालों को धिक्कारते हुए उन्हें मूर्ख करार दिया और साफ शब्दों में कहा कि हम तो राम के शत्रु हैं और भारत को माता के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह केवल भड़काऊ बयान ही नहीं, एक ऐसा नफरती भाषण है, जिसके लिए उन्हें कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। उन्होंने यह उकसाने वाला बयान तब दिया, जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि को उनके उस कथन के लिए फटकार लगाई थी, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया बताते हुए उसे खत्म करने की जरूरत जताई थी। जब उदयनिधि ने यह सब कहा था, तब जिन नेताओं ने उनका समर्थन किया था, उनमें ए. राजा भी शामिल थे। यह सहज ही समझा जा सकता है कि उदयनिधि को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार से ए. राजा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा।

ए. राजा द्रमुक के सांसद भर नहीं हैं। वह मनमोहन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2-जी घोटाले के लिए वही जिम्मेदार माने जाते हैं। जिन घपले-घोटालों ने कांग्रेस की लुटिया डुबोने का काम किया, उनमें 2-जी घोटाला भी था। हो सकता है कि ए. राजा को अपने बेजा बयान के चलते तमिलनाडु में किसी बड़ी राजनीतिक कठिनाई का सामना न करना पड़े, लेकिन द्रमुक के आइएनडीआइए का मुख्य घटक होने के नाते कांग्रेस और उसके अन्य सहयोगी दलों के लिए वह न उगलते बनेगा-न निगलते। कांग्रेस और आइएनडीआइए के अन्य घटक ए. राजा के बयान से असहमति जताकर या फिर उनके कथन को उनका निजी विचार करार देकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। सबसे पहले तो उन्हें यही बताना होगा कि यदि ए. राजा भारत को देश ही नहीं मानते तो फिर 'इंडिया' नाम वाला गठबंधन बनाने की क्या जरूरत थी? यह पहली बार नहीं है, जब तमिलनाडु में राजनीतिक स्वार्थों के चलते हिंदी या फिर राम के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काने का काम किया गया हो। यह काम वहां पहले भी किया जाता रहा है। इसी तरह वहां तमिल राष्ट्रवाद को भी उभारने की हरकत होती रही है। इस बार तो ए. राजा सारी हदें ही पार कर गए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह उनके बयान का स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि ऐसे बिगड़े बोल तो देशविरोधी या फिर अलगाववादी संगठनों के तत्व बोलते हैं। चूंकि ऐसे बयान देश की एकता और अखंडता को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले हैं, इसलिए उन्हें सहन नहीं किया जा सकता।

अच्छी पहल

बिहार सरकार जल-जीवन- हरियाली को लेकर हमेशा सचेत और प्रयासरत रही है। चाहे लुप्त हो रहे कुआं, तालाब या अन्य जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने का मोर्चा हो या वन क्षेत्र को विस्तारित करने का मामला, विशेषकर नीतीश सरकार ने इसपर लगातार काम किया है। इसका सुफल भी देखने को मिल रहा है। जल प्रबंधन के लिए किए गए उपायों से कुछ जगहों पर जलस्तर में सुधार हुआ है। हालांकि अभी बहुत काम करना शेष है, लेकिन यह सच है कि लगातार इसपर काम होता रहा तो हालात बहुत हद तक सुधर जाएंगे। एक संवेदनशील सरकार को पर्यावरण की चिंता होनी ही चाहिए। आज पर्यावरण वैश्विक चिंता का विषय है। ऐसे में अपने-अपने हिस्से के काम कर लिए जाएं तो संभावित भयावहता को कम किया जा सकता है। एक और उल्लेखनीय कार्य करते हुए बिहार सरकार ने जलीय जीवों के संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पटना में डाल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। इस तरह का यह एशिया का पहला अनुसंधान केंद्र है, जहां देश-विदेश के विज्ञानी शोध करेंगे। विशेषकर गांगेय डाल्फिन पर शोध होगा, जो इस जलीय जीव के रहवास से लेकर प्रजनन व संवर्द्धन तक के मार्ग को सरल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। गांगेय डाल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्राप्त है। गंगा में इस नेत्रहीन स्तनपायी जीव के साथ-साथ घड़ियाल, कछुआ और ऊदबिलाव जैसे जलीय जीव हैं। इनका संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। गंगा में इन जीवों के संवर्द्धन में आने वाली अड़चनों पर अध्ययन होगा। जल की गुणवत्ता, अवैध शिकार, रहवास की कमी आदि के अध्ययन से एक रास्ता निकलेगा। निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण में यह बड़ा कदम होगा। सरकार शोध के आधार पर अनुकूल वातावरण बनाने के प्रति सचेत रहेगी। लगातार प्रदूषित हो रही गंगा के संरक्षण का भी रास्ता निकलेगा। जलीय जीवों के संरक्षण में आमजन की सहभागिता भी अति महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस के पराभव का कारण

सुरेंद्र किशोर

अपेक्षाकृत कम योग्य उत्तराधिकारियों के कारण ही कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल संकट में हैं। कुछ तो डूब रहे हैं

अवधेश राजपूत

कई कारणों से 1929 से अब तक कांग्रेस ने नेहरू-गांधी परिवार के अपेक्षाकृत कम योग्य नेताओं को सत्ता और पार्टी के शीर्ष पर बैठाया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को जब सत्ता सौंपी गई, तब वे अपने समय के कांग्रेस के श्रेष्ठतम नेता नहीं थे। श्रेष्ठतम नेता कोई और थे, जिन्हें दरकिनार कर इस परिवार के नेताओं को आगे किया गया। आज भी वही हाल है। नतीजतन अगले लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस से एक-एक करके नेता निकलते जा रहे हैं। देश की मूल समस्याओं को समझने और उनके हल प्रस्तुत करने की क्षमता के अभाव में नेहरू-गांधी परिवार के सदस्य देश, सरकार और दल को सफल नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। आर्थिक, आंतरिक और वैदेशिक मोर्चों पर सफलताएं कम ही मिलीं। कुछ क्षेत्रों में नेहरू-इंदिरा-राजीव की सफलताएं जरूर ध्यान खींचने वाली रहीं, पर इस गरीब देश को जिस तरह के निर्णायक नेतृत्व की जरूरत थी, वह आवश्यकता पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ठीक ही कहते हैं, 'इस देश के कई जरूरी काम मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे।'

किसी देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर सफलता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आर्थिक साधनों से ही विकास, कल्याण तथा सुरक्षा के काम किए जा सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि में 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, 'केंद्र सरकार 100 पैसे भेजती है, पर गांवों तक उसमें से सिर्फ 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं।' यह काम एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। उसमें कुछ न कुछ योगदान 1947 से 1985 तक की सारी सरकारों का रहा ही होगा। यानी उन दिनों की सरकारें भ्रष्टाचार के खिलाफ उतनी सख्त नहीं थीं, जितनी किसी गरीब देश की सरकारों को होना चाहिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में कई दशक पहले सचिव रहे एनसी सक्सेना ने यह सलाह दी थी कि बैंक खातों के जरिये ही लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाई जानी चाहिए। उससे लीकेज बंद होगा, लेकिन यह काम मोदी सरकार ने ही बड़े पैमाने पर शुरू किया। सक्सेना की नेक सलाह को मानने से कई सरकारों ने इन्कार कर दिया। कारण स्पष्ट है।

नेताओं के वंशज-परिजन के बीच से निकले अपेक्षाकृत कम योग्य उत्तराधिकारियों के कारण ही कांग्रेस समेत कई दल संकट में हैं। कुछ तो डूब रहे हैं। संकेत हैं कि आने वाले दिन भी उनके लिए सुखकर नहीं हैं। इन दलों की स्थिति सुधरती नहीं देखकर बीते दिनों के कुछ लाभार्थी तरह-तरह के उपदेश दे रहे हैं। कुछ तो विलाप और प्रलाप भी कर रहे हैं। दलों के पराभव के मूल कारणों की गंभीर चर्चा संबंधित दलों के नेता भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे हाईकमान के यहां उनकी पूछ खत्म हो जाएगी। कांग्रेस में वंशवाद की शुरुआत 1929 में ही हो चुकी थी। उसे ठोस रूप महात्मा गांधी की मदद से मोतीलाल नेहरू ने दिया। इससे यह साफ है कि गांधी जी ने प्रारंभिक हिचक के बाद ही जवाहरलाल नेहरू को आगे बढ़ाया। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस मुख्यालय संचालन के लिए प्रयागराज का अपना विशाल आनंद भवन दे दिया था। गांधी जी पर संभवतः इस बात का असर रहा होगा। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल ने 1928 में महात्मा गांधी को बारी-बारी से तीन चिट्ठियां लिखीं। उनके जरिये उन्होंने आग्रह किया कि वह जवाहरलाल को कांग्रेस अध्यक्ष बनवा दें। पहले दो पत्रों पर गांधी राजी नहीं हुए। वह तब जवाहर को उस पद के योग्य नहीं मानते थे। मोतीलाल जी के तीसरे पत्र पर गांधी जी बेमन से मान गए।

आजादी के तत्काल बाद जब प्रधानमंत्री पद पर किसी नेता को बैठाने की बात आई तो महात्मा गांधी ने सरदार पटेल के दावे को नजरअंदाज कर नेहरू को प्रधानमंत्री बनवा दिया, जबकि देश की 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने इस पद के लिए सरदार पटेल का नाम सुझाया था। कांग्रेस के तब के अधिकतर शीर्ष नेतागण इस देश की जमीनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस पद के लिए सरदार पटेल को सर्वाधिक योग्य मानते थे। 1958 में इंदिरा गांधी कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य बना दी गईं। कल्पना कीजिए, कितने बड़े-बड़े स्वतंत्रता सेनानी तब इस पद के लिए उनसे अधिक काबिल थे। कुछ समय बाद इंदिरा गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दी गईं। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महावीर त्यागी ने इंदिरा को अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में जवाहरलाल नेहरू को कड़ा पत्र लिखा।

वास्तव में नेहरू जी इंदिरा को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाकर यह संकेत दे रहे थे कि उनके न रहने पर बेटी प्रधानमंत्री बने। अंततः ऐसा ही हुआ। बीच में कुछ समय के लिए लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। क्या 1984 में इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या के बाद राजीव गांधी कांग्रेस में पीएम पद के लिए सबसे योग्य नेता थे? ऐसा नहीं था। राजीव गांधी ने जिस तरह अपनी सरकार और पार्टी चलाई, उसका यह नतीजा हुआ कि उनके बाद कांग्रेस को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिलना बंद हो गया। याद रहे कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही जनता ने पहली बार 1977 में कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से हटा दिया था। दूसरी ओर, बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से राजनीति में आए मोदी के कारण भाजपा की चुनावी ताकत बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि मोदी ने देश की मूल समस्याओं को समझा और उनके समाधान पूरे मनोयोग से तलाशे। उसके सकारात्मक परिणाम भी देखे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आजादी के तत्काल बाद के हमारे शासकों को सुशासन की सलाह देने वालों की कोई कमी थी। सिंगापुर के संस्थापक प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने नेहरू को इस बारे में सलाह दी थी। जब उनकी सलाह नहीं मानी गई तो उन्होंने कहा, 'समस्याओं के बोझ के कारण नेहरू ने अपने विचारों और नीतियों को लागू करने का जिम्मा मंत्रियों और सचिवों को दे दिया। अफसोस की बात है कि वह भारत के लिए वांछित परिणाम लाने में असफल रहे।' ली कुआन 1959 से 1990 तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सिंगापुर के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को 500 डालर से बढ़ाकर 55 हजार डालर पर पहुंचा दिया। भारत भी सिंगापुर की तरह तरक्की कर सकता था, लेकिन मौका गंवा दिया गया।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

गरीबी घटाने से आगे की चुनौती

डा. जयंतीलाल भंडारी

यह अच्छी बात है कि देश में गरीबी कम हो रही है, लेकिन प्रयास यह होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े

प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्था द ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन की एक हालिया अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन करने में सफलता हासिल की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेज विकास और असमानता में कमी के चलते भारत को यह कामयाबी मिली है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि कुल आबादी में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों (प्रतिदिन 1.90 डालर से कम खर्च करने वाले) की संख्या 2011-12 के 12.2 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में दो प्रतिशत पर आ गई है। यह गरीबों की संख्या में हर वर्ष 0.93 प्रतिशत की कमी के बराबर है। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबों की संख्या घटकर 2.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में एक प्रतिशत रह गई है। कहा गया है कि भारत में गरीबों की संख्या में जो गिरावट बीते 11 वर्षों में दर्ज हुई, इससे पहले इतनी गिरावट 30 वर्षों में आई थी।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों नीति आयोग द्वारा जारी किए गए वैश्विक मान्यता के मापदंडों पर आधारित बहुआयामी गरीबी इंडेक्स (एमपीआइ) के मुताबिक बहुआयामी गरीबी कम करने में सरकार की विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं की भी अहम भूमिका रही है। एमपीआइ के मद्देनजर वित्त वर्ष 2013-14 में देश की 29.17 प्रतिशत आबादी गरीब थी। अब वित्त वर्ष 2022-23 में सिर्फ 11.28 प्रतिशत लोग एमपीआइ के हिसाब से गरीब रह गए हैं। इन नौ वर्षों में 17.89 प्रतिशत लोग यानी करीब 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यहां संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट भी उल्लेखनीय है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गरीबी 2015-2016 के मुकाबले 2019-2021 के दौरान 25 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत के स्तर पर आ गई है।

यह भी कोई छोटी बात नहीं है कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आइएमएफ सहित सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वैश्विक संगठनों द्वारा भारत में बहुआयामी गरीबी घटाने में खाद्य सुरक्षा योजना की जोरदार सराहना की गई है। आइएमएफ द्वारा प्रकाशित शोधपत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम ने कोविड-19 की वजह से लगाए गए लाकडाउन के प्रभावों की गरीबों पर मार को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज, स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना, सभी घरों में बिजली के लिए सौभाग्य योजना, पेयजल सुविधा के लिए जल जीवन मिशन एवं जन-धन खाते की सुविधा आदि से लोगों को गरीबी से ऊपर लाने में खासी मदद मिली है। खासतौर से गरीबों के सशक्तीकरण में करीब 51 करोड़ से अधिक जनधन खातों (जे), करीब 134 करोड़ आधार कार्ड (ए) तथा करीब 118 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ताओं (एम) की शक्ति वाले 'जैम' से सुगठित बेमिसाल डिजिटल ढांचे की असाधारण भूमिका रही है। इसी के बल पर गरीबों के खातों में सीधे आर्थिक प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित हो रही है।

लोगों की क्रयशक्ति बढ़ाने की चुनौती। फाइल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गत माह प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट 2024-25 में बहुआयामी गरीबी से देश की जनता को पूरी तरह से मुक्त करने के पक्के इरादों और प्रयासों की कवायद दिखी। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के तहत बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकालने के उद्देश्य से विभिन्न मदों पर किए गए वित्तीय आवंटन की तुलना में औसतन 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की है। यद्यपि देश में एक ओर गरीबों के कल्याण के लिए लागू की गई विभिन्न सरकारी योजनाएं मसलन सामुदायिक रसोई, वन नेशन-वन राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पोषण अभियान आदि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी के स्तर में कमी लाने और स्वास्थ्य एवं भुखमरी की चुनौती को कम करने में सहायता मिली है, लेकिन अभी भी गरीबी की जो व्यापक चुनौती बनी हुई है, उसका सामना करने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना होगा।

हमें इस पर ध्यान देना होगा कि गरीबों के सशक्तीकरण के साथ ही उनकी प्रतिव्यक्ति आय भी बढ़े। अभी भारत उन प्रमुख 10 देशों में शामिल है, जहां बीते 20 वर्षों में लोगों की आय में असमान बढ़ोतरी हुई है। इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि गरीब लोगों को मुफ्त अनाज के साथ उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी अधिक प्रयास किए जाएं। इतना ही नहीं, देश की तेजी से बढ़ती आबादी के तहत गरीब वर्ग की नई आबादी की खाद्य सुरक्षा के लिए अधिक खाद्यान्न उत्पादन के रणनीतिक प्रयत्न भी जरूरी होंगे। इस पर भी ध्यान देना होगा कि जनकल्याण के मद्देनजर लोगों को रेवड़ियां बांटने जैसा अभियान आगे नहीं बढ़े। ऐसी योजनाएं ही आगे बढ़ाई जानी होंगी जो गरीबी से लड़ाई में सहायक बन सकें और जो गरीब लोगों को उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सक्षम हों।

सरकार को देश में अत्यधिक गरीबी का सामना कर रहे दो प्रतिशत लोगों और बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहे करीब 15 करोड़ से अधिक गरीबों को लक्ष्य के मुताबिक वर्ष 2030 तक गरीबी से बाहर लाने के लिए गरीबी कम करने से संबंधित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में अभी और अधिक कारगर प्रयासों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ना होगा। गरीबों की प्रतिव्यक्ति आय बढ़ाने के मद्देनजर गरीब परिवारों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और डिजिटल कौशल से सुसज्जित करके रोजगार से सशक्तीकरण के रणनीतिक अभियान को आगे बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है।

(लेखक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, इंदौर के निदेशक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

तपस्या

तपस्या का अर्थ है-अपने लक्ष्य के प्रति अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए उसकी प्राप्ति हो जाने तक निरंतर साधना में लीन रहना। तपस्या का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर पर्वतों अथवा कंदराओं अथवा किसी वृक्ष के नीचे आंख बंद करके बैठ जाएं। तपस्या एक व्यापक शब्द है। किसी भी कार्य अथवा लक्ष्य हेतु पूर्ण समर्पण को तपस्या कहा जाता है। फिर चाहे वह लक्ष्य गृहस्थ जीवन से संबंधित हो अथवा सांसारिक मोह-माया को छोड़कर ईश्वर प्राप्ति से संबंधित।

तपस्या के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि जिस लक्ष्य के लिए तपस्या की जा रही है, उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य विचार, चिंता अथवा तनाव मन-मस्तिष्क में घर न करने पाए, क्योंकि ऐसा होने की दशा में हमारा ध्यान पूर्णतया लक्ष्य पर केंद्रित नहीं रह पाएगा। हम उसकी प्राप्ति में असफल हो जाएंगे। तपस्या में समर्पण समाहित होता है और समर्पण के भीतर एक जादुई चुंबकीय शक्ति है। यह शक्ति ही हमें और हमारे लक्ष्य को एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने के लिए बल आरोपित करती है और एक दिन ऐसा आता है जब हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तपस्या हमें बुरे विचारों, दुर्गुणों, छल, कपट, ईर्ष्या एवं द्वेष से कोसों दूर कर देती है और हमारा मन पवित्रता के एक उच्चतम स्तर को स्पर्श कर लेता है। मन की पवित्रता हमें सृजन के लिए प्रेरित करती है।

लोहे को जब तपा दिया जाता है तो वह नरम हो जाता है, ठीक इसी प्रकार जब हम अपने मन को तपस्या की अग्नि में समाहित कर देते हैं तो विनम्रता स्वयं ही हमारी तरफ खिंची चली आती है। निष्कर्ष यही है कि लक्ष्य चाहे कोई भी हो और कैसा भी हो, बिना तपस्या के उसे हासिल कर पाना नितांत असंभव है। यदि हमने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो हमें उसे प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से तपस्या एवं समर्पण की नौका पर सवार होना पड़ेगा।

शिशिर शुक्ला

'नेट जीरो' की राह में बाधाएं

सुधीर कुमार

'नेट जीरो' से तात्पर्य कार्बन उत्सर्जन के स्तर को शून्य तक लाने के बजाय इसकी भरपाई उन प्रयत्नों पर जोर देकर करनी है, जो कार्बन अवशोषित करते हैं

दक्षिण-पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया ने 'नेट जीरो' के लक्ष्य को समय पर हासिल करने के लिए अपने देश में एक नए तरह का टैक्स- 'कार्बन टैक्स' लागू किया है। इसका मकसद 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करना है। इंडोनेशिया में कार्बन उत्सर्जन करने वाली इकाइयों को अब प्रत्येक एक टन कार्बन उत्सर्जन पर तीस हजार इंडोनेशियाई 'रुपिया' चुकाने होंगे। 'कार्बन टैक्स' बिजली संयंत्रों, परिवहन, लुगदी और कागज, पेट्रोकेमिकल्स, सीमेंट, निर्माण सामग्री जैसे क्षेत्रों पर लगाया जाएगा।

'कार्बन टैक्स' लागू करने वाला इंडोनेशिया दुनिया का 28वां देश है। इस अवधारणा को सबसे पहले डेविड गार्डन विल्सन ने 1973 में प्रतिपादित किया था। वर्ष 1990 में फिनलैंड 'कार्बन टैक्स' लागू करने वाला दुनिया का प्रथम देश बना था। मौजूदा समय में यह आर्थिक अवधारणा अलग-अलग दरों के साथ अर्जेंटीना, कनाडा, चिली, जापान, कोलंबिया, डेनमार्क जैसे देशों में प्रचलित है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को देखते हुए अब दुनिया विभिन्न तरीकों से कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाने को लेकर संजीदा होती दिख रही है। उरुग्वे ने 'नेट जीरो' कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030, फिनलैंड ने 2035, आस्ट्रिया ने 2040, जर्मनी और स्वीडन ने 2045, अमेरिका ने 2050, चीन, रूस और इंडोनेशिया ने 2060, जबकि भारत ने इसे 2070 तक हासिल करने का संकल्प लिया है। 'नेट जीरो' से तात्पर्य कार्बन उत्सर्जन के स्तर को शून्य तक लाने के बजाय इसकी भरपाई उन प्रयत्नों पर जोर देकर करनी है, जो कार्बन अवशोषित करते हैं। इसमें वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में अपनी हिस्सेदारी को क्रमबद्ध तरीके से कम करने पर बल दिया जाता है। उन क्रियाकलापों को बढ़ावा देना होता है, जो वातावरण से कार्बन को सोखने में समर्थ हों।

'नेट जीरो' का लक्ष्य पाना तब तक मुमकिन नहीं होगा, जब तक दुनिया जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल पर रोक, वनोन्मूलन पर पाबंदी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाती हैं। जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल को कम करना इस राह में एक बड़ी चुनौती है। कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा जिन जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त होता है, उनके इस्तेमाल की मानवता और पर्यावरण को भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जीवाश्म ईंधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। इससे भावी पीढ़ी की ईंधन-उपलब्धता भी प्रभावित होती है। इन पर निर्भरता घटाना तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना ही मानवता के लिए श्रेयस्कर है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

शिथिलता का खामियाजा भुगतती कांग्रेस

'आंतरिक संकट की अनदेखी के दुष्परिणाम' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राज कुमार सिंह ने कांग्रेस की मौजूदा दिशाहीनता एवं दयनीय दशा को बखूबी रेखांकित किया है। आखिर इसे क्या ही कहा जाए कि सहज बहुमत होते हुए ही पार्टी न केवल तय मानी जा रही राज्यसभा सीट को भी गंवा बैठी, बल्कि जैसे-तैसे अपनी सरकार बचाने में सफल रही है। हिमाचल का यह संकट ऐसा भी नहीं था कि आलाकमान को नजर न आ रहा हो, लेकिन वह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और हालात को बिगड़ने दिया गया। हिमाचल तो केवल एक उदाहरण भर है। बीते कुछ समय से कांग्रेस किसी भी सत्तारूढ़ राज्य में आंतरिक खींचतान पर समय रहते लगाम नहीं लगा पाई। छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक दो खेमों का टकराव मुखर रहा और मध्य प्रदेश में तो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सरकार गंवानी पड़ी। कांग्रेस को यदि अपना अस्तित्व बचाना है तो शीर्ष नेतृत्व को अपना शिथिल रवैया छोड़कर सक्रियता दिखानी होगी। अन्यथा एक के बाद एक राज्य उसके हाथ से निकलते जाएंगे और वह कुछ हिस्सों में सिमटी हुई पार्टी बनकर रह जाएगी।

केशव तिवारी, आजमगढ़

मोदी का "परिवार"

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पटना की रैली में जिस तरह से "संतान और परिवार" को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया, उसे राजनीति का निचला स्तर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राजनीति में शब्दों की मर्यादा होती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने शब्दों की मर्यादा को तोड़ते हुए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत हमला किया, वह कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी गाली को ताली में बदलना जानते हैं। विपक्षी दलों द्वारा किसी भी व्यक्तिगत हमले को किस तरह से हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय "चायवाला बयान", 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय "चौकीदार चोर का बयान" और अब 2024 के चुनाव के समय "संतान और परिवार का बयान" कहीं की न कहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक बड़ा हथियार बैठे-बिठाए दे गया। जिसका प्रयोग वह लोकसभा के चुनावी समर में समय-समय पर करेंगे। कहीं ऐसा न हो कि आइएनडीआइए को लालू प्रसाद का परिवार पर प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया गया बयान लोकसभा चुनाव में नुकसानदायक साबित हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हर व्यक्तिगत हमला विपक्षी दलों पर ही भारी पड़ा है।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

संसदीय शुचिता संरक्षित हो

सांसदों एवं विधायकों द्वारा रिश्वत लेकर वोट देने और बोलने पर आपराधिक मामला चलाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। यह भी विचारणीय है कि यह निर्णय तीन दशक बाद आया है। लोकतंत्र देश और संविधान का आत्मा है और जनमानस के विश्वास पर टिका हुआ है। इसलिए सांसदों और विधायकों द्वारा रिश्वत लेकर अनैतिक एवं आपराधिक आचरण संविधान और देश के विरुद्ध है और जनमानस के साथ विश्वासघात है। विभिन्न दलों के सांसदों और विधायकों के रिश्वत लेने के कई प्रकरण सामने आ चुके हैं। न्यायालयों में इनके निर्णय आने में दशकों का समय लगता है। संविधान में ऐसे अभियोगों के लिए दंड का प्रविधान हो, जिससे उनके सदन की सदस्यता समाप्त होने और सीमित अवधि के लिए कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगे तथा संसदीय लाभ पर भी रोक लगे। जो दंड सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को रिश्वत लेने पर लगता है, वही जनप्रतिनिधियों पर भी लागू हो। जहां तक संसद में विशेषाधिकार की बात है, तो भ्रष्ट और आपराधिक जनप्रतिनिधियों से इसकी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में भ्रष्ट और आपराधिक जनप्रतिनिधियों के लिए कोई स्थान नहीं है।

विनोद जौहरी, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

25 अरब डालर के सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत है भारत में अभी। जल्द ही यह मांग बढ़कर 100 अरब डालर की हो जाएगी।

आजकल

सेमीकंडक्टर का हब बनने की डगर पर

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने दो सेमीकंडक्टर यूनिट गुजरात में तथा एक असम में लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 1.26 लाख करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इन तीनों संयंत्रों से हर साल कुल 2602 करोड़ चिप बनेंगी। इससे न केवल घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक उपकरण, आटोमोबाइल, दूरसंचार और रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में आसानी से एवं किफायती कीमत पर चिप की आपूर्ति हो सकेगी, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत के प्रवेश का मार्ग भी खुलेगा

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था-टेली परफार्मेंस से संबद्ध

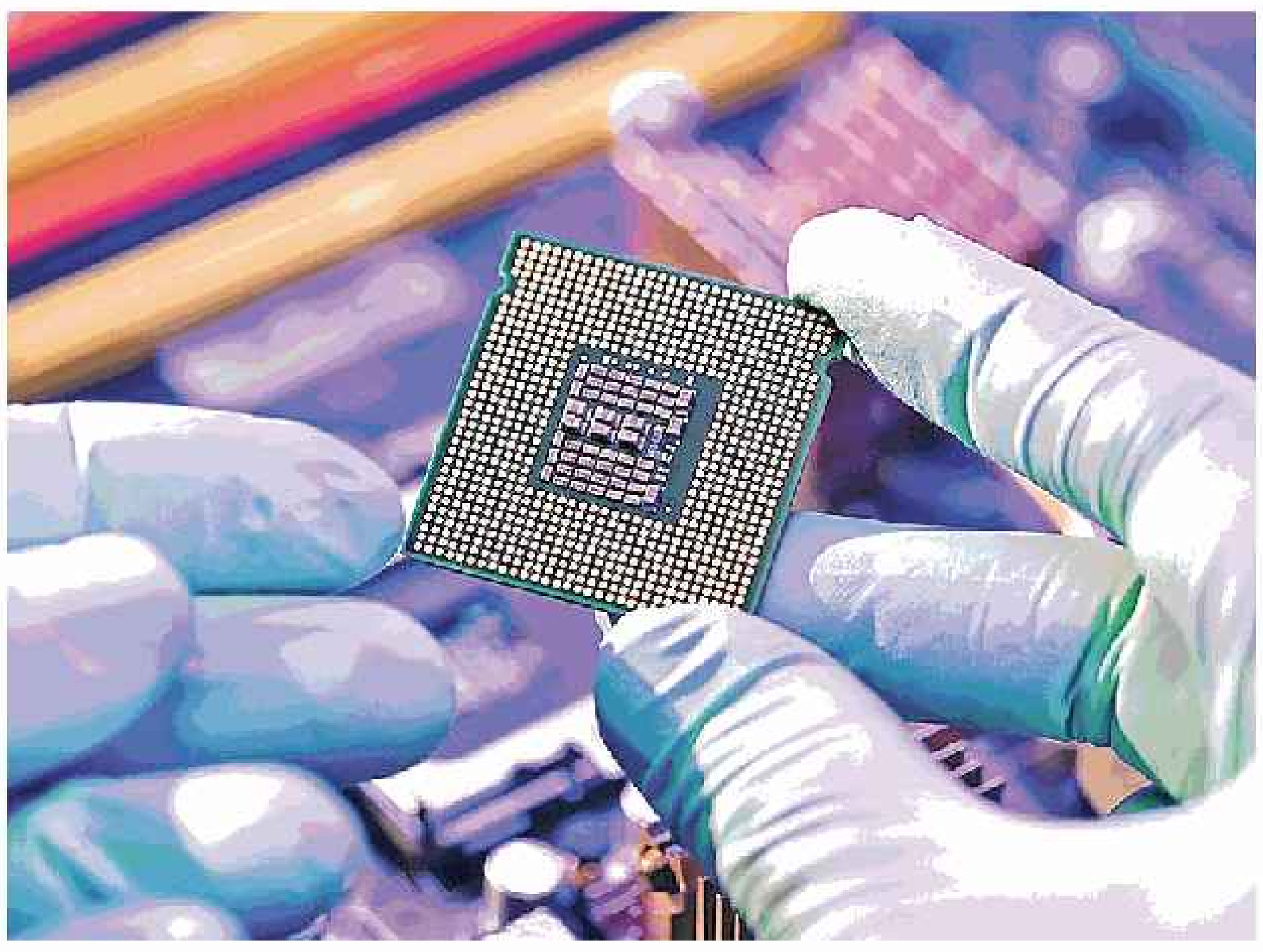

सेमीकंडक्टर के घरेलू निर्माण से देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी मिलेगी मदद। प्रतीकात्मक

विभिन्न इलेक्ट्रानिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले और आम बोलचाल में चिप कहे जाने वाले सेमीकंडक्टर की जो भारी मांग इस दौरान पैदा हुई है, उसने तकरीबन हर अर्थव्यवस्था को प्रेरित किया है कि वे इसके उत्पादन में हाथ आजमाएं। जिन देशों में इसकी मांग होने के बावजूद घरेलू स्तर पर विनिर्माण के कोई खास प्रबंध नहीं हैं, उनके लिए सेमीकंडक्टर की कमी संकट पैदा कर रही है। वजह यह है कि हर काम में डिजिटल निर्भरता बढ़ने के कारण चिप एक अनिवार्यता बन गई है, पर इसे बनाना आसान नहीं है। इस कारण इसके लिए ज्यादातर देश आयात पर निर्भर हैं। अब ज्यादा बेहतर यह माना जाने लगा है कि घरेलू स्तर पर ही इसकी इंडस्ट्री लगाई जाए ताकि इसकी नियमित आपूर्ति में कोई अड़चन नहीं आए। भारत ने जो राह पकड़ी है, वह इस मामले में काफी आशाजनक है।

हाल में केंद्र सरकार ने दो सेमीकंडक्टर यूनिट गुजरात में और एक असम में लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन तीनों संयंत्रों से हर वर्ष कुल 2602 करोड़ चिप बनेंगी। इससे न सिर्फ घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक उपकरण, आटोमोबाइल, दूरसंचार, रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में आसानी से एवं किफायती कीमत पर चिप की आपूर्ति हो सकेगी, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत के प्रवेश का रास्ता भी खुलेगा। इनमें टाटा समूह एवं ताइवान की कंपनी पावरचिप द्वारा गुजरात में लगाया जाने वाले प्लांट है। दूसरा संयंत्र असम में लगाया जाएगा। इसे टाटा समूह एक बड़ी आटोमोबाइल कंपनी के साथ मिलकर लगाएगा। तीसरा संयंत्र सीजी पावर और जापान की रेनेसा इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन संयुक्त तौर पर लगाएंगे। उक्त तीनों परियोजनाओं में कुल 1.26 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। वहीं इसके लिए एक अन्य कंपनी माइक्रोन की यूनिट पहले से लग रही है। सेमीकंडक्टर उद्योग को फलने-फूलने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं। इस उद्योग की पहली जरूरत डिजाइन इंजीनियरों की होती है। दुनिया में जितने सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े इंजीनियर हैं, उनमें से एक तिहाई (संख्या करीब तीन लाख) भारत में ही हैं। देश में करीब सौ विश्वविद्यालयों में सेमीकंडक्टर उद्योग के पाठ्यक्रम चलाने की शुरुआत की गई है, इससे बेहतरीन इंजीनियरों की आपूर्ति और बढ़ेगी। दूसरी जरूरत इस उद्योग के लिए फैब्रिकेशन सेंटर की होती है। तीसरी जरूरत होती है एटीएमपी यानी चिप बनाना, उसकी टेस्टिंग करना, मार्किंग करना और पैकेजिंग करके अंतिम उत्पाद बनाना। फैब्रिकेशन सेंटर की कमी को सरकार का ताजा फैसला पूरा करेगा। जबकि एटीएमपी भी स्थापित होने लगे हैं। इस तरह से सेमीकंडक्टर उद्योग की सारी जरूरतें भारत पूरी करने की दिशा में बढ़ रहा है। जहां भी सेमीकंडक्टर उद्योग पनपता है वहां इलेक्ट्रानिक उद्योग भी स्थापित होता है। उम्मीद है कि भारत में कई तरह के इलेक्ट्रानिक उपकरण बनाने वाली कंपनियां आएंगी। अभी भारतीय इलेक्ट्रानिक उपकरण उद्योग का बाजार 105 अरब डालर का है, जो अगले कुछ वर्षों में 300 अरब डालर का हो जाएगा। पूर्व में भी सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने की कोशिशें हुई थीं, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए 16,000 विभिन्न तरह की चीजों की जरूरत होती है। कई तरह की गैस चाहिए, अलग किस्म का पानी चाहिए, बेहद सूक्ष्मता से एवं अत्यंत सफाई से काम करने वाली प्रौद्योगिकी चाहिए होते हैं। अनुमान है कि भारत में अभी 25 अरब डालर के चिप की जरूरत है। जल्द ही यह मांग 100 अरब डालर की होगी। आज घर के पर्दे और स्विच बोर्ड से लेकर इलेक्ट्रिक कार और राकेट में चिप का इस्तेमाल होने लगा है। ईवी और प्रौद्योगिक का इस्तेमाल बढ़ने से इसकी मांग और बढ़ेगी।

सप्लाई का जोखिम घटाने की पहल : असम को इसके लिए चुनने की एक खास वजह है। यह स्थान ताइवान, मलेशिया, वियतनाम और सिंगापुर जैसे उन देशों के करीब है, जो सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग और टेस्ट की धुरी माने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2030 तक ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बढ़कर एक ट्रिलियन डालर पहुंचने का अनुमान है। सेमीकंडक्टर के निर्माण में भारत के प्रवेश से वैश्विक सप्लाई की श्रृंखला में जोखिम घटेगा और ग्लोबल सेमीकंडक्टकर इंडस्ट्री में भारत की भूमिका अहम होगी। मौजूदा समय में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, औद्योगिक और इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में उद्योग जगत की समग्र जरूरतें चिप पर निर्भर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलीजेस पर आधारित डिजिटलीकरण की मौजूदा तरक्की में भी सेमीकंडक्टर की अहम भूमिका है।

आत्मनिर्भरता की फैक्ट्री : भारत में अभी वैश्विक जरूरतों की तुलना में बहुत कम चिप बनाए जा रहे हैं। इससे भारत की अपनी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं पड़ रही हैं। इसके लिए भारत मुख्य रूप से ताइवान, चीन और अमेरिका पर निर्भर है। भारत सालाना करीब 1.90 लाख करोड़ रुपये के सेमीकंडक्टर दूसरे देशों (खासकर चीन-ताइवान) से मंगाता रहा है। हालांकि इसके लिए कई कोशिशें शुरू हो चुकी हैं जिससे कि देश इस मामले में आत्मनिर्भर हो सके। देश में सेमीकंडक्टर उद्योग की वृद्धि के लिए एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा रहा है। इसके लिए यानी सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री लगाने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने का एलान भी किया गया है। सेमीकर्डक्टर सप्लाई की एक श्रृंखला विकसित करने के इरादे से देश में सेमीकंडक्टर डिजाइन पर पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है। सेमीकंडक्टर का मामला कुछ ऐसा बन गया है कि इसे दुनिया की एक नई औद्योगिक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। जो देश सेमीकंडक्टर निर्माण और उसकी तकनीक में दूसरों से आगे नहीं हैं, आने वाले वक्त में न तो उनकी इलेक्ट्रानिक जरूरतें पूरी होंगी और न ही वहां रोजगार पैदा करने वाला विकास हो पाएगा।

पेट्रोल-सोने के बाद चिप का नंबर : सेमीकंडक्टर के निर्माण की ओर भारत का बढ़ना वस्तुतः एक बड़े बदलाव का भी द्योतक है। यह बदलाव उस विरोधाभासी विडबंना पर प्रहार है कि कंप्यूटर-आइटी में भारत खुद को हमेशा से अगुआ देश मानता रहा, लेकिन उसी क्षेत्र से जुड़े अहम उत्पाद-सेमीकंडक्टर के निर्माण में निहायत फिसड्डी रहा है। हमारे देश में पेट्रोल और सोने के बाद सबसे ज्यादा आयात इलेक्ट्रानिक साजो-सामान का होता है। हमारे देश में फरवरी 2021 से अप्रैल 2022 के बीच 550 अरब डालर के आयात बिल में अकेले इलेक्ट्रानिक्स वस्तुओं की हिस्सेदारी 62.7 अरब डालर थी। ऐसे में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटाप, नोटबुक्स और टेलीविजन से लेकर स्मार्ट फीचर वाली कारों और वाशिंग मशीन तक में लगने वाले सेमीकंडक्टर अगर भारत में ही बनने लगें तो ये चीजें बेहद सस्ती हो सकती हैं। हालांकि आज की तारीख में ताइवान और चीन जैसे देशों ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर रखा है। ताइवान तो दुनिया में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप का सबसे अग्रणी उत्पादक देश है। यहां तक कि खुद चीन भी अपनी सेमीकंडक्टर की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ मायनों में ताइवान पर निर्भर है। ताइवान की सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी 'ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी' (टीएसएमसी) दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप की मांग के बड़े हिस्से की पूर्ति करती है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले सभी चिप का आठ प्रतिशत ताइवान में बनता है। इसके बाद चीन और जापान का नंबर आता है। अच्छा है कि ताइवान और चीन के इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए हमारी सरकार टाटा और वेदांता जैसे समूहों को एक अवसर दे रही है।

सिलिकान शील्ड का रूपक : कहते हैं कि ताइवान को कब्जाने की ताक में बैठा चीन उस पर कोई सीधी सैन्य कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी वह खुद ताइवान से सेमीकंडक्टर आयात करने के लिए विवश है। इसीलिए ताइवान को चीन से बचाने वाली इस नीति को सिलिकान शील्ड का नाम दिया गया है। इस बारे में यह सच है कि सेमीकंडक्टर बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कोई नया देश इसे रातोंरात नहीं बना सकता है, लेकिन सही नीतियां अपनाकर और रास्ते में आने वाली बाधाओं को खत्म करके आयात पर निर्भरता को धीरे-धीरे खत्म किया जा सकता है। भारत चीन से 40 प्रतिशत इलेक्ट्रानिक आयात घटा सकता है-बशर्ते यहां कुछ चीजों पर ठोस अमल किया जाए। जैसे सबसे पहले तो पीएम गति शक्ति स्कीम के तहत मिलने वाली रियायतों को ईमानदारी से लागू किया जाए। साथ ही भारतीय उत्पादकों की इस भावना का ध्यान रखा जाए कि वे प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपने उत्पाद तैयार कर सकें। सेमीकंडक्टर का उत्पादन भारत में ही होने से न केवल भारत का आयात बिल कम होगा, बल्कि नौकरियों के सृजन के साथ मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी भारत की धाक जम सकेगी।

छोटी चिप का बड़ा धमाल

आज सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल हर किस्म के इलेक्ट्रानिक उपकरणों में किया जा रहा है। हालांकि एक दौर ऐसा भी था, जब इलेक्ट्रानिक उपकरणों में चिप नहीं होते थे। इस वजह से ऐसे तकरीबन सभी डिवाइस आकार में काफी बड़े, वजनी होते थे और काफी जगह घेरते थे। घरों में मौजूद डेस्कटाप कंप्यूटर, रेडियो एवं कैथोड-रे ट्यूब वाले टेलीविजन इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यही नहीं, सेमीकंडक्टर-रहित इलेक्ट्रानिक उपकरण काफी ज्यादा बिजली की खपत भी करते थे, लेकिन जब से इलेक्ट्रानिक उपकरणों का आकार घटाने, उन्हें संचालन और बिजली की खपत के मामले में दक्ष बनाने के प्रयास विज्ञान जगत ने शुरू किए तो सेमीकंडक्टर का उपयोग समझ में आया। सेमीकंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रानिक डिवाइस को स्लिम-ट्रिम करने में सफलता मिली। मोबाइल, लैपटाप, कंप्यूटर, टीवी, वाशिंग मशीन और यहां तक कि वे कारें भी सेमीकंडक्टर पर निर्भर हो गईं, जिनमें तमाम कार्यों का संचालन वन-टच यानी किसी बटन को छूने भर से होता है।

खरी-खरी

एक ऊबे हुए माननीय की व्यथा

डा. प्रदीप मिश्र

एक माननीय ऊबे हुए से थे। एक दर्द भरा नगमा गुनगुना रहे थे। गीत के भाव की गंभीरता इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही थी कि दल-बदल के लिए माननीय की डील फाइनल हो चुकी है। माननीय पिछले कुछ दिनों से पार्टी छोड़ने के संकेत लगातार दे रहे थे। वह ईमानदारी पर कुछ ज्यादा ही जोर देने लगे थे। उन्हें अपने चारों ओर के लोग अचानक ही बेईमान लगने लगे थे। वह सोते-जागते कभी भी बड़बड़ाने लगते, 'जब तक लोग ईमानदार नहीं होंगे राष्ट्र का विकास कैसे होगा? ईमानदारी पब्लिक का ही नहीं, नेताओं का भी नैसर्गिक गुण होना चाहिए। मुझे क्या मालूम था कि मैंने जिनका दामन थामा था वे सारे बेईमान निकलेंगे? इन बे-ईमानों साथ रहूंगा तो भगवान के पास कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा?'

माननीय ने पत्रकारों से कहा, 'वे सारे बेईमान थे इसलिए मेरा उनके साथ रह पाना संभव नहीं था। इसलिए मैंने उनका दामन छोड़ दिया।' 'अब किसका दामन पकड़ेंगे?' पत्रकारों ने पूछा। 'राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए किसी न किसी का दामन तो पकड़ना ही पड़ेगा। फलानी पार्टी का दामन ही इस दृष्टि से श्रेष्ठ है। उसके नेता दूरदर्शी, कर्मठ, विकास के प्रति प्रतिबद्ध और देशप्रमी हैं। इन्हीं कारणों से मैं उस पार्टी का दामन इस बार पकड़ने वाला हूं।' 'पिछली बार जब आपने इसी पार्टी का परित्याग किया था तब इसे भ्रष्ट पार्टी बताया था।' 'देखिए, ऐसा भ्रष्टाचार जो खुद की स्वार्थ-साधना हेतु किया जाता है, उसका मैं कट्टर विरोधी रहा हूं और आज भी हूं, लेकिन भ्रष्टाचार यदि राष्ट्र-आराधना के लिए हो तो वह स्वीकार्य होता है और उसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती।'

'असल बुराई भ्रष्ट-मानसिकता में है, क्योंकि यह परिवारवाद को जन्म देती है। परिवादवाद सामाजिक-ईमान को खंडित करता है। ऐसा होने पर आदमी के आचरण में संदिग्धता उत्पन्न होती है। यही संदिग्धता मनुष्यता को कुंठित करती है। और मैं इसी कुंठा का प्रखर विरोधी हूं?' इतना कह माननीय पार्टी की प्राथमिक सदस्यता का फार्म भरने लगे।

पोस्ट

कुछ दिन पहले यूपी कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे राज्य में पार्टी की कमान राजेश मिश्रा के हाथ में होनी चाहिए थी। अब राजेश मिश्रा जी ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अनुराग@VnsAnuTi

ए. राजा जैसे नेता देश के संविधान की शपथ लेते हैं और फिर उसे लेकर विभाजनकारी सोच का प्रदर्शन भी करते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि ईवीएम हैक हो गई। सत्या चौधरी@satyagodara

ए. राजा पर मुकदमा चलाकर उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। भारत की एकता और अखंडता पर दोहरा रवैया स्वीकार नहीं होना चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अलगाववाद की वजह से असंख्य लोगों ने जान गंवाई, कइयों के साथ दुष्कर्म हुआ, करोड़ों दरबदर हुए। अब और नहीं। रंगनाथ सिंह@rangnathsingh_

तारीख पर तारीख पड़ेगी? स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि चुनावी बांड खरीदने वालों के नाम बताने के लिए 30 जून तक समय दिया जाए। कोर्ट ने छह मार्च तक का समय दिया था। अगर मांग मान ली गई तो चुनाव के बाद ही देश को पता चलेगा कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया? मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar

उत्तराखंड डायरी

इधर कतार, उधर इंतजार

विकास धूलिया
स्टेट ब्यूरो चीफ, उत्तराखंड

अभी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उत्तराखंड में भाजपा ने पांच में से तीन लोकसभा सीटों के प्रत्याशी घोषित कर चुनावी माहौल गर्मा दिया है। राज्य में अमूमन भाजपा और कांग्रेस के मध्य ही मुकाबला सिमटता रहा है और इस बार भी परिदृश्य कुछ अलग नहीं। इतना जरूर है कि भाजपा में टिकट के दावेदारों की कतार लगी रही और इसी कारण दो सीटों पर अभी निर्णय नहीं हो पाया है। उधर, पिछले 10 वर्षों से राजनीतिक रूप से हाशिये पर खड़ी कांग्रेस के नेताओं में चुनाव लड़ने को लेकर उत्साह नहीं नजर आ रहा है। पार्टी के नेता चुनाव मैदान में उतरने से कतरा रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर इंतजार ही चल रहा है।

उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस, इन्हीं दो पार्टियों के पास व्यापक जनाधार एवं सांगठनिक ढांचा है। पिछले 23 वर्षों में यहां 10 वर्ष कांग्रेस और 13 वर्ष भाजपा सत्ता में रही। पांच विधानसभा चुनावों में तीन बार भाजपा और दो बार कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला। सपा ने यद्यपि एक बार वर्ष 2004 में हरिद्वार लोकसभा सीट जीती थी, लेकिन उसके बाद उसका प्रदर्शन मामूली रहा। संगठन के दृष्टिकोण से भी सपा के पास यहां कोई ताकत नहीं है। इसका अंदाजा बात से लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में अब तक हुए पांच विधानसभा चुनावों में उसने एक भी सीट पर जीत का स्वाद नहीं चखा। बसपा जरूर पहले दो विधानसभा चुनावों में स्वयं को तीसरी बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करने में सफल रही, पर पिछले तीन चुनावों में उसके प्रदर्शन का ग्राफ गिरा है। कांग्रेस न केवल पिछले दो लोकसभा, अपितु दो विधानसभा चुनावों में भी भाजपा से पराजित हुई, लिहाजा आगामी चुनाव को लेकर पार्टी में बहुत हलचल महसूस नहीं हो रही है। यह तब है जबकि पिछले चार चुनावों में कांग्रेस ही भाजपा के साथ मुख्य मुकाबले का हिस्सा रही। कांग्रेस को वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान का 38.31 प्रतिशत, 2009 में 43.13 प्रतिशत, 2014 में 34 प्रतिशत और 2019 में 31.40 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा। जागरण

भाजपा पांच में से तीन सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। पार्टी प्रदेश इकाई ने पांच सीटों पर कुल 55 दावेदारों का पैनल केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा था। पार्टी ने टिहरी से महारानी माला राज्यलक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा से अजय टम्टा और नैनीताल-ऊधम सिंह नगर सीट से अजय भट्ट को प्रत्याशी बनाया है। तीनों ही वर्तमान में इन सीटों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि भाजपा ने अपने सिटिंग सांसदों पर भरोसा जताया है। हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीटों पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। हरिद्वार से पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और पौड़ी गढ़वाल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वर्तमान में लोकसभा में हैं। ये दोनों तो इस बार भी टिकट के दावेदार हैं ही, इनके अलावा एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी जैसे बड़े नेताओं के नाम भी इन सीटों के लिए भेजे गए पैनल में शामिल हैं।

उधर, कांग्रेस में अभी पैनल के नाम तक सामने नहीं आ पाए हैं। एक-दो सीटों को छोड़ दिया जाए तो चुनाव लड़ने को तत्पर नेता नजर ही नहीं आ रहे हैं। साफ दिख रहा है कि कांग्रेस में न नेता और न उनके समर्थक ही चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह बात अलग है कि दावेदार अवश्य गिनाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी निष्क्रियता ने कांग्रेस नेतृत्व को पसोपेश में डाला हुआ है तो जनता भी हैरत में है। दावेदारों के दृष्टिकोण से यह स्थिति तब है, जब टिकट बंटवारे के लिए कांग्रेस हाईकमान निरंतर ही माथापच्ची में लगा है। दावेदारों की उदासीनता के बीच कार्यकर्ताओं की बेचैनी भी बढ़ गई है। उनके बीच यही प्रश्न तैर रहा है कि यदि सब ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस राज्य में भाजपा का विकल्प कैसे बन पाएगी?

पिछले चुनावों को देखें तो टिकट के लिए कांग्रेस में मारामारी का आलम रहता था। दावेदार पार्टी के क्षत्रपों और अपने आकाओं से संपर्क साधने को लगातार ही दिल्ली दौड़ लगाते रहते थे। वर्तमान में स्थिति एकदम उलट है। एक दौर में राज्य में मजबूत जनाधार रखने वाली कांग्रेस वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से नेपथ्य में पहुंचने के बाद तमाम प्रयासों के बावजूद इससे उबरने की राह नहीं तलाश पा रही है। वर्तमान में स्थिति देखें तो केवल हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल सीटों पर ही कुछ मुद्दे उठाकर कांग्रेस संगठन सक्रिय दिखा। साथ ही हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सक्रिय हैं। कुछ समय पहले पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भी ताल ठोंकी, लेकिन इन दिनों पाखरो टाइगर सफारी प्रकरण में वह ईडी की कार्रवाई से दो-चार हो रहे हैं। पौड़ी क्षेत्र में मनीष खंडूड़ी कुछ सक्रिय दिखे, लेकिन अन्य सीटों पर अपेक्षाकृत खामोशी सी है। इस दृष्टिकोण से देखें तो कांग्रेस हाईकमान के सामने इन परिस्थितियों से निपटने की भी चुनौती है। देखने वाली बात होगी कि वह इससे पार पाने के लिए क्या कदम उठाता है।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या पवन सिंह का मामला भाजपा की प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में खोट का सूचक है?

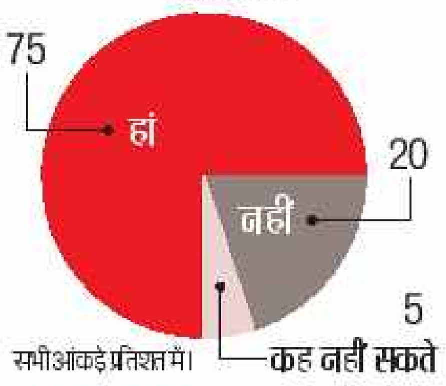

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या ए. राजा के बयानों से आइएनडीआइए को नुकसान उठाना पड़ेगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

मोदी ने तो देश को बना लिया परिवार,
कैसे इस परिवार से लड़ पाओगे यार!
लड़ पाओगे यार फैमिली अपनी लेकर,
भर पाया है देश वोट तुमको ही देकर।
अपना बच्चा आप उठाए घूमो गोदी,
यहां देश के साथ चल रहे पीएम मोदी!!

- ओमप्रकाश तिवारी

मंथन

नए भारत का विकासवादी चरित्र

गुलामी की मानसिकता से आज देश का अर्थतंत्र बाहर आया है तो इसका कारण बीते एक दशक में भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपरा को केंद्र में रखकर किए गए विकास कार्य हैं

प्रेम प्रकाश
वरिष्ठ पत्रकार

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने हाल में देश की आर्थिक वृद्धि दर को लेकर जो दावा किया है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर नई आशाएं जगाता है। वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में विकास दर का बढ़कर 8.4 प्रतिशत पहुंचना नए भारत की तस्वीर पेश करता है। भारत की इस आर्थिक कामयाबी का महत्व सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सुविचारित दृष्टि भी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अठारहवीं लोकसभा चुनाव से पहले एक खास विमर्श को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उनका यह विमर्श जहां 2047 तक विकसित भारत के संकल्प से जुड़ा है, वहीं वह बीते एक दशक के भीतर उभरे भारत के नए विकासवादी चरित्र की बात भी जोर-शोर से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस बात को संसद के अंदर और बाहर लगातार दोहरा रहे हैं कि बीते एक दशक में उन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपरा को केंद्र में रखकर विकास कार्य किए हैं। इस विजन और दृष्टिकोण के कारण गुलामी की मानसिकता से देश का अर्थतंत्र बाहर आया है। हाल में जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे तो आस्था और विरासत के साथ विकास को अपनी सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिनाया। कुछ इसी तरह की बात उन्होंने इससे पहले लखनऊ में चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी कही थी। ये प्रयास देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विभिन्नता के बीच आर्थिक विकास की क्षमता और संभावना के विकेंद्रित चरित्र को नए सिरे से उभारते प्रतीत हो रहे हैं।

स्वाभाविक तौर पर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के विजन और संकल्प के लिए जो बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वह है इसमें राज्यों का आर्थिक योगदान। नीति आयोग के गठन के पीछे भी तर्क और मकसद यही रहा है कि इससे सहकारी संघवाद की भावना को योजनागत और ढांचागत समर्थन मिलेगा। बजट पेश करने के समय एवं तारीख से लेकर कर ढांचा और योजना आयोग की बदली भूमिका देश में एक दशक में आए बदलावों की गवाही हैं। बीते करीब एक दशक में देश में आस्था और विकास की साझेदारी पर जोर लगातार बढ़ा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कई प्रदेशों के आर्थिक चरित्र के केंद्र में लोक आस्था को महत्ता प्रदान की है। गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इस दौरान कई ऐसी पहल हुई हैं, जो आस्था के पुराने केंद्रों को खासतौर पर पर्यटन और उससे जुड़े बाजार और रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण बना दिया है। हाल में प्रधानमंत्री द्वारा खासतौर पर यूपी के धार्मिक महत्व वाले शहरों में 86 हजार करोड़ रुपये की लागत से करीब 500 परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इन परियोजनाओं से करीब ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के निर्माण और अयोध्या धाम में श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद निवेशक धार्मिक शहरों में काफी रुचि दिखा रहे हैं।

इन दिनों राजस्थान, उत्तराखंड से लेकर दक्षिण के राज्यों में जहां भी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, वहां की भौगोलिक और सांस्कृतिक विलक्षणता के साथ आर्थिकी की चर्चा करते हैं। ऐसे मौकों पर वह डबल इंजन की सरकार के राजनीतिक लाभ गिनाने में भी नहीं चूकते हैं। गत दिनों जब वह दस लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के भूमि पूजन के लिए लखनऊ पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की इकोनमी बनाने के संकल्प को महत्वपूर्ण बताया। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और दो बार से नरेन्द्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी इसी राज्य में है। लिहाजा उनके प्रधानमंत्रित्व काल में जो बड़ा बदलाव देश में आया है उसमें यह प्रदेश स्वाभाविक तौर पर काफी आगे है। इसमें कहीं दो राय नहीं कि गुजरात का विकास माडल आज उत्तर प्रदेश की जमीन पर नया विस्तार पा रहा है। यह प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

वैसे नए विकासवादी रुझान के साथ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि बंगाल, बिहार और झारखंड जैसे राज्य इस दौरान विकास की दौड़ में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सके हैं। इन प्रदेशों की राजनीतिक स्थिति में लगातार एक ठहराव बना हुआ है। एक खास तरह के सामाजिक वर्गीकरण की राजनीति इन राज्यों को नए विकास मूल्यों और जरूरतों से जुड़ने नहीं दे रही है। यही वजह है कि इन प्रदेशों में विकास का समावेशी चरित्र गुणात्मक रूप से ज्यादा प्रभावी नहीं दिखता। हालांकि देश में इस बीच जनजातीय या पर्वतीय क्षेत्र में विकास के नए माडल छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे प्रदेशों में जरूर विकसित हुए हैं। 2018 में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के 'कालाहांडी डायलाग' से शुरू हुआ बदलाव का सिलसिला इस मायने में असरदार है।

अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ रहा नया भारत। फाइल

****

राष्ट्रीय संस्करण
बिजनेस
दैनिक जागरण
बुधवार 6 मार्च, 2024
www.jagran.com

एअर इंडिया-विस्तारा के विलय को सिंगापुर की मंजूरी

नई दिल्ली : सिंगापुर के प्रतिस्पर्धा नियामक ने मंगलवार को एअर इंडिया और विस्तारा के विलय को सशर्त मंजूरी दे दी। इस विलय की नवंबर 2022 में घोषणा की गई थी। विलय के तहत सिंगापुर एयरलाइंस एअर इंडिया की 25.1 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी। विस्तारा सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा समूह का संयुक्त उपक्रम है। सिंगापुर एयरलाइंस के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रस्तावित विलय की प्रक्रिया जारी है। (प्रेट्र)

30 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य वर्ग के सेगमेंट में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के साथ हम इस वर्ष के अंत तक भारत के 90 प्रतिशत ईवी बाजार में पहुंच की योजना बना रहे हैं।
— संजय गोपालकृष्णन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, बीवाईडी इंडिया

सेंसेक्स	73,677.13	▼ 195.16
निफ्टी	22,356.30	▼ 49.30
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 65,000	▲ ₹800
चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 74,900	▲ ₹900
डालर	₹ 82.90	बदलाव नहीं
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 82.63	

एक नजर में

केंद्रीय मंत्री ने समर्पित किए 201 सीएनजी स्टेशन

नई दिल्ली : केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को 17 राज्यों में स्थित 201 सीएनजी स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कंपनियों से ग्राहकों तक लाभ पहुंचाने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की ओर से जमा की गई कार्ययोजना के अनुसार, 2030 तक देश में करीब 17,500 सीएनजी स्टेशन और 12 करोड़ पीएनजी कनेक्शन होंगे। (एएनआइ)

आरबीआइ के उद्गम पोर्टल से अब तक 30 बैंक जुड़े

नई दिल्ली: आरबीआइ ने मंगलवार को बताया कि बिना दावे वाली राशि की जांच के लिए उसके पोर्टल उद्गम से अब तक 30 बैंक जुड़ चुके हैं। बिना दावे वाली करीब 90 प्रतिशत राशि इन्हीं बैंकों से जुड़ी है। यह पोर्टल ग्राहकों को विभिन्न बैंकों में जमा बिना दावे वाली राशि की एक ही प्लेटफार्म के जरिये जांच करने की सुविधा देता है। (प्रेट्र)

ब्लूमबर्ग के इंडेक्स में शामिल होंगी सरकारी प्रतिभूतियां

नई दिल्ली : ब्लूमबर्ग ने अपने उभरते बाजार (ईएम) इंडेक्स में भारत सरकार की प्रतिभूतियों को 31 जनवरी 2025 से शामिल करने की घोषणा की है। इस कदम से सरकार की कर्ज लागत में कमी आएगी। ब्लूमबर्ग एलपी के संस्थापक माइकल आर ब्लूमबर्ग ने कहा कि यह भारत के वित्तीय बाजारों के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक अनुमान के अनुसार, इससे अगले दो वर्षों में सरकारी प्रतिभूतियां 40 अरब डालर का विदेशी फंड आकर्षित कर सकेंगी। (प्रेट्र)

सेबी ने पीसी ज्वेलर्स को दिया कारण बताओ नोटिस

नई दिल्ली : पूंजी बाजार नियामक सेबी ने पीसी ज्वेलर्स को लिस्टिंग और डिस्क्लोजर से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस खातों के एनपीए होने, कानूनी मामले और समाधान योजना की जानकारी को लेकर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि उसने तिमाही नतीजों में पूरी जानकारी दे दी थी। (आइएएनएस)

2023 में महिलाओं ने लिया 19% ज्यादा लोन

कारोबारी और शिक्षा को छोड़कर सभी लोन श्रेणी में वृद्धि

रिपोर्ट

- पिछले वर्ष महिलाओं को पर्सनल लोन का औसत आकार 80 हजार रुपये रहा
- महिलाओं की ओर से लिए गए पर्सनल लोन में 2023 में 52 प्रतिशत की वृद्धि रही

मुंबई, प्रेट्र : 2023 में महिलाओं की ओर से लिए गए लोन में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही है। इस दौरान कुल लोन वितरण में 17 प्रतिशत की वृद्धि रही है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले क्रेडिट इन्फार्मेशन कंपनी क्रिफ हाई मार्क की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष पर्सनल और दोपहिया लोन में 26 प्रतिशत की सबसे ज्यादा वृद्धि रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में महिलाओं पर बकाया कुल लोन की राशि बढ़कर 30.95 लाख करोड़ रुपये रही है जो 2022 में 26 लाख करोड़ रुपये थी। पिछले वर्ष कारोबारी और शिक्षा लोन को छोड़कर सभी श्रेणियों में महिलाओं को लोन वितरण में वृद्धि रही है। महिलाओं को कारोबारी और शिक्षा लोन में क्रमशः 19 व एक प्रतिशत की कमी रही है। पिछले वर्ष महिलाओं को पर्सनल लोन में 52 प्रतिशत और संपत्ति गिरवी रखकर लोन लेने में 39 प्रतिशत की वृद्धि रही है। 2023 में महिलाओं पर बकाया पर्सनल लोन की राशि 26 प्रतिशत बढ़कर 12.76 लाख करोड़ रुपये रही है। पिछले वर्ष आरबीआइ ने पर्सनल लोन जैसे असुरक्षित लोन को लेकर चिंता जताई थी। साथ ही ऐसे लोन पर आरबीआइ ने बैंकों के लिए जोखिम भार को बढ़ा दिया था। उद्योग से जुड़े लोगों के अनुसार, पिछले वर्ष बड़ी संख्या में संभावित जोखिम वाले 50 हजार रुपये से कम के लोन वितरित किए हैं। महिलाओं को पर्सनल लोन का औसत आकार 80 हजार रुपये रहा है।

बड़ी संख्या में उद्यमी बनना चाहती हैं कामकाजी महिलाएं

मुंबई, प्रेट्र : आनलाइन मार्केटप्लेस इंडियालेंड्स के अनुसार, बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं उद्यमी बनने और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती है। महानगरों, टियर-1 और टियर-2 शहरों की 24-55 आयु वर्ग की 10,000 से अधिक कामकाजी महिलाओं के बीच किए गए एक सर्वे के मुताबिक 76 प्रतिशत ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है। सर्वे में शामिल 68 प्रतिशत महिला उद्यमियों ने कहा कि वे अपनी कंपनी के खातों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करती हैं और उनमें से केवल 32 प्रतिशत ही इसके लिए पेशेवरों/पतियों/परिवार के सदस्यों का सहारा लेती है। जब उनके निवेश व्यवहार की बात आती है तो 68.7 प्रतिशत उद्यमी महिलाएं अपना पैसा स्वयं निवेश करती हैं।

अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की संख्या अधिक

नई दिल्ली, प्रेट्र : मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने मंगलवार को कहा कि जिन कंपनियों की रेटिंग अच्छी है, उनके निदेशक मंडल में महिलाओं की संख्या अधिक है। मूडीज द्वारा 3,138 कंपनियों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि बीए और उससे ऊपर रेटिंग वाली कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी औसतन 29 प्रतिशत है जो 2023 के मुकाबले एक प्रतिशत अधिक है। हालांकि बीए और उससे नीचे रेटिंग वाली कंपनियों के निदेशक मंडल में औसतन 24 प्रतिशत महिलाएं हैं और पिछले वर्ष भी यही आंकड़ा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विकसित देशों में स्थित कंपनियों के बोर्ड में लिंग विविधता और क्रेडिट रेटिंग के बीच एक संबंध दिखाई पड़ता है, लेकिन विकासशील देशों में स्थिति कंपनियों में ऐसा नहीं है।

रिपोर्ट में एएए रेटिंग वाली 24, एए रेटिंग वाली 146, ए रेटिंग वाली 728, बीएए रेटिंग वाली 1,165, बीए रेटिंग वाली 582, बी रेटिंग वाली 394 और सीएए रेटिंग वाली 90 कंपनियों को शामिल किया गया है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बोर्ड में शामिल महिलाओं और उनके द्वारा व्यक्ति की गई राय एक अच्छे कारपोरेट गवर्नेंस का प्रतिनिधित्व करती है और यह क्रेडिट गुणवत्ता के लिए सकारात्मक है। यूरोपीय कंपनियों के निदेशक मंडल में महिलाओं की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत है जो 2023 में 33 प्रतिशत थी। उत्तरी अमेरिकी कंपनियों के निदेशक मंडल में महिलाओं की हिस्सेदारी 29 से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गई।

पिछले वर्ष बेरोजगारी दर घटकर 3.1 प्रतिशत रही

- 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर पिछले तीन सालों में सबसे कम
- मार्च, 2020 में देश के महामारी की चपेट में आने के बाद से रोजगार की स्थिति में सुधार हो रहा

नई दिल्ली, प्रेट्र : 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बेरोजगारी दर 2023 में घटकर 3.1 प्रतिशत हो गई। यह पिछले तीन सालों में सबसे कम है। कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, 2022 में बेरोजगारी दर 3.6 प्रतिशत थी जबकि 2021 में यह आंकड़ा 4.2 प्रतिशत था। मार्च, 2020 में देश के महामारी की चपेट में आने के बाद से रोजगार की स्थिति में सुधार हो रहा है।

सर्वे से पता चलता है कि महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर 2022 के 3.3 प्रतिशत से घटकर 2023 में तीन प्रतिशत हो गई। 2021 में यह आंकड़ा 3.4 प्रतिशत था। इसी तरह पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर 2022 में 3.7 प्रतिशत और 2021 में 4.5 प्रतिशत से घटकर 2023 में 3.2 प्रतिशत हो गई। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की कुल दर भी 2022 के 5.7 प्रतिशत और 2021 के 6.5 प्रतिशत से घटकर 2023 में 5.2 प्रतिशत हो गई। इसी तरह, ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 2022 में 2.8 प्रतिशत और 2021 में 3.3

प्रतिशत से घटकर 2023 में 2.4 प्रतिशत पर आ गई। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2022 में 52.8 प्रतिशत और 2021 में 51.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 56.2 प्रतिशत हो गई। श्रम बल जनसंख्या उस हिस्से का पता चलता है, जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए श्रम की आपूर्ति करता है या आपूर्ति की पेशकश करता है।

ज्यादा नियामकीय घेराबंदी नुकसानदायक

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने मंगलवार को कहा कि बहुत अधिक नियामकीय घेराबंदी आर्थिक वृद्धि को बाधित कर सकती है और एक विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा को बाधित कर सकती है। उन्होंने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के दो दिवसीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नियामकों को बहुत अधिक रूढ़िवादी और सतर्क नहीं होना चाहिए। इसकी जगह संबंधित क्षेत्रों में आकस्मिक घटना पर तेजी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

उन्होंने कहा, 'मैं भारत के भविष्य के बारे में बहुत आशावादी हूं, लेकिन मैं इस बात को लेकर भी बहुत सचेत हूं कि घेराबंदी के बिना अवसरों को पाने की बेलगाम कोशिश जोखिम पैदा कर सकती है और इसी तरह बहुत अधिक घेराबंदी से भी हम वहां (विकसित देश) तक नहीं पहुंच पाएंगे।' कोटक ने कहा कि अगले 20-25 वर्षों में 7.5-8 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण जरूरी है। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलना है तो हमें अपनी अपनी उद्यमशीलता और रचनात्मक भावनाओं की रक्षा और पोषण करने की बहुत जरूर है।

उदय कोटक

दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने कहा, अगले 20 से 25 वर्षों के दौरान तेज आर्थिक वृद्धि के लिए क्षमता निर्माण जरूरी

नियामकीय भागीदारी काफी महत्वपूर्ण : विजय शेखर

नई दिल्ली, प्रेट्र : फिनटेक फर्म वन97 कम्युनिकेशंस के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक मामले के बाद पहली बार नियामकीय भागीदारी की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। जापान में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने वन97 कम्युनिकेशंस को एशिया की दिग्गज कंपनी बनाने के लिए अपना दृष्टिकोण भी साझा किया। उन्होंने कहा कि अस्पष्टता कारोबार में तनाव लाती है। चीजें बहुत तेजी से बड़ी और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हम अपने नियामक को इसमें शामिल होते हुए बहुत खुशी से देख पाए हैं। हाल में आरबीआइ ने पेटीएम पेमेंट बैंक को 15 मार्च के बाद ग्राहकों के साथ नए लेनदेन करने से रोक दिया है।

800 रुपये बढ़कर नए शिखर पर पहुंचा सोना

नई दिल्ली, प्रेट्र : मजबूत वैश्विक संकेतों के दम पर घरेलू बाजार में मंगलवार को सोना 800 रुपये बढ़कर 65 हजार रुपये प्रति दस ग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। एचडीएफसी सिक्युरिटीज के अनुसार, दिल्ली में चांदी में भी 900 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है और अब यह 74,900 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना एक प्रतिशत बढ़कर 2,110 डालर प्रति औंस और चांदी भी बढ़कर 23.88 डालर प्रति औंस पर पहुंच गई है। दूसरी ओर, आइटी और एफएमसीजी क्षेत्र के शेयरों में बिकवाली के चलते बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स चार दिनों की वृद्धि के बाद मंगलवार को 195.16 अंक गिरकर 73,677.13 के स्तर पर बंद हुआ।

सेवा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में फरवरी के दौरान रही गिरावट

- बिक्री में नरमी से सेवा क्षेत्र का पीएमआइ इंडेक्स गिरा
- सेवा कंपनियों को विदेश से मिलने वाले नए कारोबार में बढ़ोतरी हुई

नई दिल्ली, प्रेट्र : कारोबारी गतिविधियों, बिक्री और नौकरियों में नरमी के चलते फरवरी में सेवा क्षेत्र की वृद्धि सुस्त पड़ गई। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया सेवा व्यवसाय गतिविधि सूचकांक फरवरी में 60.6 रहा, जो इससे पहले जनवरी में 61.8 था। खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआइ) की भाषा में 50 से अधिक अंक का अर्थ विस्तार, जबकि 50 से कम संकुचन को दर्शाता है।

एचएसबीसी की अर्थशास्त्री इनेस लैम ने कहा, 'भारत की सेवा पीएमआइ से पता चलता है कि सेवा क्षेत्र में विस्तार की गति जनवरी के मुकाबले फरवरी में कम हो गई है।' सर्वे के मुताबिक फरवरी में व्यावसायिक गतिविधि सूचकांक में कमी आई, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह मजबूत बना रहा। भारत में सेवा कंपनियों को विदेश से मिलने वाले नए कारोबार में लगातार तेरहवें महीने वृद्धि हुई। सर्वेक्षण के मुताबिक भविष्य की व्यावसायिक गतिविधि के लिए सेवा कंपनियों का पूर्वानुमान सकारात्मक रहा, हालांकि यह पहले के मुकाबले थोड़ा कमजोर पड़ गया। लैम ने आगे कहा कि इनपुट कीमतों की वृद्धि दर कम होने से सेवाओं के बदले ली जाने वाली कीमतें 24 महीनों में सबसे धीमी दर से बढ़ीं। एचएसबीसी इंडिया कंपोजिट पीएमआइ आउटपुट इंडेक्स जनवरी में छह महीने के उच्चस्तर 61.2 से गिरकर 60.6 पर आ गया, जो विस्तार में नरमी का संकेत देता है।

जेएम फाइनेंशियल पर शेयर की एवज में लोन देने पर लगाई रोक

मुंबई, प्रेट्र : नियमों का उल्लंघन करने वाली फिनटेक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर आरबीआइ की सख्ती जारी है। अब केंद्रीय बैंक ने जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को शेयर, डिबेंचर और आइपीओ पर किसी भी प्रकार का लोन मंजूर और वितरण करने पर रोक लगाई गई है। आरबीआइ ने मंगलवार को कहा कि कंपनी अपने मौजूदा लोन खातों से संग्रह और अन्य कार्य जारी रख सकती है।

आरबीआइने कहा कि कंपनी की ओर से आइपीओ और गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूति (एनसीडी) के लिए लोन मंजूरी में कुछ गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। सेबी की सूचना की समीक्षा के बाद यह रोक लगाई गई है।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

कर्नाटक में तेजाब पीड़िताओं को चार-चार लाख रुपये मुआवजा

मंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को दक्षिण कन्नड़ जिले में कडाबा स्थित सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी (पीयू) कालेज में तेजाब हमले की शिकार तीन छात्राओं को मुआवजे के रूप में चार-चार लाख रुपये देने की घोषणा की। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने अस्पताल में भर्ती तीनों छात्राओं से मुलाकात की। मुआवजे के अलावा उनकी चिकित्सा का खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी। (प्रेट्र)

केरल में एक ही परिवार के पांच सदस्य घर में मृत मिले

पाला : केरल के कोट्टायम जिले के पाला क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच सदस्य एक घर में मृत पाए गए। मरने वालों में तीन बच्चे शामिल हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि घर का मुखिया जयसन पेशे से ड्राइवर है। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने आशंका जताई कि जयसन ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या करने के बाद फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली। (एएनआइ)

केरल में छात्र की मौत को लेकर डीन, सहायक वार्डन निलंबित

वायनाड : पूकोडे पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान कालेज के डीन एमके नारायण और सहायक वार्डन आर कांतनाधन को मंगलवार को निलंबित कर दिया गया। केरल पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति पीसी शशींद्रन ने सिद्धार्थथन जेएस की आत्महत्या को लेकर यह कदम उठाया है। आत्महत्या में सत्ताधारी माकपा के छात्र संगठन एसएफआइ का हाथ होने के आरोप में पूरे केरल में हंगामा हुआ है। (प्रेट्र)

आइएसआइ को सूचनाएं देने वाले को छह साल की सजा

लखनऊ : पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ को भारतीय सेना की सूचनाएं देने वाले मो राशिद को छह साल की सजा और सुनाने के साथ ही छह हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एनआइए विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने दिए। राशिद को पाकिस्तान निवासी उसकी प्रेमिका से कराने व पैसे का लालच देकर जाल में फंसाया था। (जासं)

भारत से चीन में इंसानी बाल की तस्करी में मिले हवाला साठगांठ के सुराग

- ईडी ने फरवरी 2022 में हैदराबाद व मिजोरम में छापेमारी की थी
- मनी लांड्रिंग मामले की विशेष अदालत ने ईडी के साक्ष्यों का संज्ञान लिया

नई दिल्ली, प्रेट्र : ईडी ने एक हवाला साठगांठ का भंडाफोड़ किया है जिसके तहत भारत से चीन और अन्य देशों में इंसानी बाल की तस्करी से कमाए धन का इस्तेमाल म्यांमार से सुपारी तस्करी के लिए किया जाता था। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि इंसानी बाल की तस्करी की मनी लांड्रिंग जांच के दौरान यह साठगांठ सामने आई।

ईडी ने पिछले साल अगस्त में हैदराबाद के नामपल्ली में मनी लांड्रिंग मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था जिसमें कथित साठगांठ के साक्ष्य रिकार्ड में लाए गए। ईडी ने सोमवार को बताया, विशेष अदालत ने एक मार्च को मिजोरम के चम्फाई जिले के निवासी लुकास थांगमंगलियाना, हैदराबाद की कंपनी नायला फैमिली एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और 16 अन्य आरोपितों के खिलाफ दायर अभियोजन शिकायत और ईडी के साक्ष्यों का संज्ञान लिया। हैदराबाद पुलिस द्वारा नायला फैमिली एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने इस मामले में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी के मुताबिक पुलिस ने कंपनी के विरुद्ध इंसानी बाल निर्यात करने के लिए ''बेनामी'' आयात निर्यात कोड (आइईसी) का इस्तेमाल करने, फर्जी पहचान के आधार पर धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज का उपयोग करने के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा हैदराबाद हवाईअड्डे से और मिजोरम में भारत-म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भूमि मार्ग से म्यांमा, बांग्लादेश, वियतनाम और चीन में इंसानी बाल की तस्करी के आरोप भी हैं। जांच में पाया गया कि भारत से म्यांमार तक इंसानी बाल और उर्वरकों की तस्करी के लिए थांगमंगलियाना ने मिजोरम में अंतरराष्ट्रीय सीमा को अवैध तरीका अपनाया। उसने म्यांमार से भारत में सुपारी की तस्करी में म्यांमार के निवासियों की भी मदद की और हवाला नेटवर्क के माध्यम से नकद भुगतान की व्यवस्था की। थांगमंगलियाना द्वारा संचालित ''हवाला नेटवर्क के माध्यम से भुगतान'' की प्रणाली के बारे में बताया गया है कि थांगमंगलियाना के सहयोगियों को भारत से म्यांमार में तस्करी करके लाए गए इंसानी बाल और उर्वरकों के खरीदारों से क्यात (म्यांमा की मुद्रा) में भुगतान मिलता था। म्यांमार से तस्करी की गई सुपारी के लिए वे स्थानीय भारतीय खरीदारों से रुपये में भुगतान लेते थे। भारत में सुपारी के खरीदारों से जो रुपये में भुगतान होता था, उससे इंसानी बालों के भारतीय विक्रेताओं को भुगतान किया जाता था। इस मामले में ईडी ने फरवरी 2022 में हैदराबाद और मिजोरम में विभिन्न परिसरों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 1.21 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई थी। ईडी ने 100 से अधिक बैंक खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी थी जिनमें 7.85 करोड़ रुपये जमा थी।

ईडी ने किया साठगांठ का भंडाफोड़। फाइल

अवैध आव्रजन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामलों में ईडी ने फिर की छापेमारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : ईडी ने भारतीयों को अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भेजने वाले अवैध आव्रजन से संबंधित मनी लांड्रिंग मामलों में दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के 29 ठिकानों पर छापेमारी की। सभी स्थानों पर गत एक मार्च को तलाशी अभियान चलाया गया। गत जनवरी और फरवरी में भी ईडी ने अवैध आव्रजन के मामले में दिल्ली और गुजरात के 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने बताया, आरोपितों, उनके सहयोगियों, आव्रजन सलाहकारों और लेखा परीक्षकों के परिसरों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान प्रापर्टी से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, कई असली पासपोर्ट, अज्ञात लोगों के पहचान पत्र और दो लग्जरी वाहनों को जब्त किया गया। आरोपितों, संदिग्धों, उनके सहयोगियों, रिश्तेदारों और उनकी कंपनियों के 50.10 लाख रुपये वाले बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। ईडी का यह मामला गुजरात पुलिस द्वारा भरतभाई उर्फ बाबी पटेल, राजूभाई बेचारभाई प्रजापति, भावेश अशोक भाई पटेल और कुछ अन्य मुख्य आरोपितों के खिलाफ दर्ज तीन मुकदमों से उपजा है।

रेलवे में तैनात दिव्यांग कर्मचारियों के तबादले पर रोक

जासं, अंबाला : रेलवे ने कुछ शर्तों के साथ दिव्यांग कर्मचारियों को तबादला या रोटेशनल तबादला से बाहर किया है। इस संबंध में सभी जोन के महाप्रबंधक को लेटर जारी किया गया है। अब पर्सनल विभाग ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार करेगा। ऐसे दिव्यांग कर्मचारी, जिनके परिवार के सदस्य उन पर आश्रित हैं और किसी बीमारी के चलते उनको देखभाल की जरूरत है तो उनको तबादले के नियमों में राहत मिलेगी। निर्देशों में रेलवे बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2023 में दिए गए एक फैसले का भी जिक्र किया गया है। ऐसा ही एक केस दिल्ली हाईकोर्ट में भी आया था, जिसमें छत्तीसगढ़ तबादला किए गए एक दिव्यांग कर्मचारी ने अपील दायर की थी। उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्थानांतरण के आदेश रद कर दिए गए थे।

पीएफए के पदाधिकारी ने कहा- मुझ पर हो सकता है मूसेवाला जैसा हमला

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

एल्विश सांप प्रकरण

एल्विश सांप प्रकरण में मंगलवार को सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता ने जिला अदालत को मामले की पैरवी के दौरान अपने ऊपर जानलेवा हमला होने के डर से लंबी तारीख लगाने के लिए पत्र लिखा है। मामले में मंगलवार को अदालत में सुनवाई होनी थी। अब 28 मार्च को सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज राणा की अदालत में चल रही है।

मंगलवार सुबह पीएफए के पदाधिकारी सौरभ गुप्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज राणा को पत्र लिखकर कहा कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। अदालत में मामले की पैरवी के लिए आने-जाने के दौरान सिद्धू मूसेवाला व नफे सिंह जैसा हमला हो सकता है। कुछ समय पहले ही उन्होंने वन्य जीव तस्करी और रेव पार्टी में सांपों का जहर बेचने के मामले दर्ज कराए हैं। उन्होंने यह पत्र पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के साथ ही गुरुग्राम के जिला सत्र एवं न्यायाधीश सूर्य प्रताप सिंह को भेजा है। उन्होंने हरियाणा पुलिस और उप्र को अपनी सुरक्षा के लिए लिखा है। कहा कि वे पुलिस की सुरक्षा न मिलने तक इस मामले में पैरवी करने में असमर्थ हैं। बता दें कि 32 बोर गाने में एल्विश यादव के पास विदेशी नस्ल के सांप दिखे थे। इसको लेकर उन्होंने एल्विश पर केस दर्ज करने की मांग की है।

एल्विश यादव के हाथ में सांप। जागरण आर्काइव

चेक बाउंस मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल सुलह को तैयार

राज्य ब्यूरो, रांची : चेक बाउंस की आरोपित फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी दिग्विजय नाथ शुक्ला की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान उनके अधिवक्ता ने शिकायतकर्ता से सुलह करने की बात कही। इस पर शिकायतकर्ता के वकील विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव ने अदालत में कहा कि कागज पर हस्ताक्षर कर भेजने से नहीं, बल्कि यहां उपस्थित होकर बताना होगा। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि छह मार्च निर्धारित की है।

मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज होने के बाद अमीषा पटेल एवं कुणाल ग्रूमर का बयान दर्ज किया जाना है। इसके लिए दोनों को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बयान दर्ज करने की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन दोनों नहीं आए। बता दें, रांची के अरगोड़ा निवासी अजय सिंह ने देसी मैजिक नामक फिल्म बनाने के नाम पर अमीषा पटेल को दो करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन फिल्म नहीं बनी। इसके बाद अमीषा से पैसे वापस मांगा गया। वापसी के लिए जो दो चेक दिए, वह बाउंस कर गया।

खाने के साथ बोतलबंद पानी देना मानसिक प्रताड़ना

बलवान शर्मा, नारनौल

- उपभोक्ता फोरम ने होटल हाईवे किंग के संचालक पर लगाया 60 हजार रुपये जुर्माना
- शिकायतकर्ता को जग में पानी न देकर जबरन दिया बोतलबंद पानी, जीएसटी भी वसूला

दिल्ली जयपुर हाइवे पर निमराना स्थित होटल हाई-वे किंग को नारनौल के एक उपभोक्ता को खाने के साथ निश्शुल्क पानी के बजाय बोतलबंद थोपना महंगा पड़ गया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला देते हुए पानी की बोतल की एवज में वसूले गए 19.5 रुपये नौ प्रतिशत सालाना ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही होटल संचालक को शिकायतकर्ता को मानसिक प्रताड़ना पहुंचाने की एवज में 40 हजार रुपये और 20 हजार रुपये वकील खर्च के रूप में भुगतान करना होगा। उपभोक्ता फोरम का यह फैसला नजीर के रूप में देखा जा रहा है। इस तरह की समस्याएं होटलों में खाना खाने वाले सैकड़ों उपभोक्ताओं के सामने भी आती हैं। शिकायतकर्ता एडवोकेट साकेत मक्कड़ के अनुसार, वह अपने साथी अधिवक्ता नवनीत और मालाराम और दो अन्य साथियों के दो जनवरी 2022 को दिल्ली जा रहे थे। वह निमराना रुके और होटल हाई-वे किंग में खाना खाने पहुंचे। उन्होंने होटल के वेटर से पीने के लिए पानी मांगा। वेटर ने उन्हें जग में पानी देने की बजाए बोतलबंद पानी दे दी। शिकायतकर्ता ने वेटर से पानी का जग देने की बात कही तो वेटर ने यह पानी देने से मना कर दिया और कहा कि इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। साथ ही पानी की बोतल का अलग से शुल्क देना होगा। उन्होंने होटल के कर्मचारियों को इसकी शिकायत की तो उन्होंने भी मुफ्त में पानी देने की सुविधा नहीं होने की बात की। खाना खाने के बाद होटल के मैनेजर ने पानी की बोतल के एवज में 19.5 रुपये जीएसटी सहित चार्ज कर लिए। इसका विरोध किया गया पर कोई समाधान नहीं दिया गया। पीड़ित पक्ष ने आरोपित होटल संचालक को पहले कानूनी नोटिस भेजे और इसके बाद 29 अगस्त, 2022 को उन्होंने उपभोक्ता फोरम में केस फाइल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए फोरम ने होटल हाई-वे किंग पर जुर्माना लगाया है।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नारनौल। जागरण आर्काइव

****

27 फरवरी से श्रीलंका की सद्भावना यात्रा पर पहुंचे भारतीय युद्धपोत समर्थ और अभिनव मंगलवार को कोलंबो बंदरगाह से रवाना हो गए। भारतीय तटरक्षक के अनुसार, युद्धपोतों ने यात्रा के दौरान श्रीलंका तटरक्षक के साथ विभिन्न स्तर पर संवाद किया और समुद्री प्रदूषण पर केंद्रित संयुक्त प्रशिक्षण आदि कई गतिविधियों में भाग लिया।

गाजा में युद्धविराम पर नहीं बन सकी बात, काहिरा में वार्ता का समय बढ़ा

रमजान करीब होने से तीसरे दिन समझौते की उम्मीद में रुके फलस्तीनी वार्ताकार

बोले, 40 दिन के युद्धविराम के साथ कुछ बंधकों को छोड़े जाने का है प्रस्ताव

जीवित बंधकों की सूची सौंपने की मांग को लेकर वार्ता में शामिल नहीं है इजरायल

गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजरायली हमले में घर ध्वस्त होने के बाद मलबे से सामान को निकालता व्यक्ति। एएफपी

काहिरा, रायटर : मिस्र की राजधानी काहिरा में युद्धविराम के लिए हमास के साथ चल रही वार्ता में मंगलवार तक कोई नतीजा नहीं आ सका। समय सीमा खत्म होने के बाद भी हमास के वार्ताकार तीसरे दिन भी काहिरा में किसी समझौते की उम्मीद में मौजूद हैं। मुस्लिमों का पवित्र महीना रमजान करीब होने के कारण हमास कुछ बंधकों की रिहाई बदले युद्धविराम चाहता है। वार्ता में मध्यस्थ के रूप में मिस्र, कतर और अमेरिका के अधिकारी शामिल थे लेकिन इजरायल कुछ शर्तें पूरी न होने से भाग नहीं ले रहा था।

युद्धविराम को लेकर काहिरा में सोमवार को वार्ता शुरू हुई थी। पहले चरण में 40 दिन के युद्धविराम के साथ दर्जनों बंधकों को छोड़े जाने का प्रस्ताव है। मिस्र के सुरक्षा सूत्रों ने सोमवार को कहा था कि वह बिना इजरायली प्रतिनिधि के भी वार्ता को जारी रखने को लेकर इजरायल के संपर्क में है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि गाजा में लोगों को अमानवीय स्थिति से निकालने के लिए छह हफ्ते का युद्धविराम जरूरी है।

हमास के वरिष्ठ अधिकारी बासेम नईम ने कहा, वार्ता के दौरान हमास की ओर से मध्यस्थों के सामने युद्धविराम का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अब इजरायल की ओर से इसपर प्रतिक्रिया का इंतजार है। उन्होंने कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समझौते के इच्छुक नहीं हैं, गेंद अब अमेरिका के पाले में है कि वह इजरायल पर वार्ता के लिए दबाव डाले। वहीं, इजरायल ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार किया है। सूत्रों के अनुसार, इजरायल ने जीवित बंधकों के नामों की पूरी सूची न मिलने के कारण वार्ता में शामिल न होने का फैसला लिया था। नईम ने कहा कि यह बिना युद्धविराम के यह असंभव है।

यूएन को इजरायल महिलाओं से यौन हिंसा के साक्ष्य मिले : संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इजरायल में सात अक्टूबर, 2023 को हुए हमले में इजरायली महिलाओं के जघन्य यौन शोषण के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। संघर्ष में यौन हिंसा के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत प्रमिला पैटन के नेतृत्व में एक टीम को यह मानने के लिए उचित आधार मिला कि हमास ने दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न किया है। पैटन ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में रिपोर्ट पेश की। टीम ने कहा, उसने किसी भी पीड़िता से मुलाकात नहीं की। हालांकि, उसने पीड़िताओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। अधिकांश साक्ष्य परिस्थितिजन्य हैं। इधर, इजरायली इतिहास में पहली बार एक महिला हर्जी हलेवी को इजरायली वायु सेना बेस की कमान सौंपी गई है। इजरायली रक्षा बलों ने सोमवार को घोषणा की कि उसे केवल उसकी रैंक और उसके नाम के पहले अक्षर लेफ्टिनेंट कर्नल ''गिम्मेल'' से पहचाना जा सकता है।

खान यूनुस में इजरायली हमले में 17 की मौत

गाजा में युद्धविराम के प्रयासों के बीच इजरायली हमले जारी हैं। दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में इतरायल के हवाई हमले में मंगलवार को 17 लोगों की मौत हो गई है। नागरिक सुरक्षा ने बचावकर्मियों के फुटेज प्रसारित किए हैं, जिसमें एक घर के मलबे से मृत और घायल लोगों को निकाला जा रहा था। जिसमें एक बच्चा भी शामिल था जिसके चेहरे पर खून लगा था और वह हिल नहीं रहा था। पास के यूरोपीय अस्पताल ने मंगलवार को कहा कि उसे रात भर में 17 शव मिले हैं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, युद्ध में अब तक 30,631 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और 72,043 लोग घायल हुए हैं।

हिजबुल्ला के हमले में एक भारतीय की मौत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लेबनान से सोमवार को दागी गई मिसाइल में एक भारतीय की मौत और दो भारतीयों के घायल होने के बाद तेलअवीव स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार को एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने कहा, मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए इजरायल में रहने वाले सभी भारतीयों को खासतौर पर उत्तरी व दक्षिणी सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों को या वहां काम पर जाने वाले भारतीयों को सुरक्षित इलाकों में जाने का सुझाव दिया जाता है। भारत इजरायल के सुरक्षा अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है ताकि सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सोमवार को दोपहर 11 बजे मार्गोलियट में एंटी टैंक मिसाइल हमले में केरल निवासी 30 वर्षीय निबिन मैक्सवेल की मौत हो गई थी जबकि बुश जोसेफ जार्ज और पाल मेल्विन नाम के दो भारतीय मजदूर घायल हो गए। इस इलाके में कई भारतीय खेतों में काम करते हैं। उधर, नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास ने कहा है कि लेबनान के शिया आतंकी संगठन हिजबुल्ला की तरफ से किए गए हमले की जद में आने से एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है। यह भारतीय मार्गोलियट इलाके में काम कर रहा था। इजरायल ने कहा कि वह घायल भारतीयों की पूरी मदद करेगा। इजरायली दूतावास ने कहा, वह घटनाक्रम से बेहद दुखी है और उसने मृतक व घायल लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। हिजबुल्ला के हमले में मारे गए केरल के कोल्लम निवासी निबिन मैक्सवेल के पिता ने बताया कि बेटा दो माह पहले ही इजरायल में पोल्ट्री फार्म में काम करने के लिए गया था। पहले बेटा दुबई में था लेकिन पिछले करीब सवा दो महीने पहले बड़े बेटे के इजरायल जाने के बाद छोटा बेटा निबिन भी वहां चला गया था। सोमवार को पहले बड़े बेटे ने निबिन के घायल होने और फिर मौत की सूचना दी।

हिजबुल्ला के हमले में मारे गए निबिन मैक्सवेल। फाइल/एएनआइ

गाजा में संघर्ष को लेकर भारत ने जताई गहरी चिंता

यूएन में रुचिरा कंबोज ने कहा-भारत द्विराष्ट्र समाधान का समर्थक

संरा में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। एएनआइ

यूएनआरडब्ल्यूए के विरुद्ध हालिया आरोप को भारत ने बेहद चिंताजनक बताया

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र: संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में भारत ने गाजा संघर्ष को लेकर गहरी चिंता जताई है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि गाजा में पिछले करीब पांच महीने से जारी संघर्ष को लेकर भारत बेहद चिंतित है। युद्ध में आम नागरिकों की मौत और उससे उपजा मानवीय संकट स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, भारत उस द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फलस्तीन लोग इजरायल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आजाद देश में स्वतंत्र रूप से रह सकें।

कंबोज ने सोमवार को 'वीटो के उपयोग' पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कहा, 'इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की जान चली गई है। कंबोज ने कहा, 'मानवीय संकट गहराने से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है।' उन्होंने बताया, भारत की ओर से फलस्तीन लोगों के लिए मदद मुहैया कराई गई और यह मदद जारी रहेगी। भारत संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के विशेष आग्रह पर विचार कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा, इस एजेंसी के विरुद्ध हालिया आरोप बेहद चिंताजनक हैं। बता दें कि फलस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली यूएनआरडब्ल्यूए पर यह आरोप लगा है कि इस एजेंसी के कुछ कर्मचारी सात अक्टूबर को इजरायल में हुए हमले में शामिल थे।

पाकिस्तान को मिले वैश्विक आतंकी फैक्ट्री का दर्जा : भारत

यूएनएचआरसी में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाक को फटकारा

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में पाकिस्तान के जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि उसे अपने बेहद खराब मानवाधिकार रिकार्ड पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और उसे 'वैश्विक आतंकी फैक्ट्री' का विश्व वैश्विक दर्जा दिया जाना चाहिए।

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में अवर सचिव जगप्रीत कौर ने सोमवार को यूएनएचआरसी के 55वें नियमित सत्र में सामान्य बहस में देश के जवाब देने के अधिकार का प्रयोग किया। इससे पहले पाकिस्तान ने इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआइसी) की ओर से अपने बयान में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया था। कौर ने कहा, 'हमने इस सत्र के दौरान पूर्व में मंच संभाला था और एक विशेष प्रतिनिधिमंडल द्वारा भारत के बारे में गलत टिप्पणियों का जवाब देने में परिषद का समय बर्बाद करने के प्रति अपनी अनिच्छा से अवगत कराया था। यह प्रतिनिधिमंडल ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके पास योगदान देने के लिए कुछ भी रचनात्मक नहीं है।'

पाकिस्तान का नाम लिए बिना, 'कौर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह देश भारत की आलोचना जारी रखता है, जिसमें अपने स्वयं के राजनीतिक रूप से प्रेरित एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ओआइसी के मंच का दुरुपयोग करना भी शामिल है।' उन्होंने कहा, 'हम ऐसी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देकर इनको बढ़ावा देना नहीं चाहते और केवल उस प्रतिनिधिमंडल से अपने स्वयं के बेहद खराब मानवाधिकार रिकार्ड और दुनिया की आतंकवाद फैक्ट्री के रूप में उनकी वैश्विक पहचान पर आत्मनिरीक्षण करने का आग्रह करने के लिए फिर से इस मंच का सहारा ले रहे हैं।'

10 मई के बाद मालदीव में न वर्दी में, न सादे कपड़ों में कोई भारतीय सैनिक रहेगा : मुइज्जू

कुछ दिन पहले ही हल्के हेलीकाप्टर का संचालन करने एक भारतीय असैन्य दल पहुंचा है मालदीव

समझौते के तहत मालदीव से 10 मई तक सभी भारतीय सैनिकों की होनी है वापसी

माले, प्रेट्र : मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा कि उनके देश में 10 मई के बाद एक भी भारतीय सैन्य कर्मी मौजूद नहीं रहेगा, यहां तक कि सादे कपड़ों में भी नहीं। मीडिया में आई एक खबर में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।

मुइज्जू का यह बयान तब आया है जब एक सप्ताह से भी कम समय पहले भारत की असैन्य टीम मालदीव में एक उन्नत हल्के हेलीकाप्टर का संचालन करने वाले सैन्यकर्मियों की जगह लेने वहां पहुंची थी। मुइज्जू ने अपने देश से भारतीय सैन्यकर्मियों के पहले समूह की वापसी के लिए 10 मार्च की समयसीमा तय की थी।

समाचार पोर्टल एडीशन डाट एमवी के अनुसार, मुइज्जू ने बा द्वीप के इधाफुशी आवासीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकालने में उनकी सरकार की सफलता के कारण झूठी अफवाहें फैला रहे लोग स्थिति को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं। पोर्टल ने चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज्जू के हवाले से कहा- 'यह कहना कि ये लोग (भारतीय सेना) देश छोड़कर जा नहीं रहे हैं, ये सादे कपड़े पहनकर अपनी वर्दी बदलने के बाद वापस लौट रहे हैं। हमें ऐसे विचार नहीं लाने चाहिए जो हमारे दिलों में संदेह पैदा करें और झूठ फैलाएं।' उन्होंने कहा- '10 मई के बाद देश में कोई भारतीय सैनिक मौजूद नहीं रहेगा। न ही वर्दी में और न ही सादे कपड़ों में। भारतीय सेना किसी भी तरह के कपड़ों में इस देश में नहीं रहेगी। मैं विश्वास के साथ यह कहता हूं।' उन्होंने यह बयान ऐसे दिन दिया है जब उनके देश ने निशुल्क सैन्य सहायता हासिल करने के लिए चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इससे पहले पिछले महीने दो फरवरी को दोनों पक्षों के बीच दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत इस द्वीपीय देश में तीन विमानन प्लेटफार्मों में अपने सैन्यकर्मियों को बदलेगा और इस प्रक्रिया का पहला चरण 10 मार्च तक पूरा किया जाएगा।

इस बीच, स्थानीय मीडिया में आई खबरों के अनुसार मालदीव ने मेडिकल बचाव मिशन के लिए विमानों का संचालन करने के लिए पिछले सप्ताह श्रीलंका के साथ सफलतापूर्वक समझौता किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि वह सभी भारतीय सैनिकों को हटाने पर तुला है।

राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकेंगे ट्रंप, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया प्रतिबंध

कोलोराडो की अदालत ने कैपिटल हिंसा में पूर्व राष्ट्रपति की भूमिका के आधार पर की थी कार्रवाई

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल फोटो

वाशिंगटन, एपी: अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन दावेदारी की दौड़ में आगे चल रहे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 16 राज्यों में होने वाले प्राइमरी चुनाव से पहले राहत मिली है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कैपिटल हिल मामले में ट्रंप पर चुनाव लड़ने से रोक हटाते हुए इसे राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया है। कहा, यह अधिकार कांग्रेस के पास है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमेरिकी जनता की जीत बताया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोलोराडो, इलिनोइस, मेन समेत उन राज्यों में जहां ट्रंप को प्राइमरी चुनाव के दौरान बैलट पेपर से हटाने की कवायद चल रही थी, उस पर विराम लग गया है। हालांकि, ट्रंप पर चार आपराधिक मामले चल रहे हैं। जिनपर निर्णय आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी राज्य संविधान के 14वें संशोधन का हवाला देते हुए, जिसमें सशस्त्र विद्रोह करने पर चुनाव लड़ने से वंचित करने का प्रविधान है, को लागू नहीं कर सकते। कोलोराडो की शीर्ष अदालत ने छह, जनवरी 2021 को कैपिटल हिल हिंसा को उकसाने के आरोप में ट्रंप के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। इसमें 14वें संविधान संशोधन के खंड-3 का हवाला दिया गया था। इधर, ट्रंप ने रिपब्लिकन उम्मीदवारी में निक्की हेली के विरुद्ध उत्तरी डकोटा काकस में सोमवार को जीत दर्ज की है।

दक्षिण चीन सागर में चीन-फिलीपींस के जहाज टकराए

विवादित दक्षिण चीन सागर में मंगलवार को फिलीपींस (बाएं) एवं चीन के तटरक्षक जहाजों के मध्य टक्कर हो गई। एपी

मनीला, एपी : विवादित दक्षिण चीन सागर में मंगलवार को चीन और फिलीपींस के तटरक्षक जहाजों के बीच हुई टक्कर में फिलीपींस के चार क्रू सदस्य घायल हो गए। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागीरी आसियान देशों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। एक दिन पहले आस्ट्रेलिया में आसियान शिखर सम्मेलन में फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने बीजिंग के आक्रामक रुख के जवाब में समूह के सदस्य देशों से एकजुटता का आह्वान किया था। फिलीपींस के अधिकारियों ने कहा, चीन तटरक्षक जहाजों व उनके पोत ने विवादित सेकेंड थामस शोल के पास फिलीपींस तटरक्षक व आपूर्ति जहाजों का रास्ता रोका। चीन तटरक्षक जहाजों के खतरनाक कदम से दोनों देशों के जहाज टकरा गए। फिलीपींस नौसैनिकों द्वारा संचालित आपूर्ति पोत पर दो चीनी तटरक्षक जहाजों से पानी की बौछार किए गए। इधर, चीन तटरक्षक प्रवक्ता ने कहा, फिलीपींस के जहाज जानबूझ कर चीनी जहाजों से टकराए इससे मामूली क्षति हुई।

यूक्रेन ने एक और रूसी युद्धपोत को डुबोने का किया दावा

कीव, एपी: यूक्रेन ने रूस के एक और युद्धपोत को समुद्र में डुबोने का दावा किया है। उसने मंगलवार को कहा कि उच्च तकनीक वाले समुद्री ड्रोन का उपयोग करके काला सागर में क्रीमिया के पास रूसी युद्धपोत को डुबो दिया गया। यूक्रेन की ओर से यह दावा ऐसे समय किया गया है, जब उसकी सेना अग्रिम मोर्चे पर लक्ष्यों को लगातार निशाना बना रही है। हालांकि रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन के इस दावे की पुष्टि नहीं की है। यूक्रेन ने फरवरी में भी दो रूसी युद्धपोतों को डुबोने का दावा किया था।

यूक्रेनी सैन्य खुफिया एजेंसी ने कहा कि एक विशेष अभियान इकाई ने बड़े गश्ती जहाज सर्गेई कोतोव को चालक रहित मगुरा वी5 से रात में नष्ट कर दिया। मगुरा वी5 यूक्रेन में डिजाइन और निर्मित था और विस्फोटक से लैस था। यूक्रेन ने कहा गश्ती जहाज को केर्च स्ट्रेट के पास निशाना बनाया गया और वह कथित तौर पर क्रूज मिसाइल से लैस और लगभग 60 चालक दल को ले जा सकता था।

यूक्रेन के दावे को तत्काल स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका और फरवरी 2022 में रूस द्वारा अपने पड़ोसी यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किए जाने के बाद शुरू हुई लड़ाई की दुष्प्रचार एक विशेषता रही है। कीव की सेना 1,500 किलोमीटर मोर्चे पर कुछ बिंदुओं पर रूसी सेना को दूर रखने के लिए संघर्ष कर रही है। साथ ही युद्ध के मैदान से परे लक्ष्यों को भी निशाना बना रही है। कीव के अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन पर लगभग 20 प्रतिशत रूसी मिसाइल हमले काला सागर से किए जाते हैं और वहां रूसी जहाजों का निशाना बनना मास्को के लिए शर्मनाक है। यूक्रेन ने पिछले महीने भी दो रूसी युद्धपोत को डुबोने का दावा किया था। हालांकि रूसी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की थी।

मास्को ने नहीं की पुष्टि, कीव ने पिछले महीने भी दो रूसी युद्धपोत डुबोने का किया था दावा

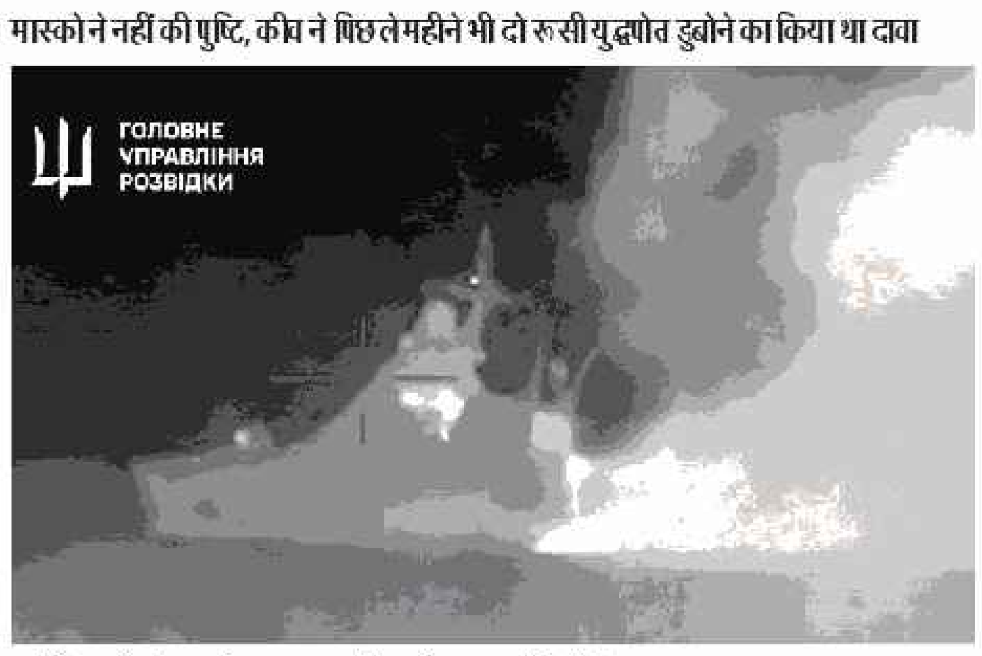

यूक्रेनी समुद्री ड्रोन का निशाना बना रूसी गश्ती जहाज सर्गेई कोतोव। रायटर

रूसी कमांडरों कोबिलाश-सोकोलोव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

हेग, रायटर: अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट (आइसीसी) ने यूक्रेन में युद्ध अपराध के आरोप में शीर्ष रूसी कमांडरों सर्गेई कोबिलाश और विक्टर सोकोलोव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हेग स्थित आइसीसी ने कहा, यह मानने के लिए पर्याप्त आधार है कि दोनों संदिग्ध जिम्मेदार है कि उनकी कमान में बलों ने 10 अक्टूबर 2022 से नौ मार्च 2023 तक यूक्रेनी विद्युत बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए मिसाइल हमले किए। आइसीसी ने मंगलवार को कहा, यूक्रेन के विद्युत ग्रिड पर हमले के कारण नागरिक क्षति हुई और यह किसी भी संभावित सैन्य लाभ के लिए बहुत अधिक थी। यूक्रेन के अभियोजक पहले ही सर्दियों में यूक्रेनी ऊर्जा और उपयोगिता बुनियादी ढांचों पर हवाई हमलों के बाद से संभावित युद्ध अपराधों की जांच कर रहे थे। हालांकि रूस यूक्रेन में नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने की बात से इन्कार करता है। यूक्रेन युद्ध से जुड़े रूसी अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए आइसीसी द्वारा जारी यह दूसरा वारंट सेट है।

पश्चिमी देशों के राजदूत आंतरिक मामलों में कर रहे हस्तक्षेप : रूस

मास्को, रायटर: रूस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मास्को में पश्चिमी देशों के राजदूत विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। राजदूतों के व्यवहार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मास्को की यह प्रतिक्रिया अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन (ईयू) के राजदूतों द्वारा देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात से इन्कार के बाद आई। बता दें कि गत एक मार्च को ईयू के राजदूत नवलनी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। आर्कटिक जेल कालोनी में नवलनी की मौत की घोषणा 16 फरवरी को की गई थी। पश्चिमी देश नवलनी की मौत के लिए पुतिन को जिम्मेदार मानते हैं। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखरोवा ने राजदूतों के इन्कार की टिप्पणी पर रूस की सरकारी टेलीविजन पर कहा कि यह सवाल सभी के बीच उठता है। वे क्या कर रहे हैं और क्यों।

बेलआउट पैकेज के लिए आइएमएफ से वार्ता का दिया आदेश

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बोले, देश की अर्थव्यवस्था सुधारना सर्वोच्च प्राथमिकता

शहबाज शरीफ। फाइल

इस्लामाबाद, प्रेट्र: पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नकदी संकट से जूझ रहे देश के लिए विस्तारित फंड सुविधा प्राप्त करने को आइएमएफ के साथ अधिकारियों को तत्काल बातचीत का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, जिसे जनादेश मिला है।

जनवरी में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) से मौजूदा तीन अरब डालर की स्टैंड-बाय व्यवस्था (एसबीए) के तहत 70 करोड़ डालर से अधिक की दूसरी किस्त प्राप्त हुई। यह पिछले साल जून में सहमति के आधार पर दी गई थी, जब पाकिस्तान धीरे-धीरे डिफाल्ट की ओर बढ़ रहा था।

पाकिस्तान ने पिछले 6.5 अरब डालर के आइएमएफए बेलआउट पैकेज को पूरा नहीं किया है। इसलिए नई सरकार का पहला काम 1.2 अरब डालर की अंतिम ऋण किस्त प्राप्त करने के लिए वाशिंगटन स्थित वैश्विक ऋणदाता के साथ बैठक करना होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष के आधिकारिक हैंडल से सोमवार को एक्स पर उर्दू में पोस्ट किया गया कि प्रधानमंत्री शरीफ के शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद ही देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक करने को लेकर बैठक आयोजित की गई।

जनादेश चुराने के विरुद्ध पीटीआइ का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन 10 को: जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) ने आठ फरवरी को हुए आम चुनाव में धांधली के विरुद्ध 10 मार्च को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव में जनादेश की चोरी हुई है।

दूसरी ओर, पीटीआइ ने आरक्षित सीटों के आवंटन के विरुद्ध चुनाव आयोग के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। आयोग ने सोमवार को फैसला सुनाया था कि पीटीआइ समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआइसी) आम चुनाव के बाद संसद में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित आरक्षित सीटों के लिए पात्र नहीं है।

मरयम नवाज का पंजाब का सीएम बनना मील का पत्थर : अमेरिका

अमेरिका ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री के रूप में मरयम नवाज के चयन को मील का पत्थर बताया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने सोमवार को प्रेसवार्ता में कहा कि इस फैसले से पाकिस्तान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पुत्री मरयम पाकिस्तान के किसी भी प्रांत में बनने वाली पहली महिला सीएम हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का पीएम बनने पर शहबाज शरीफ को दी बधाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर शहबाज शरीफ को बधाई दी। उन्होंने एक्स पोस्ट कर उन्हें शुभकामना भेजीं। शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ ली और नकदी संकट से जूझ देश की बागडोर दूसरी बार संभाली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता शहबाज शरीफ को रविवार को नेशनल असेंबली में 201 वोट हासिल करने के बाद पाकिस्तान के पीएम के रूप में चुना गया। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) समर्थित प्रतिद्वंद्वी उमर अयूब खान को हराया। शपथ ग्रहण समारोह तहरीक-ए-इंसाफ द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन के बीच हुआ। पीटीआइ ने आठ जनवरी को हुए आम चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने ऐवान-ए-सद्र में शहबाज शरीफ को शपथ दिलाई।

नेपाल में प्रचंड नहीं बना पाए सहमति, कैबिनेट विस्तार टला

नए गठबंधन के सहयोगियों के बीच वार्ता रही बेनतीजा

सरकार की स्थिरता को लेकर अनुमानों का बाजार गर्म

काठमांडू, प्रेट्र : नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड मंगलवार को सहयोगियों के साथ सत्ता साझेदारी समझौते पर सहमति बनाने में विफल रहे। नेपाली कांग्रेस के साथ नाटकीय तरीके से गठबंधन समाप्त करने वाले प्रचंड की नए सहयोगियों के साथ सरकार बनाने को लेकर बातचीत बेनतीजा रही। इसके चलते कैबिनेट का विस्तार टालना पड़ा। इससे प्रचंड सरकार की स्थिरता को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

प्रधानमंत्री प्रचंड ने कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के साथ नया गठबंधन बनाया है। संसद में संख्या बल के लिहाज से पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अगुआई वाली यह पार्टी दूसरे नंबर की है। इसके बाद सीपीएन-यूएमएल से पदम गिरी, कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल (माओवादी केंद्र) से हित बहादुर तमांग और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) से डोल प्रसाद अर्याल ने सोमवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। नया गठबंधन बनाने के बाद चारों दल, सीपीएन (माओवादी केंद्र), सीपीएन-यूएमएल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और जनमत पार्टी आठ सूत्री समझौते पर पहुंचे। समझौते के अनुसार, चारों दल नेशनल असेंबली अध्यक्ष चुनाव में माओवादी सेंटर के उम्मीदवार का समर्थन करने पर सहमत हुए हैं और उपाध्यक्ष के लिए यूएमएल उम्मीदवार का समर्थन करने का निर्णय लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों के बीच सत्ता साझेदारी पर सहमति नहीं बन पाने के कारण प्रधानमंत्री 'प्रचंड' नई गठबंधन सरकार के गठन के 24 घंटे बाद भी कैबिनेट सदस्यों को मंत्री पद बांटने में विफल रहे। सीपीएन-यूएमएल के समर्थन से आनन-फानन में गठित हुए मंत्रिमंडल में प्रचंड ने गृह, रक्षा, विदेश और वित्त समेत 25 विभाग अपने पास रखे हैं। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को सीपीएन-यूएमएल के चेयरमैन ओली, जनता समाजवादी पार्टी प्रमुख उपेंद्र यादव और आरएसपी अध्यक्ष रवि लामिछाने के साथ वार्ता की। हालांकि वार्ता बेनतीजा समाप्त हो गई। सीपीएन-यूएमएल के केंद्रीय सदस्य बिष्णु रिजाल ने बताया कि गठबंधन के सदस्यों के बीच मंगलवार शाम तक चर्चा चलने के कारण बुधवार तक कैबिनेट विस्तार पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि चारों पार्टियों के पास संसद में 142 सीटें है और यह बहुमत दिखाने के लिए पर्याप्त हैं।

चीन ने नेपाल की नई सरकार का स्वागत किया : चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि बीजिंग सरकार नेपाल की नई सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। इससे नेपाल में हुए नए राजनीतिक बदलाव में बीजिंग का हाथ होने के अनुमान को बल मिला है।

चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बीजिंग में कहा कि चीन की नेपाल की नई सरकार के साथ काम करने की इच्छा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अधूरी परियोजनाओं, भ्रष्टाचार एक महत्वाकांक्षी हवाई अड्डे की जांच को लेकर चीन विवादों में घिरा है।

****

पहले ड्रेसिंग रूम में माहौल काफी गंभीर होता था। ऐसे माहौल में खिलाड़ी का मनोबल कम हो जाता है और वह कई बार मैच में उचित प्रदर्शन नहीं कर पाता था। लेकिन अब हम लोगों ने इसमें बदलाव किया है ताकि खिलाड़ियों का मानसिक दबाव कम हो सके।
राहुल द्रविड़, कोच, भारतीय टीम

टेस्ट का शतक लगाने को तैयार बेयरस्टो–अश्विन

धर्मशाला में कल से खेला जाएगा **पांचवां टेस्ट** अश्विन बोले–2012 में इंग्लैंड के विरुद्ध सीरीज थी निर्णायक मोड़

नीरज व्यास • धर्मशाला

भारत और इंग्लैंड की टीमें गुरुवार से जब धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में सीरीज का पांचवां और अंतिम टेस्ट मैच खेलने उतरेंगी तो दो खिलाड़ियों के लिए ये बहुत बड़ा पल होगा। भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जानी बेयरस्टो का यह 100वां टेस्ट मैच होगा। यह चौथा अवसर होगा जब दो खिलाड़ी एक साथ अपना 100वां टेस्ट मैच खेलते दिखेंगे। यह केवल दूसरा मौका होगा जब प्रतिद्वंद्वी टीमों के दो खिलाड़ी एक ही मैच में अपना 100वां टेस्ट खेलेंगे। भारत पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त प्राप्त कर चुका है।

भारतीय टीम के दिग्गज आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि भारत हर हाल में यह मैच जीतकर सीरीज को 4-1 से अपने नाम करने उतरेगी। हालांकि धर्मशाला के सर्द मौसम के अनुसार खुद को ढालने में बहुत कम समय है लेकिन इसके बावजूद टीम बढ़िया प्रदर्शन करेगी और जीतेगी। अश्विन ने अपने 100वें टेस्ट के बारे में कहा कि यह बड़ा अवसर है, लेकिन इससे मेरी तैयारी में कोई बदलाव नहीं आया है। हमें हर हाल में टेस्ट मैच जीतना है। अश्विन ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ 2012 की सीरीज मेरे लिए निर्णायक मोड़ थी। इसने मुझे बताया कि मुझे कहां सुधार करना है। यह टेस्ट न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण पड़ाव है। वहीं, इंग्लिश टीम के बल्लेबाज जानी बेयरस्टो ने धर्मशाला मैदान की आउटफील्ड और पिच को बेहतर बताते हुए कहा कि यहां के परिस्थितियां हमारे लिए अच्छी हैं और निश्चित रूप से हम पांचवां टेस्ट मैच जीतेंगे। इंग्लैंड टीम के बल्लेबाज ने कहा कि यहां 100वां टेस्ट मैच खेलना यादगार व्यक्तिगत उपलब्धि होगी। इससे पहले, दोनों टीमों ने मंगलवार को नेट्स पर जमकर पसीना बहाया। सुबह इंग्लैंड की टीम कप्तान बेन स्टोक्स व कोच के साथ मैदान में अभ्यास के लिए पहुंची। इंग्लैंड टीम का अभ्यास सत्र पूरा होने के बाद दोपहर को भारतीय टीम ने अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान सिराज व जडेजा ने नेट्स पर बल्लेबाजी का अभ्यास किया। इसके बाद यशस्वी और शुभमन ने अभ्यास किया।

भारतीय कप्तान रोहित बोले, खेलते समय स्कोर बोर्ड की ओर नहीं देखता

जागरण संवाददाता, बिलासपुर : भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि जब मैं बल्लेबाजी कर रहा होता हूं तो स्कोर बोर्ड की ओर बहुत कम ध्यान देता हूं। खासतौर पर ओवर के बाद अगर स्कोरबोर्ड की ओर नजर जाए भी तो टीम स्कोर ही देखता हूं। रोहित शर्मा ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में खेल महाकुंभ के शुभारंभ पर अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि एक वनडे सीरीज के शुरुआती दो मैच में उनका स्कोर शून्य था। तीसरे मैच के उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाया। ओवर खत्म होने के बाद जब स्कोरबोर्ड की ओर देखा तो उनका निजी स्कोर शून्य ही था। इस पर उन्होंने अंपायर से पूछा, थाई पैड लगा था क्या। उनका यह संवाद स्टंप माइक पर रिकार्ड हो गया और बाद में काफी प्रसारित हुआ। उन्होंने हंसते हुए कहा कि स्टंप माइक लोगों के लिए तो सही है, लेकिन...। उन्होंने कहा कि स्टंप माइक पर बहुत सारी बातें रिकार्ड होती हैं, लेकिन अच्छी बात है कि काफी बातें सामने नहीं आतीं। स्टंप बाइक में रिकार्ड हुई कई ऐसी बातें हैं, जो मजेदार और लोगों तक पहुंचाने लायक हैं। वे सात मार्च से धर्मशाला स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ होने वाले टेस्ट मैच के दौरान स्टंप माइक की कुछ बातों को सार्वजनिक करेंगे। रोहित ने कहा कि वह अधिकतर स्लिप में क्षेत्ररक्षण करते हैं। वहां से डीआरएस लेने के लिए उचित एंगल मिल जाता है। रोहित इस कार्यक्रम के बाद सीधे हेलीकाप्टर से धर्मशाला स्टेडियम से कुछ दूर बने हेलीपैड में उतरे।

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हेलीकाप्टर से धर्मशाला पहुंचे • एक्स

जानी बेयरस्टो • फाइल फोटो, एपी अश्विन • फाइल फोटो, एपी

कब-कब खिलाड़ी एक साथ खेले 100वां टेस्ट

अश्विन और बेयरस्टो से पहले 2013 में पर्थ में इंग्लैंड-आस्ट्रेलिया एशेज सीरीज में एलिस्टर कुक और माइकल क्लार्क ने टेस्ट मैचों का सैंकड़ा एक साथ पूरा किया था। वहीं, 2000 में ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथर्टन और एलेक स्टीवर्ट ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्राप्त किया था। वहीं, 2006 में दक्षिण अफ्रीका के जैक कैलिस, शान पोलाक और न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग ने सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड मैच में अपना-अपना 100 वां टेस्ट खेला था। इस एकमात्र अवसर है जब तीन खिलाड़ियों ने एक ही मैच में अपना 100वां टेस्ट खेला था।

रोमांचक मोड़ पर पहुंचा विदर्भ और मध्य प्रदेश का मुकाबला

रणजी ट्राफी

मप्र ने 321 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्टंप तक गंवाए 228 रन पर छह विकेट, जीत के लिए विदर्भ को करने होंगे चार शिकार

नागपुर, प्रेट्र : विदर्भ ने मध्य प्रदेश के विरुद्ध रणजी ट्राफी सेमीफाइनल के चौथे दिन मंगलवार को आखिरी पल में यश दुबे (94) का विकेट चटकाकर मैच पर अपना दबदबा बना लिया। दोनों टीमों के बीच यह मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां मैच के आखिरी दिन विदर्भ को जीत के लिए चार विकेट की जरूरत है, जबकि मध्य प्रदेश के पुछल्ले बल्लेबाजों के सामने 93 रन बनाने की चुनौती है। इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में मुंबई का सामना करेगी।

मैच का रुख उस समय विदर्भ की ओर मुड़ गया जब आखिरी से एक ओवर पहले आदित्य सरवते (दो विकेट) ने दुबे को अमन मोखाडे के हाथों कैच कराया। जीत के लिए 321 रन का पीछा करते हुए मध्य प्रदेश ने स्टंप के समय छह विकेट पर 228 रन बना लिए। क्रीज पर सारांश जैन (नाबाद 16) के साथ कुमार कार्तिकेय खाता खोले बिना मौजूद हैं। लक्ष्य का पीछा करते हुए दुबे ने दूसरे छोर से विकेटों के पतन के बीच शानदार पारी खेलकर टीम के संघर्ष को जारी रखा। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 212 गेंद की पारी में धैर्य और शानदार कौशल का परिचय दिया। उन्होंने इस दौरान 10 चौके लगाए और हर्ष गवली (67 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी के टूटने के बाद विदर्भ के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाकर मैच पर अपना दबदबा बनाया। पहली पारी में शतक जड़ने वाले हिमांशु मंत्री दूसरी पारी में सिर्फ आठ रन बना सके। रजत पाटीदार की गैरमौजूदगी में टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज प्रभावित नहीं कर सके। सागर सोलंकी (12), शुभम शर्मा (छह) और वेंकटेश अय्यर (19) की तिकड़ी के सस्ते में निपटने से टीम की राह कठिन हो गई। विदर्भ के लिए तीन विकेट चटकाने वाले अक्षय वाखरे सबसे सफल गेंदबाज रहे। इससे पहले, विदर्भ ने दिन की शुरुआत छह विकेट पर 343 रन से की। टीम ने 59 रन जोड़कर बाकी के चारों विकेट गंवा दिए। बीते दिन 97 रन पर नाबाद रहे यश राठौर ने अपना शतक पूरा किया। वह 200 गेंद पर 141 रन बनाकर आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। मध्य प्रदेश के लिए अनुभव अग्रवाल ने 92 रन पर पांच विकेट चटकाए। विदर्भ की पहली पारी 170 रन पर सिमटी थी।

एक नजर में

बीसीसीआइ से मान्यता चाहती है दृष्टिबाधित टीम

नई दिल्ली : भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम चाहती है कि बीसीसीआइ उन्हें अपनी छत्रछाया में लेकर सक्षम खिलाड़ियों की तरह मान्यता दे ताकि वे भी आगे बढ़ सकें। भारतीय दृष्टिबाधित टीम के कोच मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि दृष्टिबाधित क्रिकेट को अगले स्तर तक ले जाने के लिए बीसीसीआइ से मान्यता मिलना बहुत आवश्यक है। मान्यता के साथ दृष्टिबाधित क्रिकेटरों को बोर्ड से केंद्रीय अनुबंध भी मिलने चाहिए। पाकिस्तान के दृष्टिबाधित क्रिकेटरों को पीसीबी से अनुबंध मिले हैं और वे अच्छा खेल रहे हैं. पीसीबी ने उनका काफी सहयोग किया है। बीसीसीआइ को भी यह करना चाहिए। (प्रेट्र)

पाकिस्तान में प्रतियोगिता के दौरान जूडोका की मौत

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की एक युवा महिला जूडोका की प्रतिस्पर्धा के दौरान सिर में चोट लगने से मौत हो गई। बीस वर्ष की फिजा शेर अली को मरदान में यूथ टैलेंट हंट के दौरान 44 किलोवर्ग के मुकाबले में सिर में चोट लगी थी। पाकिस्तान जूडो महासंघ के अधिकारी ने कहा कि फिजा पेशावर में बीएस प्रथम वर्ष की छात्रा थी और ट्रायल के लिए मरदान आई थी और वह इस खेल में नई थी। (प्रेट्र)

मुक्केबाज लक्ष्य चाहर क्वालीफायर से बाहर

बस्तो अर्सिजियो : राष्ट्रीय चैंपियन लक्ष्य चाहर यहां चल रहे विश्व ओलिंपिक मुक्केबाजी क्वालीफायर के पहले दौर में बाहर होने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। पुरुषों की 80 किग्रा स्पर्धा में अपनी चुनौती पेश कर रहे चाहर ईरान के 2021 के एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता गेश्लाघी मेसम से हार गए। (प्रेट्र)

जेमिमा की तूफानी पारी से दिल्ली की बड़ी जीत

नई दिल्ली, जेएनएन : कप्तान मैग लैनिंग और जेमिमा रौड्रिग्ज के धुआंधार अर्धशतकों के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने मंगलवार को यहां महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) मुकाबले में गत चैंपियन मुंबई इंडियंस को 29 रनों से हराया। दिल्ली की पांच मैचों में यह चौथी जीत है। जेमिमा (69) और लैनिंग (53) की पारियों से दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 192 रन का स्कोर खड़ा किया था। इसके बाद जेस जोनासन (तीन विकेट) और मारिजाने कैप (दो विकेट) की अगुआई में दिल्ली के गेंदबाजों ने मुंबई को 20 ओवर में आठ विकेट पर 163 रन ही बनाने दिए। मुंबई के लिए अमनजोत कौर ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। अरुण जेटली स्टेडियम में शेफाली वर्मा (28) के साथ पारी शुरुआत करने उतरी लैनिंग ने दिल्ली को तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों ने 10 की औसत से रन जोड़ते हुए 4.3 ओवर में ही 48 रन जोड़ लिए। पावरप्ले खत्म होने तक दिल्ली की टीम ने 56 रन बना लिए थे। लैनिंग ने अपनी 38 गेंदों की पारी में छह चौके और दो छक्के लगाए। शेफाली और एलिस कैप्सी (19) का विकेट गिरने के बाद क्रीज पर उतरी जेमिमा रौड्रिग्ज ने इस सत्र में अपना पहला अर्धशतक लगाया। जेमिमा ने केवल 33 गेंदों में आठ चौके और तीन छक्के जड़ते हुए ताबड़तोड़ 69 रनों की पारी खेलकर टीम को 200 के स्कोर के करीब पहुंचाया। उन्होंने 19वें ओवर में नैट स्किवर ब्रंट की गेंद पर छक्के के साथ अर्धशतक पूरा किया। दिल्ली ने अंतिम पांच ओवर में 69 रन जोड़े और जेमिमा अविजित लौटीं।

मैच के दौरान शाट लगातीं जेमिमा • प्रेट्र

संयुक्त दूसरे स्थान पर पहुंचे आर प्रगनानंद

प्राग, प्रेट्र : भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रगनानंद ने शीर्ष पर चल रहे उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को हराकर यहां प्राग मास्टर्स शतरंज प्रतियोगिता में खिताब जीतने की उम्मीद बढ़ा दी। प्रगनानंद ने काले मोहरों से खेलते हुए अब्दुसत्तोरोव को पराजित किया। इस जीत से वह संयुक्त दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरे स्थान पर चल रहे ईरान के परहम माघसूदलू की चेक गणराज्य के गुयेन थाई दाई वान से हार का भी भारतीय खिलाड़ी को फायदा मिला। अब्दुसत्तोरोव हार के बावजूद चार अंकों के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। उनके बाद प्रगनानंद, रोमानिया के रिचर्ड रापोर्ट और माघसूदलू का नंबर आता है। इन तीनों के समान 3.5 अंक हैं। भारत के डी गुकेश माटुस्ज बार्टेल से हार गए।

खेल महाकुंभ में 75 हजार खिलाड़ी हिस्सा लेंगे

खेल मंत्री ने अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को बिलासपुर में किया खेलों का शुभारंभ, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ भी कार्यक्रम में रहे उपस्थित

जासं, बिलासपुर: केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में लुहणू क्रिकेट मैदान पर मंगलवार को सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का शुभारंभ किया। इस दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि खेलोगे तभी खिलोगे और इसलिए, सांसद खेल महाकुंभ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकने का अवसर दे रहा है। सांसद खेल महाकुंभ के पहले संस्करण में 40,000 और दूसरे संस्करण में 45,000 लोग इसमें शामिल हुए थे। इस बार हमने 75,000 खिलाड़ियों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है। इस बार खेल महाकुंभ में वालीबाल, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबाल और एथलेटिक्स को शामिल किया गया है। यह प्रधानमंत्री की ही प्रेरणा है कि आज पूरे देश में लगभग 300 सांसद अपने-अपने क्षेत्र में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन करवा रहे हैं।

अनुराग ने कहा कि रोहित शर्मा खेल महाकुंभ का उद्घाटन करने के लिए सुबह 5.30 बजे दिल्ली से यहां आए हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। अगर चाहते तो आने से इन्कार कर सकते थे क्योंकि गुरुवार से टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। लेकिन वह आए क्योंकि उन्हें पता था कि भारत का भविष्य यहीं होगा।

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ क्रिकेट खेलते रोहित शर्मा • साई

सात्विक-चिराग की विजयी शुरुआत

पेरिस, प्रेट्र : सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार भारतीय जोड़ी मंगलवार को यहां मलेशिया के ओंग यू सिन और टीओ ई यी के विरुद्ध कड़े मुकाबले में जीत के साथ फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गई।

विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज भारतीय जोड़ी ने 47 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में 21-13, 24-21 से जीत दर्ज की। मलेशिया की इस जोड़ी के विरुद्ध सात्विक और चिराग की यह आठ मैचों में पांचवीं जीत है। त्रीसा जाली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रेस्टो पर 16-21, 21-19, 21-17 से जीत के साथ ही दूसरे दौर में पहुंच गई। भारत की यह दोनों महिला जोड़ी पेरिस ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई करने की दौड़ में है।

नागल इंडियन वेल्स में पदार्पण पर जीते

टेनिस डायरी

इंडियन वेल्स, प्रेट्र : भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल ने इंडियन वेल्स मास्टर्स में पहली बार खेलते हुए अमेरिका के वाइल्ड कार्डधारी स्टेफान डोस्टानिक को सीधे सेटों में हराया।

नागल ने क्वालीफाइंग के पहले दौर में 6-2, 6-2 से जीत दर्ज की। आठवीं वरीयता प्राप्त नागल को जीतने में 68 मिनट लगे। उन्होंने आखिरी क्वालीफाइंग दौर में पहुंचकर 10 रैंकिंग अंक हासिल कर लिया। इस साल वह आस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंचने वाले एक दशक में पहले भारतीय पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी बने थे।

ओलिंपिक के कारण होपमैन कप रद्द: फ्रांस में होने वाला होपमैन कप पेरिस ओलिंपिक के कारण रद्द कर दिया गया है। इस मिक्स्ड टीम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नीस में जुलाई के अंत में होना था। ओलिंपिक में टेनिस की स्पर्धाएं 27 जुलाई से चार अगस्त तक चलेंगी। इंटरनेशनल टेनिस महासंघ ने कहा कि होपमैन कप 2025 में वापसी करेगा।

सुमित नागल • फाइल फोटो, प्रेट्र

हालेप के प्रतिबंध में कटौती

लुसाने, एपी : दो बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन सिमोना हालेप को टेनिस कोर्ट पर वापसी की मंजूरी मिल गई है। हालेप की अपील पर खेल पंचाट ने डोपिंग के कारण उन पर लगे प्रतिबंध में कटौती की है। खेल पंचाट न्यायालय ने कहा कि उसके न्यायाधीशों ने हालेप के प्रतिबंध को आंशिक रूप से बरकरार रखा और उनके चार साल के प्रतिबंध को घटाकर केवल नौ महीने कर दिया। इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था जो पिछले साल जुलाई में समाप्त हो गया है। हालेप ने 2022 यूएस ओपन के बाद से अब तक कोई मैच नहीं खेला है। हालेप पर डोपिंग में विफल रहने के कारण अक्टूबर 2026 तक का प्रतिबंध लगा था। हालेप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया था और इस निर्णय के विरुद्ध अपील की थी।

पीसीआइ का निलंबन तत्काल प्रभाव से हटा

नई दिल्ली, प्रेट्र : खेल मंत्रालय ने लंबे समय से लंबित चुनावों के लिए प्रक्रिया शुरू करने के बाद मंगलवार को भारतीय पैरालिंपिक समिति (पीसीआइ) पर लगाए गए निलंबन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। इन चुनावों में पैरालिंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया का अध्यक्ष बनना तय है। इस पद के लिए सिर्फ झाझरिया ने ही नामांकन किया है।

खेल मंत्रालय ने दो फरवरी को राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार 'नई कार्यकारी समिति के चुनाव में जानबूझकर देरी' पर पीसीआइ की मान्यता समाप्त कर दी थी। पीसीआइ ने छह से 15 मार्च तक पैरा निशानेबाजी विश्व कप के कारण चुनावों को 28 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया था, जो इस साल 31 जनवरी से पहले होने चाहिए थे।

नील वेगनर को संन्यास के लिए मजबूर किया गया : रोस टेलर

क्रिकेट डायरी

वेलिंगटन, प्रेट्र : न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रोस टेलर ने कहा कि तेज गेंदबाज नील वेगनर को संन्यास लेने को मजबूर किया गया। 37 वर्षीय वेगनर ने आस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहले टेस्ट से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में संन्यास का ऐलान किया। वेगनर को अंतिम एकादश में नहीं चुना गया था। टेलर ने एक कार्यक्रम में कहा, अब समझ में आ रहा है कि वेगनर को संन्यास लेने पर मजबूर किया गया। वेगनर की प्रेस कांफ्रेंस को सुने तो पता चलता है कि वह संन्यास लेने वाला था, लेकिन अंतिम टेस्ट मैच के बाद। वह इस सीरीज के लिए उपलब्ध था। लेकिन पहले टेस्ट के लिए उसे टीम में नहीं चुना गया।

सेना के साथ ट्रेनिंग करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर

नई दिल्ली, जेएनएन : पाकिस्तानी क्रिकेटर अब पीएसएल समाप्त होने के बाद सेना के साथ 10 दिन का ट्रेनिंग लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने मंगलवार को कहा कि मैंने लाहौर में जब मैंने मैच देखा तो मुझे नहीं लगा कि किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने स्टैंड में छक्का मारा हो। वहीं विदेशी खिलाड़ी आराम से स्टैंड में छक्का मारते हैं। इसलिए मैंने खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए योजना तैयार की है। पीएसएल खत्म होने के एक सप्ताह बाद सभी खिलाड़ी 25 मार्च से आठ अप्रैल तक सेना के साथ ट्रेनिंग करेंगे।

राष्ट्रीय फलक

बिहार के गया में सेना का माइक्रो एयरक्राफ्ट तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त

जागरण संवाददाता, गया

बिहार में गया जिले के बोधगया में मंगलवार को सेना के ओटीए (आफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी) का माइक्रो एयरक्राफ्ट तकनीकी खराबी के कारण गेहूं के खेत में गिर पड़ा। एयरक्राफ्ट के दोनों पायलटों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दोनों ने नियमित प्रशिक्षण के क्रम में उड़ान भरी थी, लेकिन थोड़ी ही ऊंचाई पर अचानक तकनीकी खराबी आ गई और एयरक्राफ्ट गेहूं के खेत में गिर गया।

एयरक्राफ्ट गिरने पर तेज आवाज हुई, जिसे सुनकर ग्रामीण दौड़ कर घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना पर ओटीए के सैन्यकर्मी भी पहुंचे। सैन्यकर्मियों की टीम ने एयरक्राफ्ट को प्लास्टिक से ढंक दिया और ग्रामीणों के सहयोग से खेत से बाहर निकाला। ग्रामीण मनोज कुमार ने बताया कि दुर्घटना से गांव के किसान की लगभग दो कट्ठे की गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने बताया कि दो दशक में दो बार इस तरह की दुर्घटना हो चुकी है। दुर्घटना की सूचना पर प्रशिक्षण अकादमी के अधिकारी तकनीकी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीण ने बताया कि एयरक्राफ्ट गांव पर गिरा होता तो बड़ी घटना हो सकती थी।

यह क्रैश नहीं, इमरजेंसी लैंडिंग : गया ओटीए के पदाधिकारी फुरकान माहिर ने कहा कि बोधगया के बगदाहा में माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है, यह क्रैश नहीं हुआ है। उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। इस कारण पायलट को उसे अचानक खेत में उतारना पड़ा। इसमें दो पायलट सवार थे। दोनों सुरक्षित हैं। कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पायलट के नाम की जानकारी नहीं दी जाती।

बिहार के गया में मंगलवार को सेना का माइक्रो एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मौके पर जुटे लोग। प्रेट्र

इंडिगो की फ्लाइट में बीड़ी पीने पर यात्री गिरफ्तार

मुंबई, प्रेट्र : रियाद जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान के दौरान शौचालय के अंदर बीड़ी पीने के आरोप में 42 वर्षीय यात्री को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को दिल्ली-मुंबई-रियाद फ्लाइट के मुंबई हवाई अड्डे पर उतरने के बाद केबिन क्रू ने उसे पुलिस को सौंप दिया। अधिकारी ने बताया कि चौंकाने वाली बात यह है कि वह अपने साथ बीड़ी जलाने के लिए लाइटर ले जाने में सफल रहा। वह दिल्ली हवाई अड्डे से विमान में सवार हुआ था। पेशे से मजदूर आरोपित की पहचान मोहम्मद फकरुद्दीन मोहम्मद अम्मुरुद्दीन के रूप में हुई है। अधिकारी ने कहा कि यह घटना तब सामने आई, जब एक सुरक्षा अधिकारी ने अम्मुरुद्दीन के शौचालय से बाहर निकलने के बाद वहां धुआं देखा। आरोपित ने पुलिस को बताया है कि वह रियाद में मजदूर के रूप में काम करता है। पूछताछ में उसने कहा कि अपनी पैंट की जेब में बीड़ी और लाइटर छिपाकर ले गया था। वह दिल्ली हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच को आसानी से पार कर गया। उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

डल झील में खिलाड़ी दिखा रहे दमखम

जागरण संवाददाता, श्रीनगर

- श्रीनगर में आल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता जारी
- पहली बार महिला खिलाड़ियों की 10 टीमें ले रहीं भाग

देश की सुरक्षा के साथ खेल गतिविधियों के माध्यम से खुद को फिट रखने और युवाओं को इन खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से डल झील में आयोजित आल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने मंगलवार को दमखम दिखाया। प्रतियोगिता की खास बात यह है कि इसमें पहली बार महिला खिलाड़ी भी हिस्सा ले रही हैं। एसएसबी की महिला टीम ने कयाकिंग में दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए।

इस प्रतियोगिता में देशभर से लगभग 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आइटीबीपी, एसएसबी की 30 टीमें (20 पुरुषों तथा 10 महिला) हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन तीन मार्च को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया था। प्रतियोगिता के तीसरे दिन रोइंग, कयाकिंग व कैनोइंग की 500 मीटर रेस में सिंगल, डब्ल व फोर-फोर मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। यह प्रतियोगिता आठ मार्च को संपन्न होगी।

प्रतियोगिता की निदेशक बिलकीस मीर ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस चौथी बार यह प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि पहली बाद महिला खिलाड़ियों की 10 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं।

इस प्रतियोगिता में अभी तक इन महिला खिलाड़ियों ने 1000 मीटर की कयाकिंग, कैनोइंग तथा रोइंग रेस में बेहतरीन प्रदर्शन किया। मीर ने कहा कि जिस तरह महिला खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखा रही हैं, उससे हमें विश्वास है कि इस प्रतियोगिता में वह अपना दबदबा बरकरार रखेंगी। मीर ने कहा, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर के 60 कार्बन बोट तक उपलब्ध रखे हैं, ताकि खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों के आधार पर कर सकें।

श्रीनगर की डल झील में मंगलवार को आल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेते प्रतिभागी। खेल महोत्सव में देश भर से 30 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें 20 पुरुष व 10 महिला टीमें शामिल हैं। जागरण

****

दैनिक जागरण
सप्तरंग
सेहत भरे जीवन का
बुधवार, 6 मार्च, 2024

स्वस्थ मातृत्व के लिए सुझाव

मां बनना एक सुखद अनुभूति और दायित्व है। इस दौरान पर्याप्त सावधानी रखें तो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। आवश्यक है कि गर्भधारण से पूर्व ही सेहत को लेकर सजग बनें, गर्भधारण के दौरान सतर्क रहें।

डा. अनीता गुप्ता, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, फोर्टिस ला फेम, नई दिल्ली

मां बनने की तैयारी

- स्वस्थ मां बनने के लिए मानसिक तैयारी के साथ ही शरीर में किसी कमी या किसी तत्व की अधिकता का जान लें तो यह एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।
- गर्भधारण के बाद आयरन की कमी या थायरायड आदि का पता चलता है तो कई बार उससे निपटने में ही काफी समय लगता है। इससे भ्रूण का विकास बाधित होता है। इससे संबंधित जांच गर्भधारण से पूर्व हो जाएं।
- मां बनने में आयुगत विलंब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इससे स्वास्थ्य जटिलताएं बढ़ सकती हैं।

गर्भधारण के बाद

- आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन की कमी न होने दें।
- यदि डाक्टर ने कार्बोहाइड्रेट के लिए मना किया है तो खानपान में इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए।
- दिन में दो बार 20-20 मिनट टहलें। डाक्टर की सलाह से कसरत या योग कर सकती हैं।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (आठ मार्च)

इन दिनों महिलाएं हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही हैं। हालांकि संपूर्ण सेहत प्राप्त करने के लिए उनका संघर्ष कहीं अधिक होता है। ऐसे में आवश्यक है कि वे स्वस्थ खानपान, योग और व्यायाम का भी ध्यान रखें, ताकि स्वयं और स्वजन की बेहतर देखभाल के साथ खुशहाल जीवन का आनंद उठा सकें...

संपूर्ण सेहत की हो बात

इन बातों का रखें ध्यान

- बच्चियों की अच्छी शिक्षा के साथ सेहत की वार्षिक रिपोर्ट भी रखें। सेहत के कमजोर पक्ष को जानकर दिनचर्या में उचित बदलाव करते रहें।
- घर पर स्वास्थ्य जांच स्वयं करना सीखें ताकि अपने लिए सजगता और बढ़ सके।
- कोई बीमारी नहीं है तब भी साल में एक बार स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं। परिवार में बीमारी रही है तो यह जरूरी हो जाता है।
- बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीका अवश्य लगवाएं ताकि भविष्य में यह चुनौती न रहे।
- परिवार में योग और व्यायाम का वातावरण बनाएं ताकि उम्र के हर पड़ाव पर इसकी आदत बनी रहे।
- यदि आप घर पर रहकर भी अस्वास्थ्यकर खाती हैं तो बाहर के खाने में और उसमें ज्यादा अंतर नहीं (बस गुणवत्ता व मात्रा का फर्क हो सकता है)।
- ध्यान रखें कि आपका वजन लंबाई के अनुपात में रहे। वजन बढ़ना जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का बड़ा कारण है।

जीवनशैली

डा. सुशीला कटारिया, डायरेक्टर, इंटरनल मेडिसिन, मेदांता, गुरुग्राम

जब स्त्री स्वयं स्वस्थ रहेगी, तभी परिवार की सेहत को लेकर भी सजग प्रयास कर सकती है। न भूलें कि सेहत का पचास प्रतिशत अपने हाथ में है और आधा चिकित्सक-दवा के पास। अपने लिए समय नहीं है या परिवार पहले है, ऐसी सफाई स्त्री की सेहत की सबसे बड़ी चुनौती है। महिलाओं में मोटापा, हड्डियों की कमजोरी आम है। वहीं, पुरुषों में प्रभावी जीवनशैली से जुड़ी समस्याएं, जैसे-उच्च रक्तचाप, मधुमेह महिलाओं में भी तेजी से बढ़ रही हैं। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों, मांसपेशियों की समस्याएं बढ़ती ही हैं, लेकिन कम उम्र से ही सजगता से बचाव संभव है।

सेहत के लिए 60 मिनट

प्रतिदिन अपने लिए एक घंटा अवश्य निकालना चाहिए। यह ठान लें तो स्वस्थ रहना कठिन नहीं। अच्छा खान, समय पर खाना, योग और ध्यान आदि को दिनचर्या में शामिल कर लेना पर्याप्त है। शुरुआत में आदत बनाने में थोड़ी कठिनाई आती है पर सेहत प्राथमिकता बन जाए तो यह आसान हो सकता है।

एनीमिया की गंभीर समस्या : हमारे देश में महिलाएं हीमोग्लोबिन की कमी से जूझ रही हैं। प्री-मेनोपाज वाली महिलाओं में इसकी कमी पचास प्रतिशत तक होती है। दस प्रतिशत महिलाएं गंभीर रूप से एनीमिया (रक्त अल्पता) की शिकार होती हैं। आज भी महिलाएं हीमोग्लोबिन की कमी को सामान्य मानती हैं। सामान्य कामकाज भी ठीक से नहीं हो पा रहा, चिड़चिड़ापन रहता है, घबराहट, चक्कर आने या सांस फूलने जैसी समस्या है तो ये एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं जो अवसाद व गंभीर हृदय रोग का कारण भी बन सकता है।

आहार को लेकर भ्रम : कोई कमजोरी महसूस कर रहा है तो तुरंत कहते हैं कि दूध का सेवन करें। पर जान लें, अकेला दूध संपूर्ण आहार नहीं है। शरीर को दूध के साथ फल, सब्जियां, अनाज आदि सबकी आवश्यकता होती है। जन्म के एक साल के बाद से ही बच्चों को सभी प्रकार के आहार दें। इससे वे कुपोषण से बचेंगे। बच्चियों की सेहत अच्छी रहेगी, तभी वह स्वस्थ महिला बनेगी।

मानसिक सेहत की अनदेखी : कामकाजी हो या घरेलू, हर स्त्री को तनाव का प्रबंधन करना जानना चाहिए। विचारों की उलझनों से बचने के लिए योग, ध्यान या कुछ ऐसे शौक भी रखें, जिनसे रचनात्मकता को बढ़ावा मिले। विचारों की उलझन से बाहर निकल उन्हें सकारात्मक रूप देना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक सेहत का भी अच्छा रहना बहुत आवश्यक है।

बातचीत : सीमा झा

काला मोतिया की आशंका से कैसे बचें

विश्व ग्लूकोमा दिवस (12 मार्च)

डा. रोहित सक्सेना। प्रोफेसर, राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र, एम्स, नई दिल्ली

ग्लूकोमा या काला मोतियाबिंद को 'दृष्टि चोर' भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश समय तक स्पष्ट लक्षण नहीं होता और धीरे-धीरे दिखना बंद हो जाता है। काला मोतिया और सफेद मोतिया दोनों में ही दृष्टि धीरे-धीरे कम होती है, हालांकि सफेद मोतिया में आपरेशन के बाद दृष्टि वापस आ जाती है, लेकिन काला मोतिया से जो नजर जाती है, वह लौटती नहीं है। इसका बड़ा कारण है कि आंखों की भीतरी नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं यानी जो नसें आंखों को दिमाग से जोड़ती हैं, जिससे इंसान देख पाता है, वे पूरी तरह खराब हो जाती हैं। वैसे काला मोतिया अधिकतर 40-45 वर्ष की उम्र के बाद ही होना शुरू होता है।

क्यों होता है काला मोतिया : काला मोतिया का कारण है आंखों पर दबाव बढ़ना। जिस तरह रक्तचाप बढ़ने से शरीर को नुकसान होता है, उसी तरह दबाव बढ़ने से आंखों को भी नुकसान होता है। दबाव के कारण आंखों के पीछे की नसें सूखने लगती हैं और धीरे-धीरे उनके कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है।

बच्चों को भी होता है काला मोतिया : काला मोतिया बच्चों में भी देखा जाता है। आमतौर पर यह समस्या जन्मजात होती है। हालांकि कुछ ही मामलों में बच्चों में काला मोतिया होने की आशंका रहती है।

स्क्रीन टाइम बढ़ना कारण तो नहीं: आजकल लोग काफी समय स्मार्टफोन, लैपटाप और अन्य तरह के गैजेट्स की स्क्रीन पर बिता देते हैं। हालांकि, यह काला मोतिया होने का सीधे तौर पर कारण नहीं है। दिक्कत है तो सावधानी बरतनी चाहिए, समय-समय पर जांच करा लेनी चाहिए।

क्या होते हैं लक्षण

- आंखों पर दबाव बढ़ने पर आंखों के चारों तरफ और सिर में दर्द महसूस होता है।
- रोशनी के चारों तरफ इंद्रधनुष दिखने लगता है।
- अक्सर मरीज जब डाक्टर के पास पहुंचता है, तो पता चलता है कि नजर जा चुकी होती है।
- अचानक आंखों में बहुत तेज दर्द महसूस होना आंखों पर दबाव बढ़ने की निशानी है।

बचाव हेतु उपयोगी सुझाव

- 40 वर्ष की उम्र के बाद वर्ष में कम से कम एक बार आंखों की जांच अवश्य कराएं।
- हमारी आंखें नजदीक नहीं, दूर देखने के लिए बनी हैं। नजदीक में देखने से जोर पड़ता है।
- लगातार स्क्रीन पर समय बिताने से बचें।
- स्मार्टफोन या लैपटाप पर काम करते समय पर्याप्त रोशनी रखें, अंधेरे में काम न करें।
- हर आधे घंटे में पांच मिनट के लिए दूर देखें।
- आंखों को ब्लिंक करते रहें यानी पलकों को झपकाते रहें, अन्यथा आंखों में ड्राइनेस बढ़ती है।
- आंखों में ड्राइनेस बढ़ जाने पर जलन, खुजलाहट महसूस होती है।
- तकलीफ होने पर चिकित्सक से संपर्क करें।

सतर्कता आवश्यक

- भोजन में विटामिन व पोषक तत्व शामिल करें।
- अक्सर लोग सुबह उठते ही काफी पानी पी लेते हैं। इससे आंखों पर अचानक दबाव बढ़ जाता है।
- पानी जरूर पिएं, लेकिन रुक-रुक कर।
- पर्याप्त व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां करें।
- डायबिटीज, हाइपरटेंशन की जांच कराते रहें, क्योंकि आंखों पर इसका असर पड़ता है।

बातचीत : ब्रह्मानंद मिश्र

वर्ग पहेली-2565

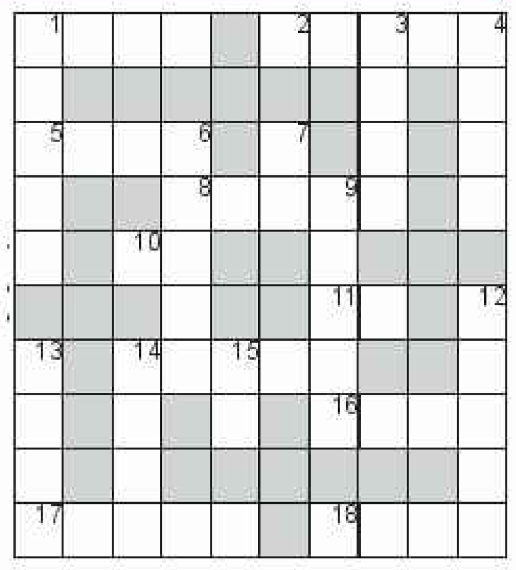

बाएं से दाएं

1. व्याकरण में जिस क्रिया का कर्म न हो (4) 2. स्वयं के बारे में कही गई कथा (2,3) 5. आग का दहकना (4) 8. साहित्य रचने वाला (5)। 10. सूर्य, दिनकर (2) 11. डर (2)। 14 पक्षपाती, सहायक (5)। 16. निर्बुद्धि, बेवकूफ, बुद्धिहीन (4)। 17. इज्जत बचाना (2,3) 18. रात में जगने वाले जीव-जंतु (4)

ऊपर से नीचे

1. समय से पहले मौत हो जाना (5)। 3. गोलाकार (4)। 4. सुंदर तरीके से काटना या कतरना (4)। 6. नाक काटना (5)। 7. यथार्थ, सही बात, सच (2)। 9. किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करके किसी को उसके विरुद्ध करना (2,3)। 12. बुद्धिमान, समझ रखने वाला (5)। 13. किसी चीज का दबाव से घट जाना (4)। 14. उपाय, तरीका, ढंग (4)। 15. कर्तव्य, कर्म (2)।

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

जागरण सुडोकू-2565

	7	9		6				8
2			4				9	
		5			9		3	
3			1			8		9
		2		5	7		6	
	6			4			5	
5	9				8		7	2
		1				6		
	2			3		9		5

कल का हल

6	1	4	2	8	3	9	7	5
8	2	9	6	5	7	3	4	1
5	7	3	1	9	4	8	2	6
1	3	2	9	6	5	7	8	4
7	4	6	3	2	8	1	5	9
9	8	5	4	7	1	2	6	3
2	5	1	8	3	6	4	9	7
3	9	7	5	4	2	6	1	8
4	6	8	7	1	9	5	3	2

आज का भविष्यफल- 06 मार्च, 2024 बुधवार

के.ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी। राहुकाल : दोपहर 12 बजे से 01 : 30 बजे तक। दिशाशूल : उत्तर। पर्व एवं त्योहार : विजया एकादशी स्मार्त। एकादशी तिथि क्षय। आज की भद्रा : प्रात : 06 बजकर के 12 मिनट तक।

कल 07 मार्च, 2024 का पंचांग
दिशाशूल : दक्षिण
पर्व एवं त्योहार : विजया एकादशी वैष्णव।
विशेष : बुध मीन राशि में एवं शुक्र कुंभ राशि में, एकादशी तिथि क्षय।
विक्रम संवत 2080 शिशिर ऋतु फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तत्पश्चात त्रयोदशी उत्तराआषाढ़ा नक्षत्र वरियान योग तत्पश्चात परिघ योग मकर में चंद्रमा।

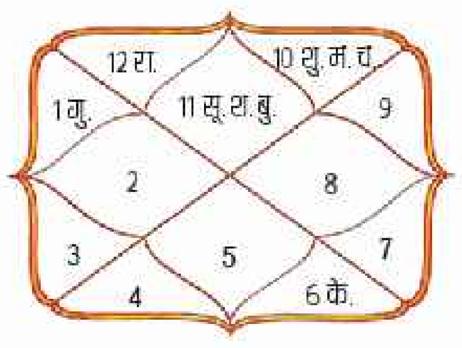

- मेष : शुक्र बुध का परिवर्तन उत्तम है। रचनात्मक कार्यों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
- वृष : उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तों में निकटता आएगी।
- मिथुन : शिक्षा में किया जा रहा कार्य सम्मानजनक प्रतिष्ठा देगा।
- कर्क : आर्थिक सफलता मिलेगी। शिक्षा में चल रहा प्रयास सार्थक होगा।
- सिंह : मौसम के रोग से बचें। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं।
- कन्या : पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। शासन का सहयोग मिलेगा।
- तुला : शिक्षा में श्रम सार्थक होगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी।
- वृश्चिक : पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक प्रयास फलीभूत होगा।
- धनु : जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
- मकर : उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तों में निकटता आएगी।
- कुंभ : आजीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासनसत्ता का सहयोग रहेगा।
- मीन : रोग के प्रति सचेत रहें। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय फलक

सात साल बाद जवानों ने बलिदानी की बहन को ससुराल विदा किया

- 2017 में कश्मीर में दो आतंकियों को ढेर कर वीरगति को प्राप्त हुए थे ज्योति प्रकाश
- बलिदानी की दारोगा बहन की शादी में कमांडो की टोली ने निभाया भाई का फर्ज

जवानों की हथेली पर पैर रखकर विदा होती दुल्हन। जागरण

चुनरी की छांव में दुल्हन सुनीता को ले जाते एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो की टोली। जागरण

प्रमोद टैगोर, संझौली (रोहतास)

सर्वोच्च सैन्य सम्मान अशोक चक्र प्राप्त बलिदानी ज्योति प्रकाश निराला की बहन सुनीता की शादी में जब एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो की टोली बिक्रमगंज (रोहतास) पहुंची तो समारोह में उपस्थित लोग भावुक हो गए। सात वर्ष बाद भी जवानों ने अपने वीर साथी के बलिदान एवं परिवार के इकलौते पुत्र के नाते पीछे छूट गई उनकी जिम्मेदारियों को याद रखा।

चार मार्च को जवान जब जयमाल एवं सात फेरों की रस्म में दुल्हन के सिर के उपर चुनरी की छोर पकड़ कर चले तो लोगों ने कहा, भाई की कमी पूरी हो गई। विदाई भी अनोखी रही। जवानों ने जमीन पर फूल बिछाए और अपनी हथेलियों पर बहन के पैर रख उसे ससुराल विदा किया।

दुल्हन बनी सुनीता बलिदानी ज्योति प्रकाश की तीसरी बहन हैं, वह बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर (दारोगा) हैं। सुनीता की शादी बक्सर जिले के धनसोई निवासी दारोगा राहुल कुमार से संपन्न हुई। दोनों अभी किशनगंज में पदस्थापित हैं। इनके अलावा बलिदानी की दो बहनें व एक बेटी भी है।

16 एयरफोर्स गरुड़ कमांडो की टोली का नेतृत्व कर रहे जेडब्ल्यूओ कमांडो आरसी प्रसाद ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि ज्योति प्रकाश की तीसरी बहन की शादी है तो उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात अन्य जवानों को भी सूचित किया। सोमवार को वे सभी बहन की शादी में पहुंचे। टीम लीडर ने बताया कि एयरफोर्स एक परिवार है। चार बहनों में ज्योति अकेले भाई थे, जिन्होंने देश की खातिर प्राण न्योछावर कर दिए। उनकी बहन एयरफोर्स के सभी जवानों की बहन हैं। पहली बहन की शादी 2010 में हो चुकी थी। ज्योति के बलिदान होने के बाद दूसरी बहन की शादी में भी हम सभी आए थे, तब भी बहन को हथेलियों पर विदा किया था। शादी में आए जवानों में शौर्य चक्र प्राप्त देवेंद्र मेहता के अलावा देश के गरुड़ कमांडो आरसी प्रसाद (जोरहाट, असम), प्रभाकर रंजन (जोधपुर), नागेंद्र सक्सेना (जम्मू), पिंटू कुमार (झाबुआ), मणिशंकर यादव (पठानकोट), सतीश (ग्वालियर), अनीस दूबे (बेंगलुरू), शुभम (हासीमारा), बिपिन कुमार रवि (जम्मू), तुलसी यादव (हासीमारा) शामिल थे।

बलिदानी भाई की पूरी कर दी कमी : सुनीता ने कहा कि शादी के वक्त एक भाई की मौजूदगी एक बहन के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, यह बिना भाई वाली बहन ही समझ सकती है, परंतु मेरी इस कमी को गरुड़ कमांडो भाइयों ने पूरा कर दिया। हर पल मेरे साथ भाई बनकर खड़े रहे। ये मुझे आजीवन याद रहेगा।

कौन थे ज्योति प्रकाश

रोहतास जिले के बाडिलाडीह के तेजनारायण सिंह व मालती देवी के पुत्र ज्योति प्रकाश 2005 में वायु सेना में भर्ती हुए थे। 18 नवंबर 2017 को सर्च आपरेशन के दौरान कश्मीर के चंद्रगढ़ में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के बावजूद दो आतंकवादियों को ढेर कर सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस मुठभेड़ में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोइबा के कुल छह आतंकी मारे गए थे। 26 जनवरी 2018 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया था।

इस साल तापमान औसत से अधिक बढ़ेगा : डब्ल्यूएमओ

- वर्ष 2023 अब तक के सबसे गर्म वर्ष के रूप में रिकार्ड किया गया
- भारत में इस साल मानसून की बारिश 2023 की तुलना में अच्छी होगी

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस साल मार्च और मई के बीच तापमान औसत से अधिक रहेगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने मंगलवार को कहा कि वर्ष 2023-24 की अल नीनो अब तक के पांच सर्वाधिक प्रचंड अल नीनो में से एक होने का रिकार्ड कायम किया है। अल नीनो के कमजोर रुख के बावजूद आने वाले महीनों में वैश्विक जलवायु को प्रभावित करना जारी रखेगी।

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा कि मौजूदा अल नीनो की दशा दुनियाभर में रिकार्ड तापमान और मौसम से जुड़ी घटनाओं को बढ़ावा देगी। यूरोपीय संघ की कापरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार, वैश्विक औसत तापमान जनवरी में पहली बार पूरे वर्ष के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया। हालांकि, पेरिस समझौते में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करना तापमान बढ़ोतरी को संदर्भित करता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा कि मार्च-मई के दौरान अल नीनो के बने रहने की लगभग 60 प्रतिशत संभावना है।

अप्रैल से जून के दौरान तटस्थ स्थितियों (न तो अल नीनो और न ही ला नीना) की 80 प्रतिशत संभावना है। इसमें कहा गया है कि साल के अंत में ला नीना विकसित होने की संभावना है लेकिन ये संभावनाएं फिलहाल अनिश्चित हैं।

भारत में घटनाक्रम पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों ने कहा है कि जून-अगस्त तक ला नीना की स्थिति बनने का मतलब यह हो सकता है कि इस साल मानसून की बारिश 2023 की तुलना में अच्छी होगी। अल नीनो से आशय मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का समय-समय पर गर्म होने से है और यह औसतन हर दो से सात साल में होता है तथा आमतौर पर नौ से 12 महीने तक रहता है।

इस बारे में डब्ल्यूएमओ के महासचिव सेलेस्टे साउलो ने कहा कि जून 2023 के बाद से हर महीने तापमान ने एक नया रिकार्ड बनाया है और वर्ष 2023 अब तक के सबसे गर्म वर्ष के रूप में रिकार्ड किया गया है।

विज्ञानियों का कहना है कि अल नीनो का वैश्विक जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव इसके उत्पन्न होने के हर दूसरे साल देखने को मिलता है और अबकी बार वर्ष 2024 में इसका प्रभाव दिखेगा। वर्तमान अल नीनो जून 2023 में विकसित हुई, नवंबर और जनवरी के बीच सर्वाधिक प्रचंड थी। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 0

उत्तराखंड में भारी हिमपात से चोपता में फंसे 30 पर्यटक

भारी बर्फबारी से बंद हुए कुंड-चोपता मार्ग से बर्फ हटाते एसडीआरएफ के जवान। साभार पुलिस

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग

उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के चलते चोपता में 30 पर्यटकों के फंसे होने की सूचना है। जिला आपदा प्रबंधन की टीम मार्ग से बर्फ साफ कर पर्यटकों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा कि मेरठ और गुरुग्राम के ये पर्यटक पिछले तीन दिन से चोपता में फंसे हुए हैं। हालांकि, खाने-ठहरने की उनके सामने कोई समस्या नहीं है।

पिछले दिनों लगातार बर्फबारी के बाद रुद्रप्रयाग के इस पर्यटन स्थल में चार से पांच फीट बर्फ जमी हुई है। इससे आवाजाही की राह अवरुद्ध हो गई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि 30 पर्यटकों के फंसे होने की सूचना के बाद मंगलवार को रेस्क्यू टीम चोपता के लिए रवाना हो गई। बताया कि लगातार बर्फबारी के चलते कुंड-चोपता-गोपेश्वर हाईवे चोपता से भुलकन तक बाधित है।

पीयू ला विभाग की पूर्व प्रोफेसर निष्ठा बनीं एएलयू जयपुर की कुलपति

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी स्थित ला विभाग की पूर्व प्रोफेसर और चेयरपर्सन प्रोफेसर निष्ठा जसवाल को डा. भीमराव अंबेडकर ला यूनिवर्सिटी (एएलयू) जयपुर राजस्थान की कुलपति नियुक्त किया गया है। यूनिवर्सिटी चांसलर व राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी की गई। प्रो. निष्ठा जसवाल इससे पहले शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश नेशनल ला यूनिवर्सिटी में भी पांच वर्ष तक कुलपति रह चुकी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से कुलपति पद हासिल करने वाली प्रो. निष्ठा जसवाल पहली महिला प्रोफेसर रही हैं। वह एएलयू की की भी पहली महिला कुलपति होंगी। दैनिक जागरण से बातचीत में प्रो. निष्ठा ने कहा कि उन्हें फिर से कुलपति के लिए चुना जाना सम्मान की बात है। प्रो. निष्ठा 36 वर्षों से कानूनी शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। प्रो. निष्ठा के पति प्रो. पीएस जसवाल सोनीपत स्थित एसआरएम ला यूनिवर्सिटी में कुलपति हैं। दंपती के नाम दो यूनिवर्सिटी में कुलपति बनने का खास रिकार्ड है।

प्रो. निष्ठा जसवाल की फाइल फोटो। जागरण

तीन फीट के गणेश बरैया बने चिकित्सक...

गुजरात निवासी गणेश बरैया तीन फीट के हैं, लेकिन इनका धैर्य, लगन एवं उत्साह अपरिमित है। 23 वर्षीय गणेश बरैया चिकित्सक बन गए हैं। इन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली है। इनकी राह बाधाओं से भरी रही, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प एवं आत्मविश्वास से विभिन्न चुनौतियों को मात दिया। भावनगर मेडिकल कालेज में इंटर्नशिप भी आरंभ कर दिया है। प्रेट्र

10 रुपये किया गया पैसेंजर ट्रेनों का न्यूनतम किराया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना काल में पैसेंजर ट्रेनों में बढ़ाया गया किराया अब कम हो गया है। रेलवे बोर्ड की तरफ से इसे लेकर अभी आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है।

अधिकारियों के मौखिक आदेश पर किराये में कटौती की गई है। कोरोना से पहले लोकल ट्रेनों का न्यूनतम किराया 10 रुपये था। कोरोना काल में ट्रेनों का परिचालन कुछ माह के लिए बंद कर दिया गया था। चरणबद्ध तरीके से विशेष ट्रेन के तौर पर परिचालन शुरू किया गया था। उसी समय लोकल ट्रेनों का न्यूनतम किराया 10 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया था। कोरोना काल के बाद ट्रेनों का परिचालन सामान्य होने के बाद भी बढ़ोतरी वापस नहीं हुई। रेलवे यात्री पीछे काफी समय से इंटरनेट मीडिया व अन्य माध्यमों से बढ़ा हुआ किराया वापस लेने की मांग कर रहे थे।

हिमाचल की शानन प्रोजेक्ट की जमीन पर पंजाब का कब्जा

हंसराज सैनी, मंडी

736 बीघा से अधिक भूमि कब्जाई है पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन ने

1961 में हुए बंदोबस्त के मुताबिक जमीन का मालिक हिमाचल

मंडी जिले के 110 मेगावाट क्षमता के शानन पनविद्युत प्रोजेक्ट की जमीन पर पंजाब का अवैध कब्जा है। 736 बीघा से अधिक भूमि पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन ने कब्जाई है। 1961 में हुए बंदोबस्त के मुताबिक हिमाचल सरकार जमीन की मालिक है। राजस्व विभाग ने रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेजी है।

जोगेंद्रनगर तहसील के अलग-अलग राजस्व मुहाल में पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन ने करीब 303 बीघा भूमि पर कब्जा किया है। टिक्कन उपतहसील के विभिन्न राजस्व मुहाल में करीब 433 बीघा जमीन शानन प्रोजेक्ट के मुख्य बांध और पाइपलाइन की भेंट चढ़ी थी।

राजस्व विभाग ने सरकार को भेजा जमीन का रिकार्ड : राजस्व विभाग ने जोगेंद्रनगर और द्रंग विधानसभा क्षेत्र में पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन द्वारा अवैध रूप से कब्जाई जमीन का मुहाल स्तर पर रिकार्ड तैयार कर सरकार को भेज दिया है।

अधर में लटका शानन प्रोजेक्ट। फाइल

****

किसी बौने ग्रह की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना डान

2015 में आज ही के दिन नासा का अंतरिक्ष यान डान किसी बौने ग्रह की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था। डान जिस बौने ग्रह की कक्षा में पहुंचा था वह सेरेस था। इससे पहले 2011 में डान वेस्टा क्षुद्रग्रह की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था।

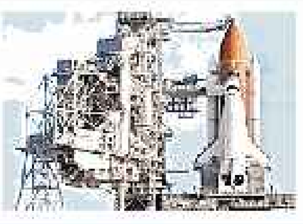

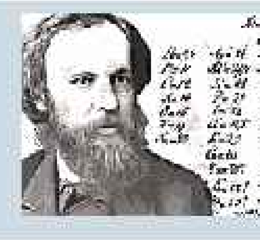

रासायनिक तत्वों की पहली आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई

1869 में आज ही के दिन रसायनज्ञ दिमित्री मेंडेलीव ने रूसी केमिकल सोसाइटी के समक्ष रासायनिक तत्वों की पहली आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी। इसमें तत्वों का उनके गुणों के अनुसार सारणीबद्ध रूप में वर्गीकरण किया गया था। इस आवर्त सारणी में 30 तत्व मौजूद थे।

भारतीय सेना के प्रतिष्ठित सैनिकों में गिने जाते हैं चुन्नी लाल

नायब सूबेदार चुन्नी लाल का जन्म 1968 में आज ही जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में हुआ था। 1984 में जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में शामिल हुए। 1999 में आपरेशन रक्षक के दौरान पुंछ सेक्टर में 12 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारने में भूमिका निभाई। 24 जून, 2007 को कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में एलओसी पार करके भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को खदेड़ने के दौरान बलिदान हो गए। 15 अगस्त, 2007 को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित हुए।

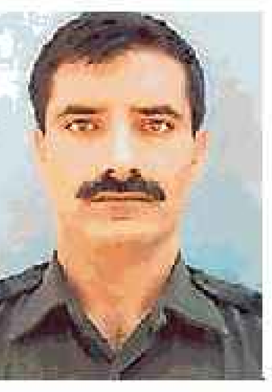

इधर-उधर की

डायनासोर की पोशाक पहनकर बनाया रिकार्ड

1,273 लोग डायनासोर की पोशाक में इकट्ठा हुए • इंटरनेट मीडिया

वाशिंगटन, एजेंसी: कैलिफोर्निया के लेगोलैंड थीम पार्क में एक अजीबो-गरीब नजारा देखने को मिला। यहां गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाने के लिए 1,273 लोग डायनासोर की पोशाक पहनकर पहुंचे थे। रिकार्ड का आयोजन करने वाली संस्था ने बताया कि पार्क ने डायनासोर की पोशाक पहने लोगों की सबसे बड़ी सभा का गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड अपने नाम किया है। इसके पहले यह रिकार्ड 2019 में अमेरिका के ही लासएंजिल्स में बनाया गया था। इस दौरान 252 लोग डायनासोर की पोशाक में इकट्ठा हुए थे। लेगोलैंड में यह आयोजन डायनासोर से जुड़े नए थीम पार्क डिनो वैली के उद्घाटन के उपलक्ष्य में किया गया था।

बच्चों में एकाग्रता की कमी दूर करेगी नई दवा

एफडीए ने बच्चों में एडीएचडी के इलाज के लिए केल्ब्री नाम की दवा को हरी झंडी दिखाई

वैश्विक स्तर पर दो से सात प्रतिशत बच्चे व किशोर इस रोग से प्रभावित

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

अमेरिका में अटेंशन डेफिसिट हाइपरऐक्टिविटी डिसआर्डर (एडीएचडी) वाले बच्चों के इलाज के लिए एक नई दवा को अनुमति मिल गई है। एडीएचडी से बच्चों में ध्यान की कमी, हाइपरऐक्टिविटी और इम्पल्सिविटी जैसी परेशानियां हो जाती हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने छह से 17 साल के बच्चों में एडीएचडी के इलाज के लिए केल्ब्री नाम की दवा को हरी झंडी दिखा दी है। यह एक कैप्सूल के रूप में आती है और इसे रोज खाना पड़ता है। दूसरी एडीएचडी दवाओं की तरह केल्ब्री एक स्टीमुलेंट या एक नियंत्रित पदार्थ नहीं है, जिसकी वजह से आसानी से इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। अभी तक जो दवाएं उपलब्ध थीं, जैसे रिटालिन, लगभग उन सभी में एम्फीटामाईन या मिथाइलफेनिडेट जैसे स्टीमुलेंट हैं। इसके साथ आत्महत्या के बारे में विचार आने की संभावना की चेतावनी दी जाती है। दवा को लेकर हुए अध्ययन में एक प्रतिशत से कम वालंटियरों में इस तरह के असर देखने को मिले।

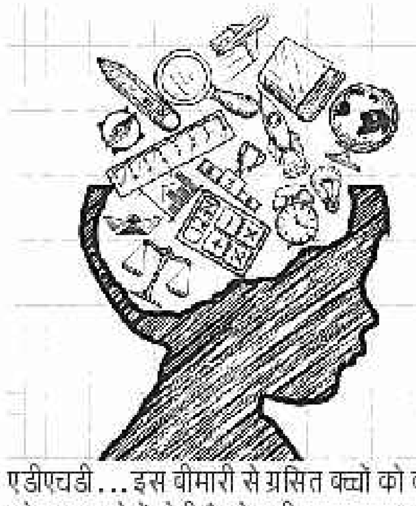

एडीएचडी... इस बीमारी से ग्रसित बच्चों को काम को पूरा करने में होती है परेशानी। फाइल

दुरुपयोग की संभावना कम

गुडमैन ने बताया कि दवाएं लेने वाले एडीएचडी के अधिकांश रोगियों को लम्बा असर करने वाले स्टीमुलेंट दिए जाते हैं जिनका दुरुपयोग करके उनसे नशा करना आसान नहीं होता।

50 प्रतिशत तक देखी गई कमी

जिसमें छह से 11 उम्र तक के 477 बच्चों ने यह नई दवा छह हफ्तों तक ली. इन बच्चों में उस समूह के मुकाबले ध्यान कम देने और हाइपरएक्टिविटी के लक्षणों में 50 प्रतिशत तक की कमी देखी गई, जिसमें दूसरे बच्चों को सिर्फ प्लेसिबो (पानी या ऐसा तरह जिसमें दवाई नहीं हो) दिया गया था।

अमेरिका में करीब 60 लाख बच्चे और किशोर इस रोग से प्रभावित हैं। इनमें से कई लोगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें ध्यान देने में परेशानी, काम पूरे करने में परेशानी, बेचैनी और आवेग शामिल हैं।

जानकारों का मानना है कि संभव है कि यह दवा उन लोगों को पसंद आएगी जो अपने बच्चों को स्टीमुलेंट नहीं देना चाहते हों। जान्स अपकिंस स्कूल आफ मेडिसिन में मनोविज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डेविड गुडमैन कहते हैं कि यह दवा उन बच्चों के लिए भी एक विकल्प हो सकती है जो पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या से जूझ रहे हों, जो स्टीमुलेंटों के दुष्प्रभावों से दूर रहना चाह रहे हों या जिन्हें अतिरिक्त रूप से थेरेपी की आवश्यकता हो।

ये है लक्षण

- कुछ अध्ययनों में विलोक्साजीन के नाम से भी जाने जाने वाली इस दवा ने लक्षणों को एक सप्ताह के अंदर कम कर दिया. इसके आम दुष्प्रभावों में नींद आना, आलस, भूख में कमी और सिर में दर्द शामिल हैं।
- एडीएचडी के शिकार वयस्कों में इस दवा के परीक्षणों का आखिरी चरण में है। इस रोग से पीड़ित वयस्कों की संख्या कम है। अभी बहुत कम वयस्क एडीएचडी की दवा लेते हैं।

117 की हुई विश्व की सबसे उम्रदराज जीवित शख्स

मारिया ब्रान्यास विश्व की सर्वाधिक उम्रदराज जीवित शख्स हैं। वह 117 वर्ष की हो गई हैं। स्पेन के कैटालोनिया में उन्होंने अपनी 117वीं जन्मतिथि मनाई। 118 वर्षीया फ्रांसीसी महिला लूसिल रैंडन की मृत्यु के बाद जनवरी 2023 में मारिया विश्व की सबसे अधिक उम्र की जीवित शख्स बन गई थीं। सुनने में कठिनाई एवं चलने-फिरने में समस्या के अतिरिक्त इन्हें कोई शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्या नहीं है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में चार मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था। जब वह आठ वर्ष की थीं, परिवार के साथ स्पेन आ गई थीं। रायटर

आठ साल के लड़के को पैपिलरी थायराइड कैंसर

मिड डे, मुंबई

यमन का 8 वर्षीय लड़का संभवतः भारत में दूसरा सबसे कम उम्र का लड़का है, जिसका पैपिलरी थायराइड कैंसर का इलाज किया गया है, यह एक ऐसी स्थिति है जो ज्यादातर वयस्कों को प्रभावित करती है। पिछले साल ही बेंगलुरु में एक 7 साल की बच्ची को इस स्थिति का पता चला था। मुंबई के जसलोक अस्पताल में इस मामले से जुड़े बाल रोग विशेषज्ञ डा. फजल नबी ने कहा कि 20 साल बाद उन्हें बच्चों में इस प्रकार के कैंसर का मामला पता चला, आखिरी मामला 14 साल की लड़की में था।

तीन महीने से लड़के के बायीं तरफ सूजन थीः बच्चा गर्दन के सामने और बायीं तरफ 4x4 सेमी की सूजन के साथ अस्पताल आया था, जो तीन महीने से मौजूद थी। मुंबई आने से पहले परिवार ने यमन में एक स्वास्थ्य सुविधा में उसकी जांच कराई, जहां उसे थायराइड कैंसर का पता चला। जसलोक में, परिवार को किसी भी संबंधित चिकित्सा समस्या या कैंसर के आगे फैलने से बचने के लिए फिर से कई निदानों से गुजरना पड़ा, जिसके बाद अस्पताल ने बच्चे का आपरेशन करने का फैसला किया।

अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ्य : डा. नबी ने कहा कि कैंसर को बाहर निकालते समय हमें किसी भी अन्य ग्रंथि को नुकसान न पहुंचाने के लिए बहुत सावधान रहना था। विकिरण जोखिम, अधिक मात्रा में रंगों के साथ भोजन का सेवन और यहां तक कि आनुवंशिकी जैसे संभावित कारक भी हो सकते हैं। हम अभी भी इसका सटीक कारण नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इलाज 8 जनवरी से 15 जनवरी तक चला, उसके बाद एक और सप्ताह तक बच्चे को रखा गया। डा. नबी ने कहा, "परिवार लगभग एक महीने से उसकी देखभाल कर रहा है और उसके शेष उपचार को पूरा करने के लिए फिर से वापस आएगा, लेकिन अब हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि बच्चा किसी भी खतरे से बाहर है।

गर्दन में नाजुक संरचनाओं को संभालने में चुनौतियां : सर्जिकल आन्कोलाजी के निदेशक डा. मेहुल भंसाली ने कहा कि इस विशेष मामले में एक बच्चे की गर्दन में नाजुक संरचनाओं को संभालने में चुनौतियां थीं, हालांकि इसमें शामिल सभी सर्जन अत्यधिक प्रशिक्षित और अनुभवी थे। डा. नबी ने कहा यहां प्रक्रिया के लिए सहमति देने से पहले परिवार ने शहर के कई डाक्टरों से परामर्श लिया।

थायरायड ग्रंथि को करता है प्रभावित : पैपिलरी थायराइड कैंसर थायरायड ग्रंथि को प्रभावित करता है, जो गर्दन में स्थित होता है। हालांकि इसका अक्सर वयस्कों में निदान किया जाता है, लेकिन बच्चों में यह कम देखा जाता है और वह भी बहुत छोटे बच्चों के बजाय ज्यादातर किशोरों और बड़े बच्चों में। चिकित्सा साहित्य से पता चलता है कि यह सभी बाल चिकित्सा संबंधी घातक बीमारियों का 1.4% है।

'महिलाओं द्वारा संचालित खेती व परिवार पर जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा'

रोम, एपी: संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को चेतावनी दी कि गरीब देशों में खेत और ग्रामीण घर चलाने वाली महिलाएं जलवायु परिवर्तन से अधिक पीड़ित होती हैं और जब वे संकट के समय आय के अन्य स्रोतों को अपनाने की कोशिश करती हैं तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन 'द अनजस्ट क्लाइमेट' की नई रिपोर्ट में पाया गया कि पुरुष प्रधान परिवारों की तुलना में महिला प्रधान ग्रामीण परिवारों को गर्मी के दौरान औसतन 8 प्रतिशत और बाढ़ के दौरान 3 प्रतिशत अधिक आय का नुकसान होता है। रोम स्थित इस संगठन ने दुनियाभर के 24 गरीब व मध्यम आय वाले देशों में 100,000 ग्रामीण परिवारों का सर्वेक्षण करके आंकड़े पेश किए। उस डाटा को 70 वर्षों के वर्षा और तापमान डाटा के साथ एकीकृत किया गया है।

मलेरिया रोकने में मददगार पाया गया कीटनाशक पेंट

अनुसंधान

एक नए शोध में घरों पर लगाया जाने वाला पेंट येलो फीवर के मच्छरों को मारने में प्रभावी पाया गया है। यह 'वेस्टा' पेंट कोटिंग के बाद लंबे समय तक थोड़ी मात्रा में कीटनाशक छोड़ता है। शोधकर्ताओं ने इस पेंट को घरेलू स्तर पर मलेरिया को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक आशाजनक रणनीति के रूप में दर्शाया है। यह डेंगू, चिकनगुनिया, जीका बुखार सहित इन मच्छरों द्वारा फैलने वाले किसी भी वेक्टर जनित रोग के विरुद्ध कारगर हो सकता है।

शोध का नेतृत्व करने वाले अफ्रीका के जीन पियागेट यूनिवर्सिटी, केप वर्डे के शोधकर्ताओं ने कहा कि पेंट टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल थे और उन इलाकों में लगभग सभी आबादी के बीच इसे स्वीकृति मिली इसका जहां परीक्षण किया गया। फ्रंटियर्स इन टापिकल डिजीज जर्नल में प्रकाशित अध्ययन की मुख्य लेखिका लारा फेरेरो गोमेज ने कहा कि यहां हमने देखा कि 'वेस्टा' कीटनाशक पेंट पश्चिमी अफ्रीकी देश केप वर्डे के प्रिया शहर में येलो फीवर के मच्छर एडीज एजिप्टी को कम से कम एक साल तक मारने में प्रभावी है। अध्ययन के लिए प्रशिक्षित स्वयंसेवकों ने 228 घरों को पेंट किया, जो विशेष रूप से मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के प्रति संवेदनशील थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि वेस्टा फार्मूलेशन पेंटिंग के छठे और 12वें महीने में डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुरूप रहा, जबकि अन्य दो फार्मूलेशन छठे महीने में सीमा से नीचे गिर गए। शोधकर्ताओं ने कहा निवासियों के स्वास्थ्य पर पेंट का कोई गंभीर प्रभाव नहीं देखा गया। उनमें से 10 प्रतिशत ने आंख या नाक में हल्की जलन और चार प्रतिशत ने सिरदर्द की शिकायत की। (प्रेट्र)

स्क्रीन शाट

कानून से बहुत पहले से ही रहा है निधि का जुड़ाव

निधि बिष्ट। (इंस्टाग्राम) @ekthapatiger

अगर किसी विषय के बारे में कलाकार को अच्छी जानकारी होती है, तो उससे संबंधित भूमिकाएं निभाना उनके लिए काफी सहज होता है। नेटफ्लिक्स पर हालिया प्रदर्शित वेब सीरीज मामला लीगल में अभिनेत्री निधि वकील सुजाता नेगी की भूमिका में नजर आई। दिलचस्प बात यह है कि अभिनेत्री बनने से पहले वह दो साल दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर चुकी हैं। ऐसे में इस शो की दुनिया उनके लिए जानी पहचानी रही। इस बारे में निधि बताती हैं, 'मैंने पहले ला की पढ़ाई की, फिर दिल्ली हाईकोर्ट में दो साल प्रैक्टिस की थी। हालांकि ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता था। कोर्ट और कानून को लेकर बहुत सी चीजें अभी भी ऐसी हैं, जो मुझे आज भी नहीं पता है। शो की स्क्रिप्ट इतनी रिसर्च के साथ तैयार की गई थी कि मेरे लिए उसमें कुछ सुधार करने की गुंजाइश नहीं थी। जब मैं कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी, तो मुझे कोर्ट के बड़े चक्कर लगाने पड़े थे। उस समय वही तो मेरी नौकरी थी। मेरे पिता दिल्ली पुलिस में नौकरी करते थे, अब रिटायर हो चुके हैं। इसलिए कानून को लेकर दिमाग में यह बातें तो बचपन से थी कि क्या-क्या चीजें नहीं करनी है। यह बातें मैं कानून से बचने या कानून तोड़ने के संदर्भ में नहीं बोल रही हूं। मेरे घर में गैर कानूनी चीजों लिए सख्त मनाई थी। यहां तक बिना हेलमेट स्कूटी चलाने की भी अनुमति नहीं थी।'

रितिक की तरह नाचने के लिए कहते थे कास्टिंग डायरेक्टर : अभिषेक बनर्जी

दूसरों का दर्द तब ज्यादा समझ में आता है, जब व्यक्ति खुद उस दौर से गुजरा हो। स्त्री फिल्म में जना के पात्र से प्रसिद्ध हुए अभिनेता अभिषेक बनर्जी सफल कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। हालांकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जो शुरुआत वह कैमरे के सामने करना चाहते थे। वह कैमरे के पीछे शुरू करेंगे। अभिषेक कहते हैं कि जब मैं आडिशन देने जाता था, तो कोई कह देता था नाट फिट, तो कोई बड़े ही बुरी तरह से बात करता था। जब ऐसा होता था, तो बतौर आर्टिस्ट बहुत चोट पहुंचती थी। कम ही लोग थे, जो नए लोगों को काम देना चाहते थे। आडिशन रूम में जो कास्टिंग डायरेक्टर होते थे, वह कहते थे कि शाह रुख खान की तरह डायलाग्स बोलकर दिखाओ। रितिक रोशन की तरह नाच के दिखाओ। मुझे लगा मेरे एक्टिंग के टीचर्स ने ये सब तो नहीं सिखाया। फिर धीरे-धीरे समझ आया कि उनका कास्ट करने का तरीका गलत था। मुझे लगा कि कास्टिंग की दुनिया का हिस्सा बनना चाहिए। मैं कैमरे पीछे रहकर कलाकारों की मदद कर सकता हूं। मुझे लगा मैं अभिनय भूल जाऊंगा, क्योंकि कास्टिंग से पैसे कमा रहा था। अभिनय के लिए वक्त नहीं बचा था। एक दिन निर्देशक अमर कौशिक, जो मेरे दोस्त रहे हैं, उन्होंने कहा स्त्री फिल्म बना रहा हूं। जना की भूमिका के लिए आडिशन दे दो। आडिशन पसंद आया और मैं एक्टर बन गया।

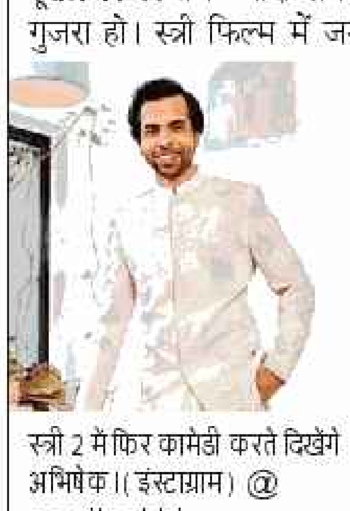

स्त्री 2 में फिर कामेडी करते दिखेंगे अभिषेक। (इंस्टाग्राम) @nowitsabhi

जब दीवारों को तौलिए से साफ किया था कुणाल खेमू ने

दोस्ती की बात होते ही याद आ जाता है फिल्म दिल चाहता है का वो गाना, जिसमें तीन दोस्त गोवा घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन हर गोवा की यात्रा सुखद हो ऐसा जरूरी नहीं। सोचिए क्या हो जब गोवा के बड़े होटल के स्वीट वाले रूम में दीवारों को तौलिए से साफ करना पड़े। अभिनेता कुणाल खेमू के साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ है। कुणाल बताते हैं कि मैंने दो फिल्में कर ली थीं। उसके बाद पैसे आ गए थे, तो मैं अपने बचपन के दोस्तों के साथ गोवा गया था। एक अच्छे से होटल में स्वीट (बड़ा सा कमरा) बुक कराया था। मेरे एक दोस्त ने बाल गीले किए, उसके पास उन्हें सेट करने के लिए जेल नहीं था। तो वह कहीं से नारियल का तेल ले आया था। हम सूटबूट पहनकर तैयार खड़े थे। वह रूम के बीचोबीच खड़े होकर उस बोतल से तेल निकालने की कोशिश कर रहा था। वह बोतल उसके हाथ में फट गई। सारा तेल कमरे की दीवारों और हमारे सूट पर आ गिरा। हमने तुरंत कपड़े उतारे। डिटर्जेंट खरीदा और होटल से तौलिए मंगाए। बाथरूम में नहाने वाले टब में झाग बनाया। तौलिए को उसमें डूबाकर दीवार तौलिए से साफ करने लगे। थोड़ी देर बाद दीवारों पर पपड़ी बनने लगी। हमें काफी पैसे भरने पड़े और बहुत माफी मांगनी पड़ी थी। तीन दोस्तों के गोवा जाने पर बनी कामेडी फिल्म मडगांव एक्सप्रेस के जरिए कुणाल ने निर्देशन में कदम रखा है।

मडगांव एक्सप्रेस से निर्देशक बन गए हैं कुणाल। (इंस्टाग्राम) @kunalkemmu

तो सलमान की जगह शाहिद बनेंगे प्रेम

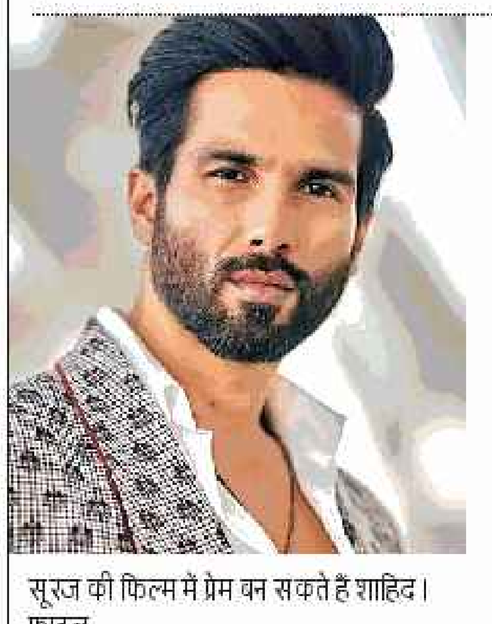

सूरज की फिल्म में प्रेम बन सकते हैं शाहिद। फाइल

सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म प्रेम की शादी से सलमान खान के अलग होने की खबरें आई थीं। बताया जाता है कि स्क्रिप्ट के कई पहलुओं पर सहमति नहीं बन पाने के बाद दोनों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से इस प्रोजेक्ट से अलग होने का फैसला किया। इससे पहले दोनों की जोड़ी ने मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन!, हम साथ साथ हैं और प्रेम रतन धन पायो जैसी सफल फिल्में दी हैं। सलमान के अलग होने से फिल्म बंद नहीं हुई है। खबर है कि सूरज ने इस फिल्म के लिए शाहिद कपूर से संपर्क किया है। वह अब स्क्रिप्ट में बदलाव कर रहे हैं और मुख्य किरदार की उम्र कम कर दी गई है। शाहिद इससे पहले सूरज के साथ फिल्म विवाह (2006) कर चुके हैं। दोनों कई बार मिल चुके हैं। अब जो उनकी बातचीत हो रही है, वो 18 साल बाद उनके पुनर्मिलन की संभावना की ओर इशारा करती है। हालांकि शाहिद ने अभी तक अपनी अंतिम मंजूरी नहीं दी है। अगर शाहिद इस महीने के अंत तक फिल्म साइन कर लेंगे, तो शूटिंग इस साल आरंभ हो सकती है। इसके अलावा शाहिद दो ऐतिहासिक पात्रों अश्वत्थामा और छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं।

फिल्म वार 2 में अभिनेता जूनियर एनटीआर भारतीय एजेंट की भूमिका में नजर आएंगे। बालीवुड गलियारों की खबरों के अनुसार वार 2 में ही नहीं बल्कि यशराज फिल्म्स के स्पाइ यूनिवर्स की दूसरी फिल्मों में भी जूनियर एनटीआर दिख सकते हैं।

भारतीय एजेंट बनेंगे जूनियर एनटीआर

वार 2 में रितिक रोशन के साथ होंगे जूनियर एनटीआर • मिडडे आर्काइव

यह पहले ही तय हो चुका है कि यशराज फिल्म्स की आगामी फिल्म वार 2 में अभिनेता रितिक रोशन और जूनियर एनटीआर होंगे। इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म वार में रितिक के सामने टाइगर श्राफ थे। टाइगर निगेटिव रोल में थे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि जूनियर एनटीआर भी वार 2 में विलेन की भूमिका में दिखेंगे। अब बालीवुड गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक जूनियर एनटीआर फिल्म में भारतीय एजेंट की भूमिका में होंगे। इसका मतलब है कि यशराज फिल्म्स के स्पाइ यूनिवर्स में सलमान खान, रितिक और शाह रुख खान के बाद अब जूनियर एनटीआर की भी एंट्री भारतीय एजेंट के तौर पर हो गई है। फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक अयान मुखर्जी फिल्म में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। इस फिल्म के हर किरदार में उन्होंने कई शेड्स दिखाने का प्रयास किया है। आदित्य ने जूनियर एनटीआर के रोल के लिए वार 2 की दुनिया से आगे जाकर स्पाई यूनिवर्स के लिए शानदार योजनाएं बना रखी हैं। वह भारतीय सिनेमा का पैन इंडिया यूनिवर्स बनाना चाह रहे हैं। ऐसे में जूनियर एनटीआर का किरदार वार 2 तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। किरदार का स्पिन-आफ (उसके अतीत में जाकर कहानी कहना) और इस स्पाई यूनिवर्स की दूसरी फिल्मों में भी उनका कैमियो होगा।

...इसलिए राक आन 2 से अलग हुए थे अभिषेक

कुछ दर्द हमेशा के लिए दिल के किसी कोने में छुपे रहते हैं। जब उनका जिक्र होता है, तो वह दर्द छलक भी जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ राक आन फिल्म के निर्देशक अभिषेक कपूर के साथ भी। 2008 में रिलीज हुई फिल्म राक आन के लिए अभिषेक को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन 2016 में रिलीज हुई इसकी सीक्वल फिल्म राक आन 2 से उन्हें अलग कर दिया गया। इसका कारण बताते हुए अभिषेक कहते हैं, 'मैंने उस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी। केवल ढांचा तैयार किया था। कहानी को कैसे बढ़ाना है इसे लेकर मेरे और फरहान अख्तर के बीच कुछ असहमति हो रही थी। फिर उन्होंने किसी और निर्देशक के साथ आगे बढ़ने की सोची। कई बार दिल दुखता है, लेकिन यही अनुभव होते हैं, जो जीवन में आपको समृद्ध बनाते हैं। मैंने राक आन 2 नहीं देखी। उस वक्त मैं दुखी था।' इन दिनों अभिषेक अपनी एक्शन एडवेंचर फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसमें रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी और अजय देवगन के भतीजे अमन देवगन होंगे। क्या अभिषेक दो नए चेहरों को लांच करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा, 'नहीं, मैं किसी को लांच करने के लिए फिल्म नहीं बनाता। मैं उन कहानियों को कहने के लिए फिल्म बनाता हूं, जो कई वर्षों से मेरे साथ होती हैं। राशा और अमन दोनों मेहनती हैं। युवा कलाकारों की समझ अलग होती है। फिल्म में अजय देवगन भी एक अहम रोल निभा रहे हैं।'

एक्शन एडवेंचर फिल्म पर काम कर रहे हैं अभिषेक • @gattukapoor (इंस्टाग्राम)

रामलली पर फिल्म बनाएंगे ओमंग

फिर नायिका प्रधान फिल्म बनाएंगे ओमंग • @omungkumar (इंस्टाग्राम)

हिंदी सिनेमा लगातार महिलाओं की साहसिक कहानी को सामने ला रहा है। अब निर्देशक ओमंग कुमार उत्तर प्रदेश में चित्रकूट सीमा के पास पाठा की अशिक्षित महिला रामलली पर फिल्म बनाने की तैयारी में है। रामलली न सिर्फ खूंखार डकैत के खिलाफ खड़ी हुई बल्कि अपने गांव की महिलाओं को हिंसा के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित भी किया। वह डकैत ददुआ के खिलाफ खड़ी हुई थी, जिसके आतंक का शासन उत्तर प्रदेश के बीहड़ों में था। ओमंग इससे पहले फिल्म मैरी काम, सरबजीत और पीएम नरेन्द्र मोदी का निर्देशन कर चुके हैं। साल 2001 में, ददुआ ने एक बैंक मैनेजर के बेटे का अपहरण कर लिया था। लड़का भागने में सफल रहा और उसने रामलली के घर में शरण ली थी। जब ददुआ और उसके डाकू रामलली के दरवाजे पर आए, तो उसने लड़के को छोड़ने से इन्कार कर दिया। उसकी बहादुरी का यह किस्सा काफी चर्चित है।

अब राजनीति का चस्का लग गया है मेरे पात्र को

जैसे-जैसे वेब सीरीज के सीजन आगे बढ़ते हैं, उसके पात्रों में भी बदलाव होते हैं। महारानी 3 वेब सीरीज में भी कुछ ऐसा ही होगा अभिनेत्री अनुजा साठे के पात्र कीर्ति सिंह के साथ। दूसरे सीजन में कीर्ति का पात्र राजनीति की तरफ आकर्षित नहीं था, लेकिन इस बार राजनीति के रंग उसे पसंद आ गए हैं। अनुजा कहती हैं, 'तीसरे सीजन में राजनीति ने मेरे पात्र कीर्ति सिंह अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। हालांकि इस भूमिका में जाना मेरे लिए आसान नहीं था। दूसरे सीजन के बाद तीन-चार प्रोजेक्ट एक साथ शूट कर रही थी। ऐसे में दोबारा उस भूमिका में जाने के लिए उसको पालिश करना पड़ा। डेढ़ साल का अंतराल था। हम सभी ने वर्कशाप, रीडिंग्स की। यह प्रक्रिया जरूरी होती है। तीसरे सीजन में जो नहीं बदला था, वह थी साड़ियां। मुझे वैसे भी साड़ियां बेहद पसंद हैं।' महारानी में हुमा कुरैशी शीर्षक भूमिका में हैं। ऐसे में सेकेंड लीड कहलाने से अनुजा को बुरा नहीं लगता है? इस पर वह कहती हैं, 'नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब हम सीरीज देखते हैं, तो उसमें बहुत से किरदार होते हैं। हर पात्र जरूरी होता है। हर किसी का अपना स्क्रीन स्पेस होता है।'

महारानी 3 में राजनेत्री की भूमिका में हैं अनुजा • टीम अनुजा

****